RNI NO. DELHIN/2012/48369
वर्ष 8 अंक 25
नई दिल्ली, बुधवार, 27 नवंबर, 2019
पृष्ठ 16 मूल्य ₹ 3
नगर संस्करण

नई दिल्ली, लखनऊ, रायपुर और फरीदाबाद से प्रकाशित

पायनियर

इलियाना को थी अपनी बॉडी से प्रॉब्लम
विविध-16

www.dailypioneer.com

महाराष्ट्र में सस्पेंस-ड्रामा खत्म, उद्धव होंगे मुख्यमंत्री

बुधवार को ही शक्ति परीक्षण के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरी चार दिन पुरानी फडणवीस सरकार, भाजपा की किरकिरी करा घर लौटे अजीत पवार

- महाराष्ट्र विकास अघाडी का नेता चुने जाने के बाद राज्यपाल से मिल उद्धव ने पेश किया सरकार बनाने का दावा
- एक दिसंबर को शिवाजी पार्क में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, राकांपा के जयंत पाटिल व कांग्रेस के बाला साहब थोराट होंगे उपमुख्यमंत्री

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई/नई दिल्ली

मुंबई में शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री पद के दावेदार घोषित किए जाने के बाद बैठक में उपस्थित नेताओं का अभिवादन करते उद्धव ठाकरे

शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे जबकि राकांपा के जयंत पाटिल और कांग्रेस के बाला साहब थोराट गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद संभालेंगे। प्रदेश के शीर्ष राजनीतिक पद पर पहुंचने वाले उद्धव ठाकरे परिवार के पहले सदस्य होंगे। बुधवार को ही सदन में शक्ति परीक्षण कराने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तेजी से बदलते घटनाक्रम के तहत मात्र चार दिन पुरानी फडणवीस सरकार गिर गई। इधर मुख्यमंत्री फडणवीस व उपमुख्यंत्री अजीत पवार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उधर, शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस गठबंधन (महाराष्ट्र विकास अघाडी) ने उद्धव ठाकरे को अपना नेता चुन लिया।

और वक्त जाया नहीं करते हुए उद्धव ने रात में ही सहयोगियों (प्रफुल्ल पटेल, भुजबल, अनिल देसाई, शिंदे आदि) के साथ राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और प्रदेश में नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। राज्यपाल ने बुधवार की सुबह 8 बजे विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है जिसमें प्रोटेम स्पीकर (अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष) बनाए गए भाजपा विधायक कालीदास कोलम्बकर सदन के 288 नव निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे जिसके (शेष पेज 10)

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसलों पर सुनाया आदेश

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

- कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तक में उत्पन्न राजनीतिक संकटों का दिया हवाला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा में बुधवार की शाम तक बहुमत सिद्ध करनेका निर्देश देने संबंधी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक से लेकर झारखंड विधानसभा तक में उत्पन्न ऐसे ही राजनीतिक संकटों में अपने फैसलों का हवाला दिया। इन राज्यों में भी राजनीतिक संकट पैदा होने पर सर्वोच्च अदालत ने सदन में ही बहुमत सिद्ध करने का आदेश दिया था।

न्यायमूर्ति एनवी रमण की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने अपने आदेश में सबसे पहले कर्नाटक विधानसभा के 17 सदस्यों को अयोग्य ठहराने के अध्यक्ष के निर्णय को सही ठहराने संबंधी अपने 13 नवंबर के फैसले का जिक्र किया। इस फैसले में न्यायालय ने संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों की संवैधानिक नैतिकता बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया था।

शीर्ष अदालत ने इसी तरह उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के मामले में अपने 2016 के निर्णय का हवाला दिया। इस मामले में (शेष पेज 10)

पर्दे के पीछे : पवार ने अजीत को कैसे जीता

पायनियर समाचार सेवा। मुंबई

- परिवार के सदस्यों और एनसीपी नेताओ की कोशिशें रंग लाईं

पल-पल खबरों की सुर्खियां बदल रही महाराष्ट्र की सियासत में अजीत पवार एक अहम किरदार बनकर उभरे हैं। तीन पहले ही तेजी से बदले घटनाक्रम में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनवाने वाले एनसीपी नेता अजीत पवार फिर पलटे और सीएम फडणवीस की अपना इस्तीफा सौंप कर उनकी सरकार की विदाई की पटकथा लिख दी। बहरहाल, बगावती तेवर अपनाने वाले अजीत की घर वापसी इतनी आसान भी नहीं थी। एनसीपी उनको मनाने की कोशिश लगातार जारी रखे थी। महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में अर्जुन की भूमिका निभा रहे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अपने भतीजे को मनाने में कामयाब रहे।

इस पूरे घटनाक्रम में पारिवारिक दबाव को अहम माना जा रहा है। दरअसल अजीत पवार ने जब 23 नवंबर की सुबह शपथ ली तो उसके बाद से ही पवार परिवार के सदस्य अजीत से बातचीत कर रहे थे। उन्हें परिवार में बिखराव से बचने और पार्टी (शेष पेज 10)

मौसम

अधिकतम	27.9°C (+2)
न्यूनतम	16.2°C (+5)

बाजार

सेंसेक्स	40,821	↓	67
निफ्टी	12,037	↓	36
सोना	38,547	↓	68 /10g
चांदी	45,161	↓	39 /kg

क्विक न्यूज

ईडी ने वटाली की 6.20 करोड़ की संपत्तियां कब्जे में ली

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आतंकवाद वित्त पोषण मामले के सिलसिले में कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह वटाली की 6.20 करोड़ रुपए की संपत्तियो को अपने कब्जे मे लिया है। संघीय एजेंसी ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए एक बयान मे कहा, ये संपत्तियां भूमि के टुकड़ो के रूप मे है जो केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले के सोइ्रीठ गांव मे स्थित है। बयान मे कहा गया है कि इन संपत्तियो का कुल मूल्य 6.20 करोड़ रुपए है और ए संपत्तियां वटाली और उनके परिवार के नाम पर है। वटाली के खिलाफ ईडी का मामला आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और अन्य के खिलाफ आतंकवाद वित्त पोषण तथा धनशोधन से संबंधित है।

रिश्वतखोरी की घटनाओं में 10 फीसदी की कमीः सर्वे

नई दिल्ली। एक सर्वे के अनुसार देश मे पिछले वर्ष से रिश्वतखोरी की घटनाओ मे 10 फीसदी की कमी आई है। दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, गोवा और ओडिशा मे लोगो ने भ्रष्टाचार के कम मामले दर्ज कराए जबकि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, झारखंड और पंजाब मे भ्रष्टाचार की घटनाएं अधिक थी। इंडिया करप्शन सर्वे 2019 मे 20 राज्यो के 248 जिलो मे 1,90,000 लोगो से जवाब प्राप्त हुए। यह सर्वे ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) ने किया है। यह एक गैर राजनीतिक, स्वतंत्र और गैर सरकारी भ्रष्टाचार रोधी संगठन है।

गो एयर के विमान की आपात स्थिति में लैंडिंग

मुंबई। गोएयर के लखनऊ जा रहे एक विमान को उड़ान भरने के तत्काल बाद ही इंजन से जुड़ी तकनीकी समस्या के चलते आपात स्थिति मे वापस उतारना पड़ा। मुंबई हवाईअड्डे के अधिकारियो ने मंगलवार शाम को यह जानकारी दी। एयरबस ए-320 नियो विमान मे यह गड़बड़ी सामने आई है।

अनधिकृत कॉलोनियों को वैध बनाने का बिल पेश

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक देने के लिए लाया गया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अप्राधिकृत कालोनी निवासी संपत्ति अधिकार मान्यता) विधेयक 2019 मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। आवास एवं शहरी विकास मंत्री मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा निचले सदन में पेश इस विधेयक में इन अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें पॉवर ऑफ अटॉर्नी, विक्रय करार, वसीयत, कब्जा पत्र और अन्य ऐसे दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक देने की बात कही गई है जो ऐसी संपत्तियों के लिए खरीद का प्रमाण हैं। इन कॉलोनियों के विकास, वहां मौजूद अवसंरचना और जन सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रावधान भी विधेयक में किया गया है। इस विधेयक के कानून का रूप लेने के बाद 40 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे।

पाकिस्तान सीमा पर इजराइल में बनी स्पाइक मिसाइलें तैनात

पायनियर समाचार सेवा। जम्मू

भारतीय सेना ने इजराइल में बनी टैंक रोधी मिसाइल (एटीजीएमएस) स्पाइक को जम्मू-कश्मीर में उत्तरी कमान के युद्ध क्षेत्र में नियंत्रण रेखा पर तैनात किया है। इससे पाकिस्तान के साथ लगी देश की सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। स्पाइक एटीजीएमएस मिसाइलों को दागो और भूल जाओ मिसाइल के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरी तरह पोर्टेबल हैं और शक्तिशाली इतनी हैं कि टैंक को नष्ट कर सकती हैं और चार किलोमीटर के दायरे में बंकर को तबाह कर सकती हैं।

सेना के सूत्रों ने बताया कि इन टैंक रोधी गाइडेड मिसाइलों और इसके लांचर को उत्तरी युद्ध क्षेत्र में नियंत्रण रेखा के साथ 16-17 अक्टूबर से शामिल किया गया और इस समय इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इजराइल ने सेना को आपातकालीन खरीद तंत्र के तहत 280 करोड़ रुपए के सौदे में कुल 210 मिसाइलों और 12 लॉन्चरों की आपूर्ति की थी।

यह बहुप्रतीक्षित सौदा भारतीय वायुसेना के बालाकोट में आतंकी शिविरों पर हवाई हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पर सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के बाद हुआ था। दागो और भूल जाओ एटीजीएमएस की मारक क्षमता चार किलोमीटर तक है और इनका इस्तेमाल नियंत्रण रेखा के करीब बंकरों, शेल्टरों, घुसपैठ के अड्डों और आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों को नष्ट करने के लिए किया जा सकता है।

मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी ढेर

पायनियर समाचार सेवा। श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया, पुलवामा मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए और वे दोनों हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि ए दोनों कई आतंकी हमलों में संलिप्त थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम दक्षिण कश्मीरी जिले के शदिमार्ग में तैनात सुरक्षाकर्मियों पर आतंकवादियों द्वारा गोलियां चलाने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्वाई में सोमवार देर रात एक आतंकवादी मारा गया और दूसरा मंगलवार सुबह मारा गया। अधिकारी ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों की पहचान इरफान अहमद शेख और इरफान अहमद राठेर के रूप में की गई है। मुठभेड़ स्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है।

चुनौतियों का समाधान है संविधानः मोदी

- संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को किया संबोधित

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

नई दिल्ली में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

भारतीय संविधान को वैश्विक लोकतंत्र की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि करार देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि संविधान हमें अधिकारों के प्रति सजग एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है और ऐसे में हमें नागरिक के तौर पर अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान हमारे लिए सबसे पवित्र ग्रंथ है। ऐसा ग्रंथ जिसमें हमारे जीवन की, समाज की परंपराओं, हमारे आचार-विचार का समावेश है और अनेक चुनौतियों का समाधान भी है।

संविधान को अंगीकार करने 70 वर्ष पूरा होने पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वैचारिक मतभेदों से ऊपर उठकर, संविधान-सम्मत प्रक्रियाओं का पालन करने को संवैधानिक नैतिकता का सार-तत्व बताया और कहा कि देश में हर प्रकार की परिस्थिति का सामना करने के लिए संविधान सम्मत रास्ते उपलब्ध हैं और इसलिए संविधान की मर्यादा, गरिमा और नैतिकता के अनुरूप काम करें। उप राष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देशवासियों से संविधान की मान्यताओं और मर्यादाओं के संरक्षण और संवर्धन के प्रति पुनः संकल्पबद्ध होने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यदि हम प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों को निभाए तथा राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के प्रति संकल्पबद्ध रहें तो देश का तेजी से विकास हो सकता है और यह अधिक परिपक्व लोकतंत्र बन सकता है।

वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय संविधान के दो मंत्रों ने भारतीयों के लिए गरिमा और भारत की एकता को साकार किया है। उन्होंने भारतीय नागरिकों का आह्वान किया, हम सब देश के नव नागरिक और नेक नागरिक बने। प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे संविधान की (शेष पेज 10)

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को चुनौती नहीं देगा सुन्नी वक्फ बोर्ड

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में प्रमुख मुस्लिम पक्षकार रहा उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इस मसले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल में दिए गए फैसले को चुनौती नहीं देगा। बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में आमराय से इस आशय का निर्णय किया गया है। बोर्ड अयोध्या में कहीं और मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन लेने या नहीं लेने पर अभी कोई निर्णय नहीं कर सका है।

बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने बैठक के बाद बताया कि बैठक में बोर्ड के आठ में से सात सदस्यों ने हिस्सा लिया। उनमें से अब्दुल रज्जाक को छोड़कर बाकी छह सदस्यों ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले को चुनौती न देने के प्रस्ताव का समर्थन किया। इस तरह अदालत के निर्णय को चुनौती न देने के फारूकी के पहले से ही लिए जा चुके फैसले पर आम सहमति की मुहर भी लग गई। फारूकी ने गत नौ नवम्बर को अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद ही कहा था कि बोर्ड उस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करेगा। हालांकि उन्होंने बाद में कहा था कि अगर किसी सदस्य को इस पर आपत्ति है तो वह आज की बैठक में अपनी बात रख सकता है। उन्होंने बताया कि बैठक में एक सदस्य इमरान माबूद खां किन्हीं कारणों से शामिल नहीं हो सके। फारूकी ने बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सरकार को दिए गए आदेश के मुताबिक अयोध्या में कहीं और मस्जिद बनाने के लिए पांच एकड़ जमीन लेने के मामले पर बैठक में कोई निर्णय नहीं हो सका। इस बारे में फैसला लेने के लिए बोर्ड के सदस्यों ने कुछ और समय मांगा। उन्होंने बताया कि बोर्ड के सदस्यों की राय थी कि वह जमीन लेने से जुड़े तमाम शरई पहलुओं पर विचार करना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें कुछ और समय दिया जाए।

बैठक में यह भी तय किया गया कि बोर्ड की तरफ से अयोध्या मामले में मीडिया में बात (शेष पेज 10)

भाजपा ने स्वागत किया

नई दिल्ली। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने अयोध्या विवाद पर आए उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करने के सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के निर्णय का मंगलवार को स्वागत किया और कहा कि यह राष्ट्र हित में और राष्ट्रीय सौहार्द के लिए है। हुसैन ने कहा कि अयोध्या मामले पर आए उच्चतम न्यायालय के फैसले को सभी ने स्वीकार किया है और आदेश आने के बाद देशवासियों ने शांति और सौहार्द को कायम रखा है। उन्होंने कहा, मैं अयोध्या पर आए फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर नहीं करने के सुन्नी वक्फ बोर्ड के फैसले का स्वागत करता हूं। यह राष्ट्र हित में है और देश में सौहार्द कायम रखने के लिए है। हुसैन ने कहा, हिंदू और मुस्लिम समुदाय ने अयोध्या फैसले के बाद जिस तरह की परिपक्वता और एक दूसरे के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है, वह दिखाता है कि भारतीयों के लिए भाईचारा सर्वोपरि है।

संयुक्त बैठक का कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने किया बहिष्कार

- संसद परिसर में किया प्रदर्शन, शिवसेना ने पहली बार दिया कांग्रेस को समर्थन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

संसद परिसर में प्रदर्शन करते कांग्रेस और विपक्षी दलों के सदस्य

कांग्रेस ने मंगलवार को संविधान की रक्षा का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि वह सत्ता के मद में चूर तानाशाही सरकार को संविधान को गिरवी नहीं रखने देगी। कांग्रेस की अगुवाई में कई विपक्षी दलों ने संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का बहिष्कार किया और संसद भवन परिसर में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के मुद्दे पर हुए इस विरोध प्रदर्शन में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कई अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल हुए। प्रदर्शन में कांग्रेस के अलावा द्रमुक, (शेष पेज 10)

मस्टर रोल में आग लगाने वाला पीसी कमांडर गिरफ्तार

होमगार्ड वेतन घोटाला

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

होमगार्ड वेतन घोटाला मामले में मस्टर रोल में लगी आग के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अवैतनिक प्लाटून कमांडर राजीव कुमार ने कमांडेंट ऑफिस में आग लगाई थी। जानकारी के अनुसार, 18 नवंबर की रात राजीव कुमार ने परिसर में खड़ी बाइक से पेट्रोल निकालकर मस्टर रोल में आग लगाई थी। मामले की जांच कर रही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर राजीव कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि राजीव कुमार ने घोटाले में अपने को बचाने के इरादे से आग लगाई थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।

पुलिस जांच में पता चला है कि आग लगाने वाला आरोपी कार्यालय का मुख्य द्वार कूदकर अंदर आया था। इसके बाद उसने बीएसए दफ्तर का ताला तोड़ा और भीतर रखी उसी अलमारी का ताला तोड़ा जिसमें मस्टर रोल व वेतन संबंधित दस्तावेज रखे हुए थे। इसके बाद आरोपी ने इन दस्तावेजों को कक्ष में ही रखे एक लोहे के बक्से का ताला तोड़कर उसमें रख दिया और आग लगा दी। बक्से में घोटाले से जुड़े कागजात पहले से मौजूद थे।

इस मामले में सूरजपुर पुलिस थाने में इंस्पेक्टर जितेंद्र सिंह ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में भी लिया था। मामले की जांच के लिए एसएसपी ने एक एसआइटी टीम का गठन किया था इसमें एसपी सिटी विनीत जायसवाल भी थे। पुलिस ने दावा किया कि आपराधिक कृत्य के तहत आग जानबूझकर लगाई गई है। इसमें किसी ऐसे व्यक्ति की भूमिका है जो कि घोटाले में शामिल है।

बता दें कि एसएसपी वैभव कृष्ण से जुलाई में एक होमगार्ड ने फर्जीवाड़ा कर होमगार्डों के ड्यूटी का फर्जी मस्टररोल तैयार कर भुगतान की शिकायत की थी।

राजीव कुमार ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसके द्वारा माह जुलाई में की गयी शिकायत की जांच में तत्कालीन जिला कमांडेंट होमगार्ड रामनारायण चौरसिया तथा पीसी होमगार्ड मोन्टू, शलैन्द्र, सत्यवीर आदि ने पूर्ण रूप से दोषी पाये जाने के उपरान्त भी विभाग से उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करने की अनुमति न मिलने पर उसको लगा कि विभाग द्वारा अधिकारियों का बचाव किया जा रहा है। राजीव के अनुसार वह इससे आहत था एवं उसे ऐसा लगा कि मात्र नीचे के कर्मचारियों के विरूद्ध ही कार्यवाही करके यह प्रकरण समाप्त कर दिया जायेगा तथा जिला कमाण्डेंट होमगार्ड व अन्य दोषी अधिकारियों का कुछ नहीं होगा। इसीलिए उसने मस्टररोल जला दिया जिससे कि नीचे के कर्मचारियों के विरूद्ध भी कार्यवाही न हो।

गिरफ्तार पीसी कमांडर के बारे में मीडिया को जानकारी देते एसएसपी वैभव कृष्ण।

संविधान के मूल कर्तव्यों के पालन की दिलाई शपथ

गाजियाबाद। संविधान दिवस पर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को शपथ दिलाई। इसके अलावा पुलिस लाइंस में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने पुलिसकर्मियों को और नगरायुक्त दिनेश चंद्र ने नगर निगम में अधिकारियों, कर्मियों को संविधान पालन कि शपथ दिलाई।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में डीएम ने भारत के संविधान की वर्षगांठ पर भारतीय संविधान की उत्कृष्टता के संबंध में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान दिवस की वर्षगांठ पर शपथ दिलाई कि हम सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत के संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करेंगे और संवैधानिक आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रीय प्रतीकों का आदर करेंगे।

पाक हैंडलरों को पैसा भेजने वाले दो गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

यूपी एटीएस ने पाकिस्तानी हैंडलरों के निर्देश पर काम करने वाले दो शातिर ठगों को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। दोनों फर्जी लॉटरी के धंधे में लिप्त थे और उसका पैसा पाकिस्तान भेज रहे थे। दोनों अभियुक्तों प्रकाश उर्फ जय प्रकाश रूहेला और धीरूद्दीन के विरुद्ध एटीएस के लखनऊ थाने में आईपीसी की धारा 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

● लॉटरी के जरिए करते थे लोगों से ठगी

गिरफ्तार आरोपी जय प्रकाश शामली जिले के थाना क्षेत्र स्थित रामशाला मोहल्ले का रहने वाला है। वर्तमान में वह गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन स्थित क्लासिक रेजीडेंसी में ब्लॉक एक के फ्लैट संख्या 602 में रह रहा था। दूसरा अभियुक्त धीरूद्दीन मूल रूप से मुजफ्फरनगर जिले के खरड़ गांव का रहने वाला है और वर्तमान में वह गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र स्थित पसोंडा में रह रहा था। दोनों को गाजियाबाद के मोहन नगर से गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के पास से 32 एटीएम कार्ड, पांच बैंकों की पासबुक और तीन बैंकों के चेकबुक बरामद किए गए हैं।

एटीएस यूनिट ने दोनों आरोपियों के 10 पाकिस्तानी हैंडलरों से संपर्क का खुलासा भी किया है। दोनों आरोपी पाकिस्तानी हैंडलरों के बताए खातों में रकम भेजते थे। आशंका जताई जा रही है कि इन पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किया जा रहा था। पिछले डेढ़ महीने में दोनों आरोपियों द्वारा 15 लाख रुपये पाकिस्तानी हैंडलरों को भेजने की पुष्टि हुई है। एटीएस के मुताबिक, टेरर फंडिंग का नेटवर्क बिहार, छत्तीसगढ़ और कोलकाता तक हो सकता है।

टेरर फंडिंग का शक

एटीएस के एडीजी डीके ठाकुर ने बताया कि दोनों मामू, नजीर और असगर समेत 10 पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे। शुरुआती जांच में 12 खातों की जानकारी मिली है, जिससे 15 लाख रुपए पाकिस्तान भेजने की पुष्टि हुई है। एटीएस को शक है कि फ्रॉड के जरिए आए पैसों का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में हो रहा है। एटीएस के अनुसार, पाकिस्तान में बैठे जालसाज भारत में लोगों को सोशल मीडिया के जरिए लाटरी की बड़ी रकम या गाड़ी निकलने का झांसा देते थे। जो लोग इनके झांसे में फंसते उन्हें अलग-अलग बैंक खातों में पैसा जमा कराते थे। ऐसे खातों की व्यवस्था जय प्रकाश व धीरुद्दीन करते थे। बाद में पैसों को पाकिस्तान के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता था।

तहसीलों को भी बनाया जाएगा मॉडल : डीएम

नोएडा। जिलाधिकारी बीएन सिंह ने कहा कि जिस प्रकार कलेक्ट्रेट को एक मॉडल बनाने के रूप में कार्य किया जा रहा है, उसी प्रकार अगले चरण में सभी तहसीलों को भी मॉडल बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इससे राजस्व कार्य में और अधिक गतिशीलता आएगी।

डीएम सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट के स्टाफ को आईटी सेक्टर में दक्ष करने के उद्देश्य से एनआईसी के अधिकारियों द्वारा निरंतर रूप से कार्यक्रम बनाकर सभी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और सरकार के जो विभिन्न पोर्टल एवं वेबसाइट संचालित हैं, उनकी जानकारी उपलब्ध कराते हुए मेल मर्जिग का भी व्यापक स्तर पर सभी को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि कलेक्ट्रेट में जिन शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है, उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाए।

यातायात नियम तोड़ा तो सोशल मीडिया पर वायरल होगी फोटो

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

यदि आप ट्रैफिक नियमों को उल्लंघन करते हैं तो सावधान हो जाइये। आपका फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो सकता है। ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को कैमरे में कैद करने के लिए नोएडा जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने 10 फोटोग्राफरों की टीम उतारी है। यह टीम प्रदूषण फैलाने वालों के फोटो भी खींचेगी। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु रखने और सड़क हादसे कम करने के लिए प्रशासन ने यह पहल की है।

जिलाधिकारी बीएन सिंह ने बताया कि इस पहल के तहत दस फोटोग्राफर की एक टीम को सड़कों पर लगाया गया है। यह टीम गोपनीय तरीके से अलग-अलग स्थानों पर ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वालों और प्रदूषण फैलाने वालों को कैमरे में कैद करेगी। इन फोटो के आधार पर वाहन चालक के खिलाफ परिवहन विभाग और प्रदूषण विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इन फोटो का प्रचार भी जनसामान्य के बीच सोशल मीडिया के जरिये किया जाएगा। इसके जरिये बताया जाएगा कि ये लोग यातायात के नियम तोड़ते हैं, कहीं आप भी तो इनमें शामिल नहीं। डीएम ने कहा कि उनका प्रयास है कि जिले के लोग पर्यावरण सुरक्षा व ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग रहें।

मेरठ एक्सप्रेस वे, हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट की जल्द दूर करें अड़चन

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम मंगलवार को गाजियाबाद पहुंची और प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य प्रोजेक्ट में शामिल हाईस्पीड ट्रेन और मेरठ एक्सप्रेस-वे की समीक्षा बैठक की। जीडीए सभागार में अधिकारियों संग बैठक के दौरान उन्होंने इन दोनों प्रोजेक्टों की विस्तार से जानकारी लेते हुए इसमें आने वाली अड़चनों को तुरंत दूर करने के सख्त निर्देश दिए।

बैठक में क्या विषय रखे जाएंगे इसके लिए पहले ही मिनिट्स जारी कर दी गई थी। इसमें मुख्य रूप से दो प्रोजेक्ट रखे गये जिनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हाईस्पीड ट्रेन का था। हाईस्पीड ट्रेन का प्रोजेक्ट करीब तीन हजार करोड़ रुपये का है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। मगर यह काम अब मोदीनगर और आगे मेरठ तक होना है। इस प्रोजेक्ट को लेकर सबसे बड़ी समस्या हाईटेंशन लाइन को लेकर है। सात स्थानों पर हाईटेंशन लाइन हटाने का काम होना है, लेकिन इस पर कोई प्रगति नहीं हो पा रही है। जीडीए से ली गई करीब पांच हजार वर्गमीटर जमीन पर नये बस अड्डे के पास कब्जा लिया जाना है, मगर एनसीआरटीसी ने 65 करोड़ रुपये जमीन के नहीं दिये और उस पर कब्जा नहीं हो पाया। इस कारण भी यहां काम प्रभावित हो रहा है।

उधर, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे को लेकर भी कई समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या चार गांवों की जमीन को लेकर है, जिनमें डासना, रसूलपुर सिकरोड, नाहल और कुशलिया शामिल है। इनकी करीब 19 हेक्टेयर जमीन को लेकर विवाद चल रहा है और मेरठ एक्सप्रेस-वे में यही पेंच फंसा है। गत दिनों पीएमओ ने भी इसे संज्ञान लिया। इसके बाद यूपी सरकार हरकत में आई। अब मेरठ एक्सप्रेस-वे की बाधा दूर करने के लिए कोशिश चल रही है।

प्राधिकरण कार्यालय में अधिकारियों संग पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट्स को लेकर बैठक करतीं मेरठ जोन की कमिश्नर अनिता सी. मेश्राम। साथ मे डीएम अजय शंकर पांडे।

● मंडलायुक्त ने की अफसरों संग बैठक

संक्षिप्त समाचार

मलेरिया कर्मचारियों ने शुरू की क्रमिक हड़ताल

गाजियाबाद। जिला अरबन, मलेरिया, फाइलेरिया कर्मचारी संगठन ने सांतवे वेतन आयोग में दूसरी किश्त जारी न करने के विरोध में जिला मलेरिया अधिकारी के खिलाफ कर्मचारियों ने क्रमिक हड़ताल शुरू की। पहले दिन हड़ताल में पांच कर्मचारी धरने पर बैठे। धरनारत कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि सांतवे वेतन आयोग के तहत डीएल भुगतान की दूसरी किश्त जून 2019 में जारी होनी थी लेकिन, जिला मलेरिया अधिकारी भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग कर रहे हैं और विरोध करने पर भुगतान रोके जाने की धमकी दी जा रही है। इस मामले में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया गया था लेकिन, अभी तक भुगतान को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। पहले दिन हड़ताल पर बैठने वाले अर्जुन सिंह, रविन्द्र, सतीश, भीमसिंह, जितेन्द्र बैठे। इसके अलावा अशोक चांदीवाल, विजेन्द्र सिंह आदि मौजूद रहे।

आनंदाश्रम ने किया काव्य गोष्ठी का आयोजन

गाजियाबाद। आनंदाश्रम सामाजिक सांस्कृतिक संस्था द्वारा मिलिंद अकादमी सेक्टर-6 वैशाली में काव्य गोष्ठी का भव्य आयोजन कविवर स्व. विशुद्धानंद जी की स्मृति में किया गया। सर्वप्रथम संस्था के अध्यक्ष प्रणव कुमार ने आनंदाश्रम द्वारा कमजोर वर्ग के लिए किए गए प्रयासों का विवरण दिया। अपने काव्य पाठ में प्रणव कुमार ने विशुद्धानंद जी का जीवन परिचय दिया तथा उनके प्रतिनिधि कविताओं का काव्य पाठ किया। काव्य गोष्ठी में अवधेश सिंह, शैल भदावरी, पूनम कुमारी, जितेंद्र नारायण सिंह, कुमार अमिताभ, अनिमेष शर्मा अन्य कवियों ने अपना काव्य पाठ किया तथा सभी श्रोताओं ने ताली बजाकर कवियों का उत्साह बढ़ाया। प्रणव कुमार ने सभी कवियों को धन्यवाद स्वरूप प्रशस्ति पत्र भी दिए। मुख्य अतिथि के रूप में डीके सिंह, शासकीय समापक, कंपनी कार्य मंत्रालय, दिल्ली ने भी अपने उद्गार व्यक्त किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में आलोक शर्मा, गीता गंगोत्री, मीणा गंधर्व, जीविका संस्थान व एलाक्रिटी कॉरपोरेट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड का विशेष सहयोग रहा।

छापेमारी के दौरान हुक्काबारों से पकड़े गए युवक।

दो हुक्काबारों पर पुलिस की छापेमारी

गाजियाबाद। इंदिरापुरम पुलिस और प्रशासन ने सघन चेकिंग अभियान चलाकर अवैध हुक्काबार पर छापेमारी की। इस दौरान थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में 2 हुक्काबार पर छापेमारी के दौरान 19 युवकों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस ने 29 हुक्का के अलावा काफी मात्रा में नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। शासन-प्रशासन की लाख कवायद के बाद भी नौजवानों को नशे की लत लगाने वाले हुक्काबार अवैध रूप से चल रहे हैं। जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने रात में इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए दो हुक्काबार से 19 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए युवकों में हुक्का बार संचालक भी शामिल है। बता दें कि कुछ दिन पूर्व राजनगर आरडीसी में बने होते बारो पर भी कार्यवाही की गई थी। इस कार्यवाही में एएसपी केशव कुमार और उनकी टीम के साथ एडीएम सिटी व एसडीएम का भी अहम योगदान रहा।

इमरजेंसी में घायल मरीजों को समय से नहीं मिला इलाज

शासन तक पहुंचा मामला, एमएमजी अस्पताल प्रबंधन पर लटकी कार्रवाई की तलवार

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में गंभीर रूप से घायल मरीजों को समय से इलाज नहीं मिलने का मामला शासन तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में शासन से सख्त निर्णय लिया जा सकता है।

स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की ओर से प्रकरण को संज्ञान में लेने से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी हलकान हैं। इस मामले में स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन से इमरजेंसी वॉर्ड की एक सप्ताह की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी, जो उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से कई गंभीर बातें सामने आई हैं।

पिछले शुक्रवार को जिला एमएमजी अस्पताल की इमरजेंसी में आपसी विवाद में घायल हुए 2 लोग पहुंचे। आरोप है कि दोनों को इमरजेंसी में समय से उपचार नहीं मिला और बाद में उन्हें भर्ती करने की जगह मरहम-पट्टी करके भेज दिया गया। इसकी शिकायत स्वास्थ्य राज्यमंत्री से की गई, तो वह खुद ही अस्पताल में निरीक्षण करने पहुंच गए। स्वास्थ्य राज्यमंत्री के सामने ही घायलों ने अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही उजागर की थी, जिसके बाद संबंधित डॉक्टर ने भी अपनी सफाई में शासन की अव्यवस्थाओं की ही दुहाई दे दी।

इसके अगले दिन शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था में सुधार लाने की चेतावनी दी। इसके बाद स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने अस्पताल प्रबंधन से इमरजेंसी वॉर्ड की एक सप्ताह की सीसीटीवी फुटेज मांगी थी। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज से कई गंभीर मामले सामने आए हैं। जिसके बाद स्वास्थ्य राज्यमंत्री की ओर से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की गई थी। शासन स्तर से सीएमओ से मामले में आख्या मांगी गई थी।

सूत्र बताते हैं कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को शासन ने गंभीरता से लिया है और जल्द ही कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। शासन और सरकार के कड़े रुख को देखते हुए जिले में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी खासे हलकान हैं।

नाबालिग बेटा निकला मां का हत्यारा, बाल सुधार गृह भेजा

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

बादलपुर कोतवाली क्षेत्र के धूममानिकपुर गांव में शनिवार रात घर में सो रही एक महिला की संदिग्ध परिस्थिति में गला दबाकर हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। महिला की हत्या उसके नाबालिग बेटे ने ही की थी। आरोपी बेटे ने अपराध कबूल कर लिया है।

पुलिस ने आरोपी बेटे को किशोर न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया है। हत्या की वजह मां के बार-बार पानी व तंबाकू मांगना बताया जा रहा है। एसपी देहात रणविजय सिंह ने बताया कि जांच-पड़ताल में सामने आया है कि घटना का कारण लूटपाट नहीं था। जांच में महिला की किसी से रंजिश नहीं होने की बात भी सामने आई।

वारदात के वक्त महिला के नाबालिग बेटे के अलावा घर में कोई और नहीं था। एसपी ने बताया कि महिला के बेटे पर शक होने पर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना अपराध कबूल किया। आरोपी ने बताया कि मां की वजह से वह सो नहीं पा रहा था।

एनएमआरसी के सभी 21 स्टेशनों पर चार्जिंग पाइंट

नोएडा। आने वाला समय इलेक्ट्रानिक वाहनों का होगा। पेट्रोल व डीजल की जगह इनको चार्ज करना होगा। एनएमआरसी भी इसमें अपनी भागीदारी करने जा रही है।

एनएमआरसी के सभी 21 स्टेशनों पर इलेक्ट्रानिक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। इसके लिए उन्हें संचालित करने वाली कंपनी को भुगतान करना होगा। अनुबंध के तहत इसका कुछ प्रतिशत कंपनी एनएमआरसी को देगी जिससे एनएमआरसी के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। एनएमआरसी ने इच्छुक कंपनियों से आवेदन मांगे थे। जिसमें 19 कंपनियों ने आवेदन किया है।

चार झपटमार दबोचे, 41 मोबाइल बरामद

पायनियर समाचार सेवा। गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस ने दिल्ली-एनसीआर में मोबाइल स्नैचिंग व चोरी करने वाले गैंग के चार शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरों में गैंग का सरगना भी शामिल है। इनके कब्जे से पुलिस ने लूटे गए 41 एंड्राइड मोबाइल और चोरी के वाहनों के साथ अवैध हथियार भी बरामद किया है।

पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए चारों लुटेरे शालीमार गार्डन कॉलोनी में लूट के इरादे से पहुंचे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चांद इब्राहिम, जुनैद, चांद और अकाश को बताए गए स्थान से गिरफ्तार किया।

● मुंबई से जुड़े है गिरोह सरगना के तार

उन्होंने बताया कि पकड़े गए लुटेरों में से चांद इस गैंग का लीडर है जो कि दिल्ली-एनसीआर में बाइक पर घूमते हुए महिलाओं को अपना निशाना बनाता था और मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया करता था। पूरे एनसीआर में इन सभी का एक बड़ा नेटवर्क है। चांद पर दिल्ली-एनसीआर में 14 अपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि एसपी सिटी मनीष मिश्रा द्वारा सेकेंड हैंड मोबाइल की खरीद और बिक्री को लेकर चलाये जा अभियान के कारण ही इस गैंग को पकड़ा जा सका है। एसएसपी के मुताबिक गिरोह के सरगना चांद के तार मुंबई से जुड़े हैं। चांद मोबाइलों के पार्ट्स व ईएमआई नंबर बदलकर मुंबई भेज दिया करता था जिस कारण ये पुलिस की गिरफ्त से बचा रहता था।

एनसीआर में मोबाइल लूटने वाले गिरोह की गिरफ्तारी के बाद जानकारी देते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह।

स्कूली बसों में जरूरी उपकरण होने पर ही बनेगा फिटनेस प्रमाण पत्र

पायनियर समाचार सेवा। नोएडा

परिवहन विभाग ने स्कूल बसों की मॉनीटरिंग को और बढ़ा दिया है। शासन के दिशा-निर्देश पर विभाग ने स्कूल बसों में सीसीटीवी कैमरा, सीट बेल्ट, स्पीड गवर्नर और जीपीएस अनिवार्य कर दिया है। इनके अभाव में अब विभाग में बसों का फिटनेस प्रमाण नहीं बनेगा।

● परिवहन विभाग ने बढ़ाई बसों की निगरानी

एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय ने बताया कि नई व्यवस्था को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दरअसल, अनिवार्यता के बाद भी स्कूल प्रबंधन इन आवश्यक उपकरणों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में उपकरण लगने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं। रास्ते में अनफिट स्कूल बस पकड़े जाने पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अनफिट बसों से दुर्घटना होने पर विद्यालय प्रबंधक व प्रधानाचार्यों पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

एआरटीओ प्रशासन एके पांडेय के अनुसार गहन पड़ताल के बाद अगस्त में अनफिट 55 स्कूल बसों को तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया था। साथ ही नोटिस दी गई थी कि तीन माह बाद हर हाल में विभाग से फिटनेस प्रमाण पत्र बनवा लें। नवंबर को तीन माह पूरे हो गए हैं ऐसे में अब निलंबित जिन बसों का फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बनाया गया है उनका पंजीकरण को रद्द कर दिया गया। उन्होंने बताया कि जिन स्कूलों को नोटिस भेजे गए हैं इसके बाद भी स्कूल प्रबंधन फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं बनवाते हैं तो पंजीयन हमेशा के लिए निरस्त कर दी जाएगी।

एआरटीओ के अनुसार जून में अभियान चलाकर स्कूल बसों की जांच कराई गई थी। जिसमें 105 बसें अनफिट पाई गईं। विभाग ने स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 26 जून से 20 जुलाई तक फिटनेस प्रमाण पत्र बनवाने का समय दिया था। इसके बाद भी सिर्फ 50 स्कूल बसों का फिटनेस प्रमाण पत्र बना। शेष 55 ने आवश्यक नहीं समझा।

ये किए हैं मानक तय

- *अग्निशमन यंत्र व फर्स्ट ऐड बाक्स जरूरी।*
- *अधिकतम गति 40 किमी प्रति घंटे से अधिक नहीं।*
- *आरामदेह सीट, सेफ्टी बेल्ट और आमरेस्ट अनिवार्य।*
- *सीएनजी स्कूल वाहनों का त्रैमासिक चेकिंग अनिवार्य।*
- *प्रेशर हार्न या टोनल साउंड सिस्टम पूरी तरह प्रतिबंधित।*
- *बैठने की क्षमता से डेढ़ गुना से अधिक बच्चे नहीं बैठेंगे।*
- *चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस व्यावसायिक होना अनिवार्य।*
- *बिना रजिस्ट्रेशन के एक भी वाहन नहीं चलाए जाएंगे।*

पार्टी के स्थापना दिवस पर गरीबों को कंबल बांटे

नोएडा। आम आदमी पार्टी ने अपने 7वें स्थापना दिवस एवं भारतीय संविधान के 70वें संविधान दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर और असहाय, गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे। इस मौके पर पार्टी के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र जादौन ने कहा आंदोलन से निकलकर आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी जोकि 2012 में की गई थी। इसके बाद लोगों ने देखा कैसे सरकार चलाई जाती है।

आज दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण देश की अन्य राज्यों के लिए बन चुका है। जहां जमीनी मुद्दों पर काम किया गया है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का समाधान कराया। अरविंद केजरीवाल ने साबित कर दिया की ईमानदार सरकार इस देश में चल सकती है।

सीएमवाईके प्रिंटेक लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक चन्दन मित्रा द्वारा नं. 6, गुलाब भवन के पीछे, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002, दूरभाष: 011-40110455 से प्रकाशित तथा बीएफएल इन्फोटेक लिमिटेड सी-9 सेक्टर-3, नोएडा-201301 (उ.प्र.) से मुद्रित। सम्पादक: चन्दन मित्रा, स्थानीय सम्पादक: उषा श्रीवास्तव। पाठकों को सुझाव दिया जाता है कि इस अखबार के किसी भी विज्ञापन पर प्रतिक्रिया करने से पहले पूरी तरह उसके बारे में दिए गए दावों, शर्तों और तथ्यों की जांच कर लें। पायनियर ग्रुप के मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक या उसका कोई भी कर्मचारी विज्ञापनदाता द्वारा उनके किसी उत्पाद तथा सेवा हेतु किए गए किसी दावे की सच्चाई का आश्वासन या उत्तरदायित्व नहीं लेता है। ऐसे विज्ञापनों के बाद किसी आर्थिक क्षति के लिए वे जिम्मेदार भी नहीं हैं। पत्रवार्ता ऑफिस- एफ-31, सेक्टर 6, नोएडा, गौतमबुद्धनगर-201301, उत्तर प्रदेश, दूरभाष- 120-4879800-4879900।

केजरीवाल का वादा : पूरा करेंगे आंबेडकर का सपना

दिल्ली सरकार के अभियान-संविधान के 70 साल पूरा होने पर समारोह को किया संबोधित

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

भारत का संविधान इतना बेहतर है कि अगर एक दिन के लिए उसे ईमानदारी से लागू कर दिया जाए तो देश को दुनिया में नंबर एक बनने से कोई नहीं रोक सकता। पिछले पांच साल के अंदर दिल्ली सरकार इसी संविधान से चलने की कोशिश कर रही है।

सरकार ने समानता व शिक्षा जैसे अधिकारों को वास्तविक रूप में लागू किया है। बाबा साहेब आंबेडकर के सपनों को दिल्ली में पूरा किया। यहां अमीर-गरीब के बीच की दीवार गिर गई है। पानी व बिजली पर सबका एक समान अधिकार है। सभी को सस्ती व 24 घंटे बिजली मिल रही है। सरकारी स्कूलों में निजी स्कूल जैसी शिक्षा मिल रही है। सरकारी अस्पताल में दवा व इलाज सभी को मुफ्त व बेहतर मिल रही है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यह बात मंगलवार को इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शिक्षा विभाग के तीन माह से चल रहे कांस्टीट्यूशन एट 70 कैंपेन के समापन समारोह में कही। समारोह में दिल्ली के विभिन स्कूलों के प्रिंसिपल, टीचर व छात्र मौजूद थे। अरविंद केजरीवाल ने कहा सबसे पहले जो उन्होंने बच्चों के सवाल जवाब देखे। उससे बेहद खुशी होती है। बच्चों ने जीतने अच्छे से सवाल किया। साथ ही उसी बेहतर तरीके से बच्चों ने सवाल का जवाब देकर अपना आत्मविश्वास दिखाया।

उससे पता चलता है कि सरकारी स्कूलों में तीन माह में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व को कितना आत्मसात किया है। बच्चों ने अपने अभिभावक व रिश्तेदारों से इस संबंध में कितनी बात की है। उनके हिसाब से असली शिक्षा यही है। हम कागजों में कुछ भी पढ़ाते रहे उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक शिक्षा को महसूस नहीं करेंगे। उसका कोई मतलब नहीं है। संविधान के कारण भारत एक साथ है और खूब तरक्की भी कर रहा । हमारा संविधान 70 साल का हो गया।

वह समय के साथ बहुत परिपक्व हो गया है। हमारे देश में इतनी विविधता, संस्कृति, धर्म है। इतनी विविधता वाले देश में एक तरह सरदार बल्लभ भाई पटेल देश को एक धागे में पीरो रहे थें। एकजूट कर रहे थें। ऐसे देश को एकजूट रख पाना हंसी खेल नहीं था। पूरी दुनिया इस बात को देख रही थी कि क्या भारत एक साथ रह पाएगा। अंग्रेज कह रहे थें कि वह हम थें कि भारत को एकजूट रख पाए। अब भारत बिखर जाएगा। अब देश नहीं चलने वाला।

आज 70 साल हो गए। भारत एक साथ भी है और खूब तरक्की भी कर रहा है। उसका केवल एक ही कारण है देश का संविधान । ऐसे देश का संविधान लिखना आसान नहीं था, जिसमें इतनी विविधता, धर्म और संस्कृति हो। बाबा साहेब ने पूरी दुनिया का संविधान पढ़ा। उसमें जितनी अच्छी बातें थी। उसे अपने संविधान में डाला और इतना अच्छा संविधान दिया। वह जीतना संविधान को पढ़ाते हैं।

फोटो : रंजन डिमरी

कांस्टीट्यूशन एट 70 कैंपेन के समापन समारोह में बोलते मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, साथ में मनीष सिसोदिया व अन्य

जातिवाद से ऊपर उठा देश : सिसोदिया

उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के मुताबिक संविधान को देश ने 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर तय किया था कि हम एक दूसरे के साथ जीएंगे कैसे। तीन महीने पहले उन्होंने स्कूलों में इस मुहिम को प्रारंभ किया। तभी तय कर लिया कि कर्तव्य व अधिकार दोनों के बारे में बताएंगे। समानता हमारा कर्तव्य व अधिकार भी है। संविधान की प्रस्तावना यह बताती है कि इंसान एक दूसरे के साथ कैसे जी सकता है। एक समय ऐसा भी था जब एक रास्ते से एक जाति के लोग जाते थें तो उसपर दूसरी जाति के लोगों को जाने की इजाजत नहीं थी। आज 70 साल में देश इन चीजों से उपर उठ चुका है। तो वह संविधान व शिक्षा की वजह से। पहले शिक्षा पर भी एकाधिकार था लेकिन आज ऐसा नहीं है। संविधान की प्रस्तावना को सभी किताबों के पहले पनने पर इसी कारण छापते हैं कि पढ़े हुए को जीवन में लागू कर सकें।

गरीब-अमीर का बच्चा एक समान : मुख्यमंत्री

केजरवाल के अनुसार, गत पांच साल में दिल्ली सरकार इसी संविधान से चलाने की कोशिश कर रही है। संविधान में लिखा है बराबरी का अधिकार होगा। अभी तक शिक्षा में अमीर और गरीब बच्चों के बीच बहुत गहरी खाई थी। मुख्यमंत्री के लिए दोनों बच्चे बराबर हैं। वह दोनों बच्चों में फर्क नहीं कर सकते। दिल्ली में आप सरकार बनी तभी उन्होंने प्रण लिया कि गरीब के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा मुहैया कराएंगे। गरीब हो या अमीर का बच्चा दोनों को एक समान शिक्षा मिलेगी। उन्होंने बाबा साहेब का एक सपना पूरा दिया। इसके अलावा पहले किसी को बिजली मिलती थी, किसी को नहीं मिलती थी। उन्होंने सभी को बराबरी का अधिकार दिया।

बिल की मांग करती आप ने पेश होने पर बताया धोखा

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

अनाधिकृत कालोनियों को नियमित करने लिए संसद में बिल लाने की मांग करती आम आदमी पार्टी ने केंद्र के बिल को दिल्ली वालों के साथ कच्ची कॉलोनियों को पक्का कराने के नाम पर बड़ा धोखा बताया है।

आप प्रवक्ता ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले इन कॉलोनियों में रहने वालों को बहकाने की कोशिश कर रही है भाजपा। लेकिन दिल्ली वालों को कानून का जुमला नहीं, रजिस्ट्री चाहिए। आप प्रवक्ता ने मीडिया में आई खबरों का हवाला देते हुए कहा कि इस पूरी प्रक्रिया के अंत में चुनाव से पहले सिर्फ 100 लोगों को रजिस्ट्री दिलवाएगी केंद्र सरकार। रजिस्ट्री दिलवाने का महज सांकेतिक काम किया जाएगा। इससे ये सवाल उठता है की ये 100 लोग कौन होंगे। कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले लाखों लोग जो रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे हैं उनका क्या कसूर है। उनको क्यों नहीं मिलनी चाहिए रजिस्ट्री। इससे स्पष्ट है की भाजपा भी कांग्रेस की राह पर चल रही है। कांग्रेस ने वर्ष 2008 के चुनाव से ठीक पहले इसी तरह से प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थें। भाजपा सौ लोगों की रजिस्ट्री कराकर जनता के आंखों में धूल झोकने का काम करने जा रही है।

आप का झूठ फिर बेनकाब : भाजपा

केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिये मंगलवार को लोकसभा में बिल प्रस्तावित कर दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुरी को धन्यवाद देते हुए आप पर निशाना साधत हुए कहा कि अब अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक मिलने की सारी बाधायें दूर हो गई हैं। जल्द ही रजिस्ट्री का काम भी शुरू हो जायेगा। आप का झूठ एक बार फिर बेनकाब हो गया है क्योंकि आप यह प्रचारित कर रही थी कि संसद में भाजपा कोई बिल नहीं लाने वाली है लेकिन आज आप के उन नेताओं पर करारा तमाचा है जो यह कह रहे थे कि संसद के इस सत्र में अनधिकृत कालोनियों से संबंधित कोई बिल नहीं आने वाला है। भाजपा लोगों को यह विश्वास दिलाती है कि वह जो कहती है उसे पूरा करती है। मनोज तिवारी के अनुसार कांग्रेस 15 साल तक अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों के साथ धोखा करती रही है। चुनाव जीतने के लिये कांग्रेस ने लोगों को झूठा प्रोविजनल सर्टिफिकेट तक बांट दिया जिससे अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोग ठगा महसूस कर रहे थे। पांच साल तक केजरीवाल सरकार ने भी इन लोगों के साथ विश्वासघात किया।

खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण, आज सुधार की उम्मीद

● पश्चिमी विक्षोभ के चलते आज हो सकती है हल्की बारिश

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण पहले की अपेक्षा कुछ कम तो हुआ है लेकिन दो दिन से लगातार यह खराब श्रेणी में बना हुआ है।

शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार रात आठ बजे 262 दर्ज किया गया। पूसा में एक्यूआई मॉडरेट (174) तो धीरपुर, एयरपोर्ट, आईआईटी, नोएडा में यह 220 से 300 के बीच रहा जबकि चांदनी चौक, मथुरा रोड और आयानगर में एक्यूआई बहुत खराब स्तर पर रहा। बीते डेढ़ महीने से वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ था।

मौसम विभाग के अनुसार अफगानिस्तान और आसपास पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इससे दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बुधवार को हल्की बारिश होने की संभावना है। वायु गुणवत्ता निगरानी करने वाली सरकारी एजेंसी सफर के अनुसार बारिश से राजधानी के वातावरण में प्रदूषण काफी हद तक कम हो जाएगा और इसके खराब से मॉडरेट श्रेणी में आने की संभावना है। सिस्टम ऑफ एयर क्वॉलिटी ऐंड वेदर फोरकास्टिंग ऐंड रिसर्च (सफर) के अनुसार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक मंगलवार सुबह 9 बजकर 42 मिनट पर 254 दर्ज किया गया था। एक्यूआई 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर श्रेणी में माना जाता है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 24 घंटों में बारिश होने से राहत मिल सकती है।

वहीं दिवाली के बाद स हवा का स्तर लगातार खराब बना हुआ है और प्रदूषण भी काफी गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। इस महीने दिल्ली-एनीसीआर की हवा प्रदूषण के कारण काफी जहरीली हो गई और यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय रही। हालांकि, बीच में कुछ दिन लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत भी मिली।

'केजरीवाल फिर से' कैंपेन के लिए सीएम ने जारी किया मोबाइल नंबर

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मोबाइल नंबर 9509997997 जारी किया है। इस नंबर पर लोग विधानसभा चुनाव के लिए आप के अभियान से जुड़ने के लिए मिस्ड कॉल कर वालंटियर बन सकते हैं।

आम आदमी पार्टी के सातवें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में, केजरीवाल ने कहा कि पिछले सात वर्षों में उनकी पार्टी ने दिल्ली में राजनीति की दिशा बदल दी है। नतीजतन, भाजपा राष्ट्रीय राजधानी में हिंदू-मुस्लिम की राजनीति नहीं, बल्कि बिजली और शिक्षा के मुद्दों पर बात करने को मजबूर हो गई है। आप के आठवें स्थापना दिवस पर पार्टी मुख्यालय पर कार्यकताओं व नेताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने सात साल के सफर में राजनीति में तीन बड़े बदलाव किए।

पहला सत्ता ईमानदारी से भी चल सकती है। दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी और बिजली में बदलाव हो सकता था लेकिन अन्य पार्टियों ने 70 साल तक काम नहीं किया। तीसरा बदलाव यह किया कि अब दिल्ली में काम की राजनीति होने लगी है। अब दिल्ली में कोई पार्टी जाति व धर्म की राजनीति नहीं कर रही हैं। वह भी विकास, पानी व कच्ची कालोनी पर बातकर रही है।

संक्षिप्त समाचार

झड़प में घायल हुए पुलिसकर्मियों को मिलेंगे 8 लाख

नई दिल्ली। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इस महीने की शुरुआत में तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों के साथ झड़प में घायल हुए 21 पुलिसकर्मियों को सहायता राशि प्रदान करने के लिए लगभग आठ लाख रुपए की मंजूरी दी है। गत 25 नवंबर को जारी एक आदेश के अनुसार, गंभीर रूप से घायल हुए आठ पुलिसकर्मियों को तत्काल चिकित्सा जरूरत के लिए पचास-पचास हजार रुपए मिलेंगे, जबकि मामूली रूप से घायल 13 पुलिसकर्मियों को तीस-तीस हजार रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी।आदेश में कहा गया कि उपराज्यपाल ने तत्काल चिकित्सा जरूरत के लिए वित्तीय सहायता के रूप में 7,90,000 रुपए की मंजूरी दी है। गत दो नवंबर को तीस हजारी अदालत में पार्किंग विवाद को लेकर हुई झड़प में कम से कम 20 सुरक्षाकर्मी और कई अधिवक्ता घायल हो गए थे।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर दीपालय ने किया जागरूक

नई दिल्ली। दीपालय संस्था ने राष्ट्रीय दुग्ध दिवस व अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा विरोधी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया। जिसमें 170 से ज्यादा महिलाओं व छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए दीपालय द्वारा प्रोजेक्ट की क्षेत्रीय अधिकारी अनीता राणा ने इस दिन की विशेषता के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की। अमूल के जोनल ऑफिस की तरफ से कार्यक्रम का प्रयोजन किया गया जिसमें उपस्थित सदस्यों को अमूल की डॉक्युमेंटरी फिल्म भी दिखाई गई जिसमें दर्शाया गया कि अमूल की शुरूआत कैसे हुई। सोशल सर्विस यूनियन की तरफ से कविता यादव भी उपस्थित हुई उन्होंने हिंसा से संबंधित कानून तथा उसके समाधानों के विषय में महिलाओं को जागृत किया। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में अमूल से रजित , अजीत व दीपालय से संदीप कुमार उपस्थित हुए।

जीवनशैली बदलकर बीमारियों से बचें : डॉ. आलोक

नई दिल्ली। देवम वैलनेस ने फंक्शनल और बॉयोरेगुलेटरी मेडिसन सेंटर लांच कर रहा है। इसमें कई तरह की गंभीर बीमारियों का इलाज पुराने व आधुनिक दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए किया जाएगा। बीमारियों का इलाज भी 'देवम तरीके' से ही किया जाएगा। मेडिकल डॉयरेक्टर डॉ. आलोक चोपड़ा ने कहा, हम वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार बॉयलोजी मेडिसन दृष्टिकोण अपनाकर व्यक्ति की न सिर्फ बीमारी बल्कि ये भी जानते है कि उनका जेनेटिक व्यवहार कैसे लाइफस्टाइल को नियंत्रित करता है। सीईओ संजय सचदेवा कहते हैं, विभिन्न टेस्ट के माध्यम से सभी तरह के महत्वपूर्ण डेटा का विश्लेषण करता है। डॉबर ग्रुप के चेयरमैन इमरिटस डॉ. आनंद बर्मन ने कहा, शरीर को ठीक करने के लिए पारम्परिक दवाइयों की शक्ति पर काम करना हमारा लक्ष्य रहा है।

रोहिणी पार्क में पेड़ से लटका मिला शव

नई दिल्ली। रोहिणी के सेक्टर 20 स्थित एक पार्क में एक शख्स का शव मंगलवार को पेड़ से लटका हुआ मिला। पुलिस ने कहा कि पहली नजर में यह आत्महत्या का केस लगता है।

प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटके शव की फिलहाल पहचान नहीं हो सकी है लेकिन उसकी उम्र 30 साल के आस-पास है। उसके शरीर पर बाहरी चोट के कोई निशान नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने बताया कि अमन विहार थाने को इस घटना की जानकारी दी गई। साथ ही कहा कि मृतक की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

तस्करों के पेट से निकाले 10 करोड़ की हेरोइन के कैप्सूल

● आईजीआई पर 7 अफगानी गिरफ्तार

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

सीमा शुल्क विभाग की नजरों से बचने के लिए तस्कर सामान छुपाने के अनोखे तरीके अपनाते हैं।

ऐसे ही मामले में अफगानी तस्कर हेरोइन के कैप्सूल पेट में छुपाकर ला रहे थे। हालांकि वे अधिकारियों की तेज निगाह से बच नहीं पाए और मेडिकल कराकर कैप्सूल निकाल लिए गए। अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क अधिकारियों ने 9.78 करोड़ रुपए की हेरोइन की तस्करी करने की कोशिश के आरोप में सात अफगान नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपियों को 16 नवंबर को अफगानिस्तान के कंधार से यहां पहुंचने के बाद पकड़ा गया। यात्रियों की जांच में हेरोइन की 214 कैप्सूल की बरामदगी हुई।

दिव्यांगों के प्रदर्शन से मंडी हाउस में जाम

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

रेलवे में चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले दिव्यांग युवकों के विरोध प्रदर्शन के चलते मंडी हाउस चौराहों पर भयंकर जाम लग गया। इस कारण निजी और सार्वजनिक वाहनों में यात्रा कर रहे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अलग-अलग राज्यों से दिव्यांग आवेदक मंगलवार तड़के राष्ट्रीय राजधानी पहुंचे।

उन्होंने भगवान दास मार्ग पर धरना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने इस मार्ग को यातायात के लिए बंद कर दिया। प्रदर्शन के कारण सिकंदर रोड और भगवान दास रोड बंद होने से आसपास की सड़कों पर यातायात का दबाव बढ़ गया और जाम की स्थिति बन गई। रेलवे अधिकारियों से मुलाकात की मांग करते हुए लगभग 200 दिव्यांगों ने 23 अक्टूबर को भी मंडी हाउस चौराहे पर प्रदर्शन किया था।

पीपीपी मॉडल पर पार्कों का रखरखाव

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

उत्तरी दिल्ली के महापौर अवतार सिंह ने संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। महापौर ने बताया कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में उपलब्ध सुविधाओं और वहां की समस्याओं के बारे में विस्तार से चर्चा हुई।

महापौर ने बताया कि अधिकारियों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की 17 पार्किंग का संचालन एसोसिएशन को निगम द्वारा निर्धारित दरों पर देने के लिए एक प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए है। महापौर ने निगम अधिकारियों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है ताकि वहां उपलब्ध सुविधाओं को व्यवस्थित किया जा सके। महापौर ने अधिकारियों को संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉटों को फ्री होल्ड करने की योजना बनाने व संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए जिस से की निगम के राजस्व की प्राप्ति होगी।

मेयर ने बताया कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर के 6 पार्कों को रख-रखाव के लिए एसोसिएशन को देने का निर्णय किया गया है।

आसान भाषा में लिखी जाए एफआईआर : कोर्ट

नई दिल्ली। उर्दू-फारसी के 383 शब्दों का इस्तेमाल रोकने के लिए हाई कोर्ट ने राजधानी के विभिन्न थानों से 100 एफआईआर की प्रतियां मंगवाई हैं। हाई कोर्ट इससे यह पता लगाना चाहता है कि जिन शब्दों के इस्तेमाल को रोकने के परिपत्र जारी किया गया था, उसका अनुपालन हो रहा है या नहीं।

कोर्ट ने कहा कि प्राथमिकी सरल भाषा में होनी चाहिए। प्राथमिकी दर्ज करने के दौरान उर्दू और फारसी के उन जटिल शब्दों का इस्तेमाल रोकना चाहिए, जिनका बगैर सोचे-समझे और स्वत: ही इस्तेमाल कर दिया जाता है।

जेएनयू फीस में कटौती की सिफारिश

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में हाल ही में गठित समिति ने फीस में कटौती की सिफारिश कर दी है। इसमें बीपीएल के साथ सामान्य वर्ग के छात्रों को भी शामिल किया गया है।

समिति ने 2000 रुपये का यूटिलिटी और सर्विस चार्ज कम कर 1000 कर दिया है। इसके साथ ही बीपीएल श्रेणी के लिए 75 प्रतिशत फीस कम करने का सुझाव दिया है। अब इस श्रेणी के छात्रों को 2000 के बजाय 500 रुपये ही देने होंगे। फीस वृद्धि पर हुए बवाल के बाद बीपीएल श्रेणी के छात्रों के शुल्क में 50 फीसदी की कटौती की गई थी लेकिन छात्र इससे संतुष्ट नहीं थे और लगातार आंदोलन कर रहे थे। अब सिफारिश में कहा गया कि बीपीएल श्रेणी में आने वाले छात्रों के लिए आवश्यक सेवा शुल्क में 75 फीसद और बाकी छात्रों के लिए इस शुल्क में 50 फीसद की कटौती की गई है। इससे छात्रों और अन्य पक्षकारों के बीच अच्छा संदेश जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नई दरें 2020 में जनवरी से ही लागू होंगीं। बता दें कि काफी दिनों से जेएनयू के छात्र फीस वृद्धि के खिलाफ सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे हैं।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

बागवानी विभाग (मुख्यालय)
ई-ब्लॉक, तीसरा तल, डॉ. एस.पी.एम. सिविक सेंटर
जे.एल. नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002

निविदा आमंत्रण सूचना

"एसडीएमसी के अधीन पार्कों में विभिन्न स्थानों पर एमएलएएलएडीएस निधि के अंतर्गत चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट्स की आपूर्ति एवं संस्थापन" के लिए भारतीय विनिर्माता फर्मों या उनके अधिकृत डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों से दो निविदा प्रणाली (तकनीकी एवं वित्तीय) के अंतर्गत ऑनलाइन मद दर निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। चिल्ड्रन प्ले इक्विपमेंट्स के भारतीय विनिर्माता/उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर की संयुक्त उद्यम फर्म भी निविदा में भाग ले सकती है। अनुमानित राशि: रु. 429.43 लाख, ईएमडी: रु. 8.59 लाख, पूर्णता अवधि: तीन माह। लेखा शीर्ष XL-VIII-S विस्तृत नियम व शर्तों के साथ निविदा दस्तावेज वेबसाइट http://mcdetenders.com से डाउनलोड एवं जमा किए जा सकते हैं या एसडीएमसी वेबसाइट www.mcdonline.gov.in/दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/टेंडर्स/ई-टेंडरिंग देखें। ऑनलाइन निविदा के लिए हेल्पडेस्क नं. 011-23227413 एवं 011-23227414 पर कॉल करें या mcd-ithelpdesk@mcd.gov.in पर मेल करें जिसका टेंडर नं. 317625 है । डाउनलोड, निविदा तैयारी एवं हॉश जमा तिथि 27.11.2019 को प्रातः 10.01 बजे से 04.12.2019 दोपहर 3.00 बजे तक। ऑनलाइन निविदा के रि-एनक्रिप्शन की तिथि : 04.12.2019 को सायं 5.01 बजे से 05.12.2019 को दोपहर 3.00 बजे तक। तकनीकी निविदा खुलने की तिथि : 05.12.2019 दोपहर 3.30 बजे। उपरोक्त निविदा(ओं) के संबंध में संशोधन, स्पष्टीकरण, शुद्धिपत्र, परिशिष्ट, समय विस्तार आदि, यदि कोई हो, के सभी विवरण केवल एसडीएमसी वेबसाइट http://mcdetenders.com, www.mcdonline.gov.in/दक्षिणी दिल्ली नगर निगम/टेंडर्स/ई-टेंडरिंग पर अपलोड किए जाएंगे तथा इन्हें समाचारपत्रों में प्रकाशित नहीं किया जाएगा। निविदादाता इन निविदाओं के संबंध में नवीनतम जानकारी के लिए वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें।

RO No. 119/DPI/S/2019-20 उप निदेशक (बागवानी) मुख्यालय

संविधान दिवस पर लोगों को दिलाई शपथ

संविधान दिवस के मौके पर अधीनस्थों के साथ रेलवे के महाप्रबंधक टीपी. सिंह।

पायनियर समाचा सेवा। नई दिल्ली

70वें संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी के कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान लोगों को संविधान की शपथ दिलाई गई।

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर में उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर अवतार सिंह ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सिविक सेंटर, मुख्यालय में संविधान'' की शपथ दिलाई। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की आयुक्त वर्षा जोशी व सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगणों ने अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर शपथ ली। इस के साथ ही आयुक्त वर्षा जोशी ने सभी कर्मचारियों को मौलिक कर्तव्यों के अनुपालन की भी शपथ दिलाई।

इस अवसर पर महापौर अवतार सिंह व निगम के सभी अधिकारियों ने भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। वहीं नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने मुख्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और विद्यालयों में प्रात: संविधान दिवस का आयोजन किया।

इस अवसर पर पालिका परिषद् के अध्यक्ष धर्मेन्द्र ने सभी विभागाध्यक्षों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा और सभी को संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की शपथ भी दिलाई। संविधान दिवस का महत्त्व रेखांकित करते हुए उन्होंने कहा कि इस दिन आयोजित की जाने वाली गतिविधियों से हम संविधान में व्यक्त किये गये मूल्यों और आदर्शों को पुन: स्मरण करने और उन्हें सकारात्मक रूप से परिष्कृत करने का मौका मिलता है और नागरिकों को लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में अपना यथोचित योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी बल मिलता है।

पालिका परिषद् सचिव डॉ. रश्मि सिंह ने बताया कि पालिका परिषद् के सभी विद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों में संविधान दिवस मनाया गया, इसके अंतर्गत संविधान की प्रस्तावना को पढ़ा गया और संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों की शपथ भी दिलाई गई। वहीं उत्तर रेलवे, प्रधान कार्यालय, बड़ौदा हाउस में बड़े उत्साह के साथ संविधान दिवस का आयोजन किया गया। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक टीपी. सिंह, वरिष्ठ उप महाप्रबंधक चन्द्रलेखा मुखर्जी सहित उत्तर रेलवे के विभिन्न विभागों के सभी प्रमुख विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

उपस्थित समस्त अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने भारत के संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों का अनुसरण करने की शपथ ली। सिंह ने कहा कि मौलिक कर्तव्यों पर वर्ष भर समारोह और गतिविधियों के आयोजन से जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।

वर्तमान चिकित्सा पद्धति छोड़ पौराणिक उपचार करेंगे देश के नामी चिकित्सक

गुरुग्राम में खुला भारत का पहला प्राकृतिक चीजों से उपचार का केंद्र

डाबर समूह के रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से खोला गया केंद्र

संजय कुमार मेहरा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-3 नाथूपुर स्थित देवम वेलनेस सेंटर के उद्घाटन अवसर पर संस्थापक एवं मेडिकल डायरेक्टर डा. आलोक चोपड़ा, डाबर समूह के चेयरमैन इमरिटस डा. आनंद बर्मन, वेलनेस सेंटर के संस्थापक एवं सीईओ संजय सचदेवा।

वर्तमान जो चिकित्सा पद्धति है, वह बीमारियों को जड़ से खत्म नहीं कर पा रही। कहीं न कहीं मरीजों में बीमारियां बनी रहती हैं और चिकित्सा क्षेत्र में उन्हें सही करार देकर मरीजों को एक तरह से दिमागी तौर पर राहत दे दी जाती है। बहुत सी बीमारियां फिर से पनप जाती हैं और व्यक्ति फिर से अस्पतालों के चक्कर काटता है।

यह बात देवम वेलनेस सेंटर के संस्थापक एवं मेडिकल डायरेक्टर डा. आलोक चोपड़ा का। इस देवम वेलनेस सेंटर का उद्घाटन मंगलवार को यहां एमजी रोड स्थित डीएलएफ फेज-3, नाथूपुर में किया गया। इस मौके पर डाबर समूह के चेयरमैन इमरिटस डा. आनंद बर्मन, वेलनेस सेंटर के संस्थापक एवं सीईओ संजय सचदेवा भी मौजूद रहे।

बातचीत में डा. आलोक चोपड़ा ने कहा कि वर्तमान उपचार की पद्धति और प्रक्रिया से वे नाखुश थे। वे महसूस करते थे कि हम मरीजों को डायगनोज करके उपचार के नाम पर कुछ इतना बड़ा काम नहीं कर पा रहे, जो कि उन्हें पूरी तरह से तंदुरुस्त बनाता है। कुछ ऐसे ही कारणों को महसूस करके चिकित्सा क्षेत्र के एक बड़े समूह ने गहन अनुसंधान के बाद निर्णय लिया कि क्यों न हम अपनी पौराणिक प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिये उपचार की प्रक्रिया शुरू करें और देश को पूरी तरह से स्वस्थ बनायें।

लोगों के स्वास्थ्य हित की सोच के साथ लाइफस्टाइल बीमारियों की रोकथाम करने को गुरुग्राम में भारत देश का पहला फंक्शनल और बॉयो रेगुलेटरी मेडिसन सेंटर शुरू किया। डा. आलोक ने कहा कि वर्तमान समय में हम घर से लेकर बाहर तक रोजाना कई तरह की चीजों से अपने शरीर में किसी न किसी बीमारी को लगा लेते हैं और यह हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। इसे बदल भी नहीं सकते।

ऐसे में हमें अपने शरीर को इतना मजबूत बनाना होगा कि ये सब चीजें हमें प्रभावित न कर सकें। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को बदलने की सलाह देने के साथ प्राकृतिक चीजों से अधिक लगाव रखने की सलाह दी। खान-पान को लेकर उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स की चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी नहीं हैं। वे सिर्फ हम अपने स्वाद के लिए खाते हैं। इस सेंटर में जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के न सिर्फ लक्षणों का इलाज होगा, बल्कि उसकी जड़ से पहचान करके बीमारी को खत्म करके लोगों को सेहतमंद बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने देश के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक इस नई चिकित्सा पद्धति को लेकर कहा कि सरकार इसमें इतना सहयोग कर दे कि लोगों में जागरुकता है।

वे जानते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र के लोग अब उनके दुश्मन भी बन गये हैं। वे नहीं चाहेंगे कि इस तरह की पद्धति से लोगों का उपचार हो और उनकी दुकानें बंद हों। फिर भी उन्होंने कदम बढ़ाया है और इसमें सफलता लेकर रहेंगे।

हमारा लाइफस्टाइल भी बीमारियों का कारण : डा. बर्मन

इस मौके पर डा. आनंद बर्मन ने कहा कि हमें अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। जो जीवन हम अब जी रहे हैं, वह बहुत सही नहीं है। हमें प्रकृति की गोद में जाना होगा। यहां पर दी जाने वाले दवा रूपी उत्पाद पूरी तरह से प्राकृतिक होंगे। इनमें सप्लीमेंट भी शामिल होंगे। उन्हें डाबर समूह ही जमीन स्तर पर रिसर्च करके इजाद कर चुका है। करीब 50 उत्पाद जल्द ही आ जायेंगे। उन्हें विश्वास है कि देशवासी इस उपचार पद्धति के प्रति जागरूक भी होंगे और इसे ग्रहण भी करेंगे।

होने वाली बीमारियों का पहले ही होगा उपचार : संजय सचदेवा

शरीर खुद ही बीमारी को ठीक करने वाली प्रक्रिया के बारे में देवम वेलनेस के संस्थापक व सीईओ संजय सचदेवा कहते हैं कि विभिन्न टेस्ट के माध्यम से देवम व्यक्ति के सेहत और सभी तरह के महत्वपूर्ण डेटा का विश्लेषण करता है। इसके बाद ही इलाज का सुझाव दिया जाता है। व्यक्ति की सेहत की प्रगति को अनुभवी डॉक्टरों, पुरस्कृत सॉफ्टवेयर इलाज और प्रशिक्षित वेलनेस कोच द्वारा लगातार मॉनिटर किया जाता है। समय के साथ वे लोग खुद को स्वस्थ रखने के लिए सशक्त महसूस करते हैं। देवम में 30 अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं, जो दुनिया के लगभग 14 देशों में प्रेक्टिस और बॉयोलोजिकल रिसर्च कर रहे हैं। सेंटर में इलाज का तरीका कुछ ऐसा होगा कि जीवनशैली में बेहतरीन बदलाव करके भविष्य में होने वाली बीमारियों से बचा जा सके, ताकि लोग सेहतमंद जीवन बिता सकें।

शर्मिला टैगोर ने पटौदी महल से लॉन्च किया टीबी फ्री पटौदी अभियान

भारत को 2025 तक पूरी तरह से टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य

पायलेट प्रोजेक्ट का फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने किया आरंभ

मेदांता, केंद्र और राज्य के स्वास्थ्य विभाग भी हैं साथ-साथ

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

गुरुग्राम के खंड पटौदी स्थित पटौली महल में टीबी फ्री पटौदी अभियान की शुरुआत करतीं फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर।

भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता को लेकर मेदान्ता मेडिसिटी ने पहल नहल करते हुए टीबी फ्री हरियाणा का लक्ष्य लेकर मंगलवार को पटौदी इब्राहिम पैलेस में कार्यक्रम का आयोजन किया। हरियाणा को टीबी फ्री बनाने के लिए इंटरनेशनल यूनियन अगेन्स्ट ट्यूबरकुलोसिस एण्ड लंग डिजीज भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कलयाण मंत्रालय के केंद्रीय टीबी विभाग और हरियाणा सरकार के सहयोग से टीबी के निदान एवं उपचार के स्तर में सुधार लाने के लिए टीबी फ्री ब्लॉक पटौदी अभियान लॉन्च किया।

इस पायलेट प्रोजेक्ट सहितआधुनिक उपकरणों से लैस टीबी जांच एंबुलेंस का फिल्म अभिनेत्री शर्मिला टैगोर ने उद्घाटन किया। इस मौके पर मेदान्ता अस्पताल के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. नरेश त्रेहान ने कहा कि हर साल भारत में टीबी के साढ़े आठ लाख से अधिक रोगियों, पीड़ितों सहित मामलों का न तो निदान होता है और न ही उपचार होता है। यह देश, सरकार के साथ-साथ डाक्टरों के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है।

देश जीतेगा और टीबी हारेगा : शर्मिला टैगोर

शर्मिला टैगोर ने कहा कि पटौदी को सबसे पहले टीबी मुक्त बनाने के लिए पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चुनना, यहां के सभी ग्रामीणों सहित आम लोगों के स्वास्थ्य रहने की दिशा में सराहनीय पहल है। उन्होंने इस बात सहित लक्ष्य की भी सराहना की कि पटौदी को अगले छह माह में पूरी तरह से टीबी मुक्त बना दिया जाएगा। शर्मिला ने अभियान के लोगो-नारे देश जीतेगा और टीबी हारेगा को भी कई बार बोलकर सभी को प्रेरित किया। एमसीजी गुरुग्राम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. ब्रह्मदीप संधु ने कहा कि टीबी, कैंसर या किसी भी गंभीर और ला-इलाज माने जाने वाले रोग से पीड़ित के स्वस्थ होने के बाद में संबंधित व्यक्ति के बारे में भी समाज को अवगत कराना चाहिये, इससे लोगों में जागरूकता ही आयेगी। इस मामले में क्रिकेटर युवराज एक अनुकरणीय नजीर सभी के सामने हैं। ऐसे ही और भी आम आदमी सहित बड़े सेलिब्रटी हैं, जिनके बारे में बताकर जागरूक सहित प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

हरियाणा में 25 हजार मरीजों की स्क्रीनिंग

मेदांता अस्पताल के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विख्यात श्वांस रोग के विशेषज्ञ डॉ. बोरनाली दत्ता ने कहा कि भारत को टीबी मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता के साथ हम पिछले छह सालों में अपने मिशन टीबी फ्री हरियाणा के माध्यम से 25000 मरीजों की स्क्रीनिंग कर चुके हैं। मिशन टीबी फ्री पटौदी के दोहरे लक्ष्य हैं- अगले दो वर्षों में ब्लॉक से टीबी का उन्मूलन करना और ऐसा प्रभावी मॉडल बनाकर साबित करना जिसे देश भर में अपनाया जा सके।

विश्व का सबसे बड़ा है भारतीय संविधान : प्रदीप चौधरी

गुरुग्राम। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा न्यायालय परिसर के मीडिएशन हॉल में संविधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर उपस्थित पैनल अधिवक्ताओं, पैरा लीगल वालंटियरों तथा स्टाफ के अन्य सदस्यों ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस अवसर पर जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी प्रदीप चौधरी ने कहा कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था।

हमारे देश के संविधान की रचना बाबा साहिब भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा की गई थी। हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 448 अनुछेद, 12 अनुसूचियां तथा 101 संशोधन किए गए। यह हस्त लिखित संविधान है और जिसे तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था।

सरकार ने 19 नवंबर 2015 को राजपत्र अधिसूचना की सहायता से 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया। उन्होंने कहा कि आज हम सब संविधान दिवस मना रहें हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को चलाने के लिए नियमों का होना अत्यंत आवश्यक है। संविधान के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि संविधान का अभिप्राय किसी भी देश के मुख्य कानून से है जिसकी पालना वहां रहने वाले लोगों को करनी होती है।

पत्नी की हत्या के आरोपी पति को उम्रकैद

गुरुग्राम। पत्नी की हत्या कर देने के मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर पति को दोषी करार देते हुए उम्रकैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत वर्ष 13 अप्रैल को जिले के मुमताजपुर गांव में एक महिला की हत्या का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। खुद पति हरिओम ने पुलिस कंट्रोल रुम में फोन कर बताया था कि उसने घरेलू झगड़े के दौरान अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। अभियोजन पक्ष ने अदालत के सामने वह ऑडियो टेप पेश किया, जिसमें हरिओम पुलिस कंट्रोल रुम में कॉल कर बता रहा है कि उसने अपनी पत्नी का काम तमाम कर दिया है। यह विशेष है कि पुलिस कंट्रोल रुम में काम करने वालों की बातचीत ऑटोमैटिक रिकॉर्ड हो जाती है।

अवैध कॉलोनी काटने का मामला दर्ज किया

सोहना। डीटीपीओ ने भोंडसी थाना में नया गांव निवासी प्रॉपर्टी डिलर के खिलाफ भोंडसी में अवैध कॉलोनी काटने का मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू कर दी है। डीटीपीओ गुरूग्राम ने भोंडसी थाना में नया गांव निवासी देवराज निवासी के खिलाफ भोंडसी सीमा क्षेत्र की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। डीटीपीओ ने पुलिस को बताया कि उक्त जमीन सेक्शन-7ए में आती है। जहां पर प्लाटिंग करना गैरकानूनी है। लेकिन आरोपी ने कानून की अवहेलना करते हुए कॉलोनी काटी। जिसका न तो उनके विभाग से अनुमति ली गई। न ही अन्य कानूनी कार्यवाही की गई। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्वीत कुमार ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया है। जिसकी जांच शुरू कर दी है।

सामूहिक प्रयास से होगा आतंकवाद खत्म: आरएल शर्मा

गुरुग्राम। आज के परिवेश में आतंकवाद बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है, जिसे सामूहिक प्रयास से ही खत्म किया जा सकता है। यह बात पुलिस शहीद फाऊंडेशन हरियाणा के अध्यक्ष एडवोकेट आरएल शर्मा ने मंगलवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले की 11वीं बरसी पर शहीद हुए पुलिस, सेना और आमजन के लिए आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में कही। पुलिस शहीद फाउंडेशन हरियाणा द्वारा आयोजित स्वतंत्रता सेनानी हॉल के शहीद स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के मौके पर आरएल शर्मा ने कहा कि हमें सदैव शहीदों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि शहीदों की वजह से ही आज हम सुरक्षित हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित हैं और पूरा देश चैन की नींद इन्हीं शहीदों की बदौलत ले रहा है। इसलिए शहीदों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है।

उन्होंने कहा कि आज ही के दिन वर्ष 2008 में भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई पर पाकिस्तान के आतंकी समूह लश्करे-तैयबा द्वारा लगभग एक दर्जन आतंकवादियों को नरसंहार करने के लिए भेजा गया था, जिसमें मुंबई का ताज होटल मुख्य केन्द्र रहा। अचानक हुए इस आतंकी हमले के दौरान अपने कर्तव्य का पालन करते हुए और आतंकवादियों से लड़ते हुए पुलिस और सेना के काफी जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे।

संक्षिप्त समाचार

गुरुग्राम विश्वविद्यालय में मनाया संविधान दिवस

गुरुग्राम। मंगलवार को गुरुग्राम विश्वविद्यालय में संविधान दिवस मनाया गया। 70वें संविधान दिवस पर संसद के सेंट्रल हॉल में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का सीधा प्रसारण गुरुग्राम विश्वविद्यालय के परिसर में छात्रों को दिखाया गया। इस बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। जिसे विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद सैंकड़ों छात्र-छात्राओं ने सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद मौजूद छात्रों ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी ने मूल कर्तव्यों की बात की है चाहे वो पानी की एक-एक बूंद बचाने की बात हो या वातावरण स्वच्छ बनाने की, इन छोटे-छोटे कर्तव्यों को निभा कर भी हम भारतीय नागरिक होने की भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही गुरुग्राम विश्वविद्यासय के कुलपति डॉ. मार्कंडेय आहूजा ने संविधान निर्माता डॉ. भीम राव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कुलपति ने कहा कि जैसे हमारे लिए हमारे ग्रंथ, वेद, पुराण, बाइबल, गीता है वैसे ही हमारा संविधान भी हमारा ग्रंथ है। हमारा संविधान समता मूलक समाज की स्थापना की बात करता है। कानून विभाग के अध्यक्ष डॉ. बदरुद्दीन ने संविधान के जीवन में महत्व और मूल अधिकारों के बारे में बताया। इस दौरान गुरुग्राम विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू डॉ. अमन वशिष्ठ, डॉ. तरुण ढूल, डॉ. सुमन वशिष्ठ, डॉ. वंदना हांडा, डॉ. नवीन गोयल, डॉ. धीरेंद्र, डॉ. नीलम समेत कई अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

गीता महोत्सव को लेकर गुरुग्राम में भी होंगे कार्यक्रम

गुरुग्राम। हरियाणा सरकार की ओर से कुरुक्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव को गरिमापूर्ण व भव्य रूप से मनाया जा रहा है। गुरुग्राम में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का आयोजन छह से आठ दिसंबर को किया जाएगा, जिसमें गीता पर सेमीनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम व नगर शोभायात्रा जैसे कार्यक्रम होंगे। उपायुक्त अमित खत्री मंगलवार को अपने कार्यालय में मासिक पत्रकार वार्ता के दौरान जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों व गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। श्री खत्री ने कहा कि गीता महोत्सव में समाज के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गीता महोत्सव में नगर कीर्तन, शोभा यात्रा सहित कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि इसके उद्देश्य को सफल किया जा सके। श्री खत्री ने कहा कि नई प्रतिभाओं को निखारने के उद्देश्य से गुरुग्राम में कलाग्राम सोसायटी के गठन का निर्णय लिया गया है, जिसके माध्यम से सेक्टर-29 स्थित ओपन एयर थियेटर, जान हॉल आदि स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, ताकि गुरुग्राम को एक अलग पहचान मिल सके।

पैरोल पर गया कैदी नहीं लौटा, मामला दर्ज

सोहना। भोंडसी जिला जेल अधिकारी ने गैरहाजिर चल रहे कैदी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। कैंदी दस दिन की परौल छुट्टी पर गया था। आरोपी कैदी उम्रकैद की सजा काट रहा है। जिला जेल के उपाधीक्षक दिनेश कुमार ने पुलिस को बताया कि कैदी कपिल निवासी गांव उमरा बुर्जस थाना शिवाला कला जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। जो 21 से 30 अक्टूबर तक छुट्टी पर गया था। बाद में कैदी को 15 नवंबर तक जेल में वापस आने की हिदायत दी गई थी, लेकिन अभी तक नहीं लौटा तो उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। जिला जेल के उपाधीक्षक दिनेश कुमार ने बताया कि कपिल जो उम्रकैद की सजा काट रहा है।

30 को होगा सक्षम प्लस के तहत अंग्रेजी का पेपर

सोहना। सोहना खंड के 50 राजकीय स्कूलों में सक्षम प्लस के तहत अंग्रेजी विषय का पेपर होगा। परीक्षा में कक्षा तीन से आठ तक के विद्यार्थी बैठेंगे। सोहना के कार्यवाहक खंड शिक्षा अधिकार अनिल मेहता ने बताया कि शनिवार को खंड के 50 राजकीय स्कूलों में विद्यार्थी समक्ष प्लस के तहत अंग्रेजी विषय की परीक्षा देंगे। परीक्षा को लेकर खंड के सभी 120 राजकीय स्कूलों में जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। ताकि परीक्षा सफल हो। उन्होंने बताया कि सभी स्कूलों प्रभारियों और अंग्रेसी विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के लिए भी अवसर प्रदान किया है।

पुलिस हिरासत में से भागने वाला आरोपी गिरफ्तार

सोहना। पुलिस ने 13 दिन पहले हिरासत के दौरान हवलदार को धक्का मारकर भागने वाले वाहन चोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 12 नवंबर की रात को सोहना के दौला मार्ग पर चार चोरी करने के दौरान हवा में फायरिंग भी की थी। सोहना सिटी थाना पुलिस को आखिर 13 दिन तक कड़ी मशक्कत के बाद हिरासत के दौरान भागने वाले वाहन चोर सकील निवासी गांव रिठड थाना नगीना जिला नूंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सकील 12 नवंबर को सोहना सिटी थाना के मैन गेट पर पुलिस हिरासत के दौरान हवलदार को धक्का मारने के बाद बाजार की तंग गलियों और भीड़ का फायदा उठाते हुए फरार हो गया था। मामले की जांच कर रहे एसआई वेदपाल ने बताया कि गिरफ्तार बदमाश को मंगलवार दोपहर बाद अदालत में पेश किया। अदालत ने आरोपी को एक दिन की रिमांड पर भेज दिया है।

युवा कलाकारों के कला-कौशल के कायल हुए श्रोता

15वां सामापा संगीत सम्मेलन

पायनियर समाचार सेवा। नई दिल्ली

दिल्ली का वार्षिक एवं लोकप्रिय शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, पांच दिवसीय 15वां सामापा संगीत सम्मेलन सप्ताहअंत में सम्पन्न हुआ। सोपोरी अकादमी ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स (सामापा) द्वारा अतुल्य भारत (इंक्रेडिबल इंडिया), पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार एवं इफ्को के सहयोग से आयोजित वार्षिक सामापा संगीत सम्मेलन में इस वर्ष भी युवा एवम् दिग्गज कलाकारों के कार्यक्रम आयोजित किये गये थे।

इन कलाकारों में दीपक सहाय (तबला), पियू मुखर्जी (गायन), हफीज बले खान एवं रइस खान (सितार), वसीम अहमद भट्ट (गायन), देवास्मिता भट्टाचार्य (सरोद), और रूचिरा पांडा (गायन) की प्रस्तुतियां इंडिया हैबीटेट सेंटर में आयोजित की गयी। जिसके उपरातं कमानी सभागार में सामापा अवार्ड, अजय पोहनकर (गायन), पंडित भजन सोपोरी (संतूर), विशम्भर नाथ मिश्रा (पखावज), विदूषी मालिनी अवस्थी (गायन), एवं संतूर वादक व कम्पोज़र अभय रूस्तुम सोपोरी, पं. विजय शंकर मिश्रा के नेतृत्व मे स्वर-लय-संवाद, कौशल दास (सितार) और नलिनी कमलिनी (नृत्य) के प्रस्तुतिकरण आयोजित किये गये। मंच संचालन की जिम्मेदारी मुनीश जौली एवम् प्रसिद्ध मीडिया कर्मी व एंकर साधना श्रीवास्तव ने संभाली। पांचों ही दिनों की शुरूआत पारम्परिक द्वीप प्रज्जवलन एवं स्कूली बच्चों द्वारा प्रस्तुत सरस्वती वंदना से हुई। जिसके बाद पहले दो दिन उभरते व युवा कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से उपस्थित दर्शकों व मेहमानों को प्रभावित किया और वाह-वाही लूटी और बाकी के तीन दिनों में स्थापित कलाकारों ने अपने अद्भुत प्रदर्शन से दिल्लीवासियों के बीच संगीत रस बिखेरा। सभी कलाकारों ने अपने घरानों की विशेषताएं और उससे जुड़ी नई सोच प्रस्तुत की।

कार्यक्रम के दौरान एक विशिष्ट आयोजन में लगभग 13 साल बाद भारत के तबला के घराने से 6 तबला वादकों ने अपने संबंधित घरानों की विशिष्टताएं प्रस्तुत की। पंडित विजय शंकर मिश्रा के संयोजन में इस प्रस्तुति के माध्यम से तबला की नई चीजें एवं नई सोच प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया। संकटमोचन मंदिर वाराणसी के 'महंत' पंडित विश्म्भर नाथ मिश्रा के एकल पखावज दिल्ली में उनका पहला प्रदर्शन था। प्रख्यात कलाकार मालिनी अवस्थी ने अपेक्षा अनुरूप संगीत लहरियों से दर्शकों व श्रोताओं को गिरफ्त में लिया।

छात्राओं ने दिया स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ भारत, जल संरक्षण का संदेश

गुरुग्राम के सेक्टर-14 स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय में स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण को लेकर स्लोगन दिखातीं छात्राएं।

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

अंबालाल साराभाई के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर हुआ कार्यक्रम

राजकीय कन्या महाविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने सीनियर अंडर ऑफिसर अंजू जनग्रा के नेतृत्व में स्लोगन व पोस्टर्स के माध्यम से दिया स्वच्छ ऊर्जा, स्वच्छ भारत, जल संरक्षण का संदेश।

इस कार्यक्रम का आयोजन न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत सरकार उपक्रम द्वारा देश के महान वैज्ञानिक विक्रम अंबालाल साराभाई के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर किया गया।

इस अवसर पर महाविद्यालय की प्राचार्य विजय अदलखा ने कहा कि देश भर में महान वैज्ञानिक व भारत विज्ञान जगत के पितामह विक्रम अंबालाल साराभाई की जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है।

इसी क्रम में छात्राओं ने विक्रम साराभाई के पोस्टर्स बनाकर उनकी उपलब्धियों को दर्शाया तो दूसरी तरफ स्लोगन के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और स्वच्छ भारत, सुन्दर भारत को संदेश देने का प्रयास किया।

स्तन कैंसर की समय पर पहचान के लिए जागरुकता जरूरी

हर साल दर्ज हो रहे 1,62,428 नए मामले

पायनियर समाचार सेवा। गुरुग्राम

दुनिया और भारत में स्तन कैंसर की घटनाओं में तेजी आई है। स्तन कैंसर से हर साल दुनिया में 21 लाख महिलाएं पीड़ित होती हैं और भारत में हर साल इसके 1,62,428 नए मामले दर्ज हो रहे हैं। महिलाओं में कैंसर से होने वाली कम से कम 12 फीसदी मौतें इस खतरनाक बीमारी से होती हैं।

स्तन कैंसर के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए अग्रणी ऑन्कोलॉजिस्ट, डॉ. आकाश कुमार, असिस्टैंट प्रोफेसर, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, नेषनल कैंसर इंस्टीट्यूट, झज्झर ने कहा कि स्तन कैंसर की दर भारत में खासकर तीस साल के शुरुआती चरण की महिलाओं में बढ़ रही है। 2018 में भारत में 87,090 महिलाओं की मौत स्तन कैंसर से हुई। यह भारतीय शहरों में स्वास्थ्य की एक बढ़ी समस्या बन गया है। 2030 तक स्तन कैंसर के कारण होने वाली महिलाओं की मौत की संख्या किसी भी अन्य कैंसर से होने वाली मौतों के मुकाबले बहुत ज्यादा हो जाएगी। यदि स्तन कैंसर की पहचान समय रहते कर ली जाए, तो मरीज के बचने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगर पहचान में देर हो जाती है तो मरीज के बचने की संभावना भी कम होती जाती है। स्तन कैंसर पूरी दुनिया में महिलाओं में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है, लेकिन फिर भी स्तन कैंसर के कारणों के बारे में जानकारी व समझ बहुत कम है। स्तन कैंसर के अनेक कारण हो सकते हैं। ये व्यक्ति के जींस एवं जीवनशैली पर निर्भर हो सकते हैं।

डॉ. आकाश कुमार ने कहा, स्तन कैंसर के लगभग 50 फीसदी मरीज निदान के पांच सालों से ज्यादा जीवित नहीं रह पाते। भारत में स्तन कैंसर अन्य देशों के मुकाबले अलग है। यहां पर स्तन कैंसर से युवा महिलाएं पीड़ित हो रही हैं और उनमें से आधी से ज्यादा महिलाओं में कैंसर एडवांस्ड स्तर तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम में कैंसर की रोकथाम व नियंत्रण के लिए, डायबिटी, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों एवं स्ट्रोक (एनपीसीडीसीएस), आम कैंसर यानि ओरल, स्तन एवं कर्विकल की रोकथाम, जांच व स्क्रीनिंग के लिए कार्यक्रम 150 से ज्यादा जिलों में क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इस अभियान का उद्देष्य न केवल इस बीमारी की समय पर पहचान करना, बल्कि इसके कारणों के बारे में जागरुकता बढ़ाना भी है। देश में मौजूदा सत्ताइस क्षेत्रीय कैंसर सेंटर कैंसर के इलाज की विस्तृत सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं और कैंसर की रोकथाम एवं शोध की गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं।

दोस्तों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या के बाद सिर कुचला

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

मृतक संदीप

सोतई गांव निवासी एक प्रोपर्टी डीलर का बीती रात कुछ दोस्तो से विवाद हो गया। आरोपियों ने तेज धारदार हथियार से ताबड़ तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी और मृतक की पहचान छिपाने के लिए आरोपियों ने कार का पहिया चढ़ाकर उसका सिर कुचल दिया। शव को आईएमटी में चंदावली गोल चक्कर के पास फेंकेकर आरोपी फरार हो गए। सुबह मामले का पता चलने पर पुलिस ने शव को बीके अस्पताल भिजवाने के बाद जांच शुरू कर दी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों ने दोपहर को बाईपास रोड पर चंदावली पुल के पास जाम लगा दिया। पुलिस द्वारा एक आश्वासन दिए जाने के बाद परिजनों ने करीब एक घंटे बाद जाम खोल दिया।

क्या है मामला : आईएमटी के निकटवर्ती ग्रामीण युवक मंगलवार सुबह दौड़ लगाने गए थे। युवकों ने देखा कि चंदावली गोल चक्कर के पास एक युवक का शव पड़ा हुआ है। तेज धारदार हथियार से हत्या करने के बाद शव का सिर कुचला हुआ था। घटना का पता चलते ही मौके पर लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई। लोगों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करवाने के प्रयास शुरू कर दिए। उधर सोतई गांव निवासी 25 वर्षीय संदीप के रात भर घर न पहुंचने की वजह से उसके पिता रघुवीर और अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए। शव को देखते ही उन्होंने मृतक की पहचान संदीप के रूप में कर दी।

घर से बुलाकर ले गया आरोपी

मृतक संदीप के ताऊ विजयपाल ने बताया कि प्रोपर्टी डीलिंग का काम करने वाले संदीप का एक साल पहले विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई है। इसी गांव करा धर्मेन्द्र उर्फ लाला बीती शाम संदीप को घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था। रात को परिजनों द्वारा फोन करने पर संदीप ने धर्मेन्द्र के साथ मौजूद होने की बात कही। संदीप की हत्या का पता चलने पर परिजन धर्मेन्द्र के घर पहुंचे, तो वह फरार हो चुका था। घर में खड़ी हुई उसकी सेंट्रो कार को कुछ समय पहले ही धोया गया था। इसके बावजूद कार में खून के निशान रह गए थे, जिससे परिजनों का संदेह बढ़ गया। उन्होंने धर्मेन्द्र पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत दी।

चंदावली पुल के पास परिजनों ने लगाया जाम

इस हत्याकांड को लेकर मृतक संदीप के परिजनों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। गुस्साए परिजनों ने दोपहर करीब एक बजे बाईपास रोड पर चंदावली पुल के पास जाम लगा दिया। परिजन आरोपी धर्मेन्द्र और उसके साथियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे। जाम लगाने के दौरान गुस्साए लोग पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे। सूचना मिलने पर एसीपी सिटी जयवीर राठी, थाना सदर प्रभारी नरेंद्र सिंह और थाना आदर्श नगर प्रभारी सुदीप कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने के प्रयास शुरू कर दिए।

पुलिस द्वारा आश्वासन मिलने पर खोला जाम

जाम के दौरान वाहनों की भीड़ लगने से रोकने के लिए पुलिस ने सेक्टर दो से सेक्टर 64 की तरफ रूट डायवर्ट कर दिया। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को बताया कि उन्होंने धर्मेन्द्र उर्फ लाला को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ कर अन्य आरोपियों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हो गया और उन्होंने जाम खोल दिया। पुलिस ने मृतक के पिता की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से कार के परखच्चे उड़े, एक की मौत

एक घायल

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

मृतक देवेंद्र बैंसला

ओल्ड फरीदाबाद के फ्लाईओवर पर तेज रफ्तार से दौड़ रहे किसी अज्ञात वाहन ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससेकार के बुरी तरह से परखच्चे उड़ गए। दुर्घटना में कार सवार दो युवक अंदर फंस गए, जिन्हें पुलिस ने किसी तरह बाहर निकाल कर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। इनमें से एक युवक को डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने फिलहाल अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

थाना ओल्ड फरीदाबाद में दर्ज मामले के मुताबिक बल्लभगढ़ की श्याम कॉलोनी में तेजबीर बैसला का परिवार रहता है। उनके बेटे देवेंद्र बैंसला शहर में ही अपना कामधंधा करते थे। जबकि छोटा बेटा प्रवीन पेशे से अधिवक्ता है। बताया गया है कि गतदिवस उनके किसी परिचित की शादी की रिसेप्शन पार्टी थी। उसमें शामिल होने के लिए देवेंद्र व प्रवीन एसएक्स-4 कार पर अनंगपुर गांव के पास स्थित मैरिज गार्डन गए और पार्टी से देर रात घर लौट रहे थे। रात करीब 12 बजे के आस-पास दोनों ओल्ड फरीदाबाद फ्लाईओवर से गुजर रहे थे। तभी किसी तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

राहगीरों की सूचना पर थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त कार से किसी तरह दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जहां जांच के बाद डाक्टरों ने देवेंद्र को मृत घोषित कर दिया। शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान पुलिस को मौके से टक्कर मारने वाले वाहन की नंबर प्लेट मिली है, जिसके आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है।

डीएवी कॉलेज के आदित्य बने भारतीय युवा राजदूत

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

एनएच तीन स्थित डीएवी शताब्दी कॉलेज से हरियाणा नेवल यूनिट एनसीसी कैडेट आदित्य राज का सिंगापुर में आयोजित दस दिवसीय यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैंप के अंतर्गत भारतीय युवा राजदूत के रूप में चयन किया गया। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए चयनित होने के उपरांत 17 डायरेक्टरेट में से नेवी विंग के ऑल इंडिया 17 बेस्ट कैडेट्स के बीच एक प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ डायरेक्ट के कैडेट्स ने भाग लिया। कैडेट आदित्य राज ने पांचवीं रैंक हासिल कर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किया। सिंगापुर कैंप के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अंतरराष्ट्रीय कैंप में भाग ले रहे एनसीसी कैडेट्स का मनोबल बढ़ाया।

राजनाथ सिंह ने व्यक्तिगत रूप से आदित्य राज को प्रोत्साहित करते हुए भारतीय सेना ज्वाइन करने के लिए मजबूती से तैयारी करने के लिए प्रेरित किया। दस दिवसीय यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैंप सिंगापुर में भारत, यूएसए, यूके, नेपाल, हांगकांग, सिंगापुर सहित छह देशों से आए कैडेट्स ने भी भाग लिया। भारत की ओर से चयनित 10 कैडेट में से हरियाणा प्रदेश के डीएवी शताब्दी कॉलेज के कैडेट आदित्य राज का चयन होना पूरे कॉलेज के साथ प्रांत और जिले के लिए एक बहुमूल्य उपलब्धि है।

सूदखोरों से परेशान व्यवसायी ने लगाई फांसी

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

एनआईटी के तिकोना पार्क में दुकान चलाने वाले एक व्यवसायी ने मंगलवार सुबह अपनी दुकान के पिछले हिस्से में जाकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मृतक के पास एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने इलाके के कुछ सूदखोरों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। सूदखोर मृतक पर लगातार दबाव बना रहे थे।

थाना कोतवाली में दर्ज मामले के मुताबिक जवाहर कॉलोनी निवासी महेंद्र भारद्वाज तिकोना पार्क में एमआर बेट्री के नाम से बेट्री और इनवर्टर मरम्मत की दुकान चलाता था। मंगलवार सुबह महेंद्र दुकान में साफ-सफाई के बाद पिछले हिस्से में चला गया। जहां वेंटीलेशन के लिए लगाई गई ग्रिल पर उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कुछ देर बाद कोई ग्राहक दुकान पर आया और महेंद्र को न पाकर पिछले हिस्से में गया, तो उसके होश उड़ गए। उस व्यक्ति के बताने पर वहां लोगों की भीड़ लग गई।

सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। तलाशी के दौरान पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए इलाके के कुछ सूदखोर को जिम्मेदार ठहराया है। मृतक के परिजनों का आरोप है कि महेंद्र ने कई लोगों से रुपये उधार लिए हुए थे। महेंद्र काफी समय से ब्याज और मूल रकम उन्हें वापस लौटा रहा था, लेकिन सूदखोर अपनी रकम लगातार बढ़ते जा रहे थे। रुपयों के लिए सूदखोर कई बार महेंद्र के साथ दुर्व्यवहार भी कर चुके थे। इसी परेशानी की वजह से उसने अपनी जान दी है। शव पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।

राजमिस्त्री ने फांसी लगाकर की आत्महत्या

डबुआ कॉलोनी के आशियाना फ्लैट में रहने वाले एक व्यक्ति ने बीती रात अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। थाना डबुआ कॉलोनी पुलिस के मुताबिक आशियाना फ्लैट निवासी विजय राजमिस्त्री था। वह कुछ समय से अज्ञात कारणों से परेशान चल रहा था और उसने शराब पीनी शुरू कर दी थी। परिवार के लोगों ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद उसकी परेशानी कम नहीं हुई। अन्य दिनों की तरह बीती शाम भी वह काम से घर लौट आया था। देर रात को उसने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले का पता चलते ही परिजनों ने पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंप दिया है।

श्री श्याम बाबा सेवा ट्रस्ट ने वितरित किए पौधे

बल्लभगढ़। श्री श्याम बाबा सेवा ट्रस्ट ने कल्पना चावला सिटी पार्क में पौधा वितरण शिविर लगा कर प्रात:कालीन भ्रमण के आये हुये लोगों को पौधे वितरित किये।

ट्रस्ट के प्रधान गोपाल गोयल ने लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुये कहा कि पौधे लगा कर वातावरण को शुद्ध करना चाहिये। हम जितने ज्यादा से ज्यादा पौधे लगायेंगे। उससे हम बीमारियों को दूर भगा सकते हैं और कहा कि ट्रस्ट समय-समय पर सामाजिक कार्यों में अपना योगदान देता रहता है और ट्रस्ट द्वारा चेकअप शिविर, रक्तदान शिविर भी लगाता है। इस अवसर पर इस कार्य में उनके साथ ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी दिनेश देशवाल, अमित मित्तल नीरज सिंगला, दीपक ठाकुर अमित गोयल, संजीव त्यागी, अनिल वशिष्ठ आदि ने अपना पूरा सहयोग दिया।

'आरक्षण को बने राष्ट्रीय समीक्षा आयोग'

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

दलित चिंतक एवं डॉ. बीआर अंबेडकर एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन ओपी धामा ने प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को पत्र लिख कर मांग की है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को जातिगत आधार पर दिए गए आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं के प्रति समाज में फैली भ्रांतियों को दूर करने की आवश्यकता है। आरक्षण तथा अन्य सुविधाओं के लाभ की पहुंच आखिर 70 साल बाद भी इस अपेक्षित-वंचित समाज तक क्यों नहीं पहुंच सकी। इसके मद्देनजर केंद्र सरकार एक राष्ट्रीय समीक्षा आयोग का गठन करें।

ओपी धामा मंगलवार को बौद्ध विहार स्थित डॉ. बीआर अंबेडकर शिक्षण संस्थान के सभागार में पत्रकारवार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्रीय समीक्षा आयोग यह समीक्षा करें के आरक्षण का लाभ इन वर्गों को अभी तक क्यों नहीं मिला। इसके क्या कारण रहे हैं। इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं तथा निर्धारित आरक्षण कैसे इन वर्गों तक शीघ्र अति शीघ्र पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय समाज जाति आधारित समाज है, यहां अनेक जातियां हैं। इनमें से कई ऐसी जातियां हैं जो ऐतिहासिक कारण, अवसरों के अभाव में पिछड़ गईं, इन्हीं कारणों से भारत के संविधान में राष्ट्र के सर्वांगीण विकास, सामाजिक ताना-बाना को बनाए रखने और सामाजिक समरसता कायम रखने के लिए वंचित तबके को भी प्रगति की राह पर लाने के लिए संविधान में अतिरिक्त सहूलियत दी गई थी, लेकिन आजादी के 70 वर्ष बाद भी आरक्षण एवं अन्य सुविधाओं का लाभ लोगों तक अभी तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा कि सौ नौकरियों में, साढ़े सात प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं, 15 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों के लिए है, 27 प्रतिशत आरक्षण पिछड़ा वर्ग के लिए है, जिसका टोटल साढे 49 प्रतिशत बनता है। जबकि इन वर्गों की कुल आबादी 80 प्रतिशत से ऊपर है। बकाया साढ़े 50 प्रतिशत आरक्षण सामान्य वर्ग के लिए है, जिनकी जनसंख्या 20 प्रतिशत से कम है। अर्थात 20 प्रतिशत लोगों के पास सरकारी नौकरियों में साढे 50 प्रतिशत आरक्षण है और अन्य जातियों के लिए जिनकी आबादी 80 प्रति है। इनको साढ़े 49 प्रतिशत आरक्षण है। यह केवल कुछ सरकारी नौकरियों में है।

ट्रांसफार्मर में धमाके से रबड़ कंपनी में लगी भीषण आग

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

एनएच 3जी ब्लॉक स्थित एक रबड़ कंपोनेंट बनाने और रबड़ कोटिंग करने वाली कंपनी के बाहर लगे ट्रांसफार्मर में मंगलवार दोपहर को तेज धमाका हो गया। धमाका होते ही कंपनी में शॉट सर्किट की वजह से आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंच कर आग पर किसी तरह काबू पाया। इस घटना में लाखों रुपये का माल जलकर राख हो गया है।

एनएच 3जी ब्लॉक स्थित एक रबड़ कंपोनेंट बनाने और रबड़ कोटिंग करने वाली कंपनी हैं। कंपनी के ठीक सामने बिजली निगम का एक ट्रांसफार्मर लगा है। ट्रांसफार्मर से कंपनी के अंदर बिजली की लाइन जा रही है। मंगलवार को एक गिलहरी इस ट्रांसफार्मर पर चढ़ी, जिससे जम्फर टूटा और ट्रांसफार्मर में तेज धमाका हो गया। धमाके की वजह से कंपनी में शार्ट सर्किट होने पर चिंगारियां वहां रखे रबड़ के सामान पर जा गिरी और आग लग गई।

देखते ही देखते आग तेजी के साथ फैलनी शुरू हो गई। थोड़ी ही देर में आग ने भयानक रूप धारण कर दिया। कंपनी प्रबंधकों की सूचना पर फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए। पानी की बौछार से सफलता न मिलने पर आग पर फॉम कैमिकल डाला गया। तब आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। घटना के दौरान कंपनी के ज्यादातर कर्मचारी भोजन अवकाश के लिए बाहर आए हुए थे। इसलिए किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ है। आग से हुए नुकसान का अभी आकंलन नहीं किया गया है।

हुडा ने बाईपास रोड पर 15 ठेके किए सील

फरीदाबाद। एनजीटी के आदेशों की अनुपालन में हुडा के प्रवर्तन दस्ते ने मंगलवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर ग्रीन बेल्ट पर बने शराब के 15 ठेकों को सील कर दिया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने प्रशासन और स्थानीय निकायों को ग्रीनबेल्ट पर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। उसी के तहत हुडा के एसडीओ धर्मवीर वर्मा, जेई शैलेंद्र और गांग राम ने यह कार्रवाई की है। इसके तहत बाईपास पर बदरपुर बार्डर से लेकर सेक्टर 59 तक ग्रीन बेल्ट पर बने शराब के 15 ठेकों को सील कर दिया। यदि सील तोड़ी गई, तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

औद्योगिक सुरक्षा उपनिदेशक का स्वागत

पायनियर समाचार सेवा। फरीदाबाद

औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के उप निदेशक धर्मेंद्र सिंह का फरीदाबाद में कार्यभार संभालने पर टाइम इक्विपमेंट प्राल्कि के डायरेक्टर आरके चिलाना, ईपी इलेक्ट्रो प्रेसिंग प्राल्कि के डायरेक्टर विष्णु गोयल और आरके गोयल ने फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया और उम्मीद जताई कि उनके यहां आने से फरीदाबाद के औद्योगिक संगठनों को और मजबूती मिलेगी।

आर.के. चिलाना ने कहा कि फरीदाबाद के औद्योगिक संगठन सदैव प्रशासन के साथ तालमेल बिठाकर सामाजिक व अन्य कार्यों में अपनी भूमिका निभाते हैं और उद्योगों को विकसित होने के लिए एक ईमानदार ऑफिसर्स की अत्यंत आवश्यकता होती है और उन्हें उम्मीद है कि धर्मेन्द्र सिंह यहां के उद्योगों को पूरी तरह से अपना सहयोग प्रदान करेंगे। आरके चिलाना ने कहा कि फरीदाबाद की विभिन्न इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ वह जल्द मीटिंग करके कोई भी फैक्टरी एक्ट से संबंधित पेंडित कार्य है, उसे समयबद्ध से पूरा करवाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जैसे ईमानदार सीएम की अध्यक्षता में प्रदेश में जो सरकार चल रही है, उससे उद्योगों को नई दिशा मिल रही है।

उप निदेशक धर्मेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया कि वह अपने विभाग के साथी अधिकारियों के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंटस से मीटिंग करेंगे और यदि कोई भी पेंडिंग काम होंगे, उसे जल्द से जल्द पूरा करवाएंगे और उद्योगों को आगे बढ़ाने में हरसंभव सहयोग देंगे।

फॉर्म नंबर URC-2
अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 374 (बी) और कम्पनी (पंजीकृत करने के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अर्न्तगत)
1. सूचना यह दी गई है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार CRC, मानेसर हरियाणा में एक आवेदन किया गया है कि "दादरी आईटी सर्विसेज एलएलपी" एलएलपी को कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय-XXI भाग-1 के अन्तर्गत एक शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी की प्रमुख वस्तुएं सभी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी प्रदान करना है।
3.मैमोरेडम ज्ञापन की एक प्रति और प्रस्तावित कंपनी के संघ के लेख कार्यालय 3993-ए/1, पहली मंजिल, रघु गनी, चावड़ी बाजार, दिल्ली में निरीक्षण किया जा सकता है।
4. सूचना यह दी गई है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने पंजीकृत कार्यालय में कंपनी को एक प्रति के साथ, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार CRC, मानेसर हरियाणा को लिखित रूप में अपनी आपत्ति को सूचित कर सकता है। दिनांक – 26/11/2019
आवेदक का नाम: **दादरी आईटी सर्विसेज एलएलपी**
पार्टनर :
गिरधारी लाल गुप्ता, अनिल गुप्ता,
स्नेह प्रभा गुप्ता

फॉर्म नंबर URC-2
अध्याय XXI के भाग I के तहत पंजीकरण के बारे में सूचना देने वाला विज्ञापन
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 374 (बी) और कम्पनी (पंजीकृत करने के लिए अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अर्न्तगत)
1. सूचना यह दी गई है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उप-धारा (2) के अनुसरण में रजिस्ट्रार CRC, मानेसर हरियाणा में एक आवेदन किया गया है कि "दादरी फूड्स एलएलपी" एलएलपी को कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय – XXI भाग-1 के अन्तर्गत एक शेयरों द्वारा सीमित कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया जाए।
2. कंपनी की प्रमुख वस्तुएं व्यापार, विनिर्माण, आयात, निर्यात, सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आदि के व्यापार को आगे बढ़ाना है।
3. मैमोरेडम की एक प्रति और प्रस्तावित कंपनी के संघ के लेख 188, हरगोबिंद एन्क्लेव, दिल्ली -110092 पर कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।
4. सूचना यह दी गई है कि इस आवेदन पर आपत्ति करने वाला कोई भी व्यक्ति अपने पंजीकृत कार्यालय में कंपनी को एक प्रति के साथ, इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर रजिस्ट्रार CRC, मानेसर हरियाणा को लिखित रूप में अपनी आपत्ति को सूचित कर सकता है। दिनांक – 26/11/2019
आवेदक का नाम: दादरी फूड्स एलएलपी
पार्टनर :
1. गिरधारी लाल गुप्ता 2. स्नेह प्रभा गुप्ता

प्रतीकात्मक कब्जा सूचना
ICICI Bank
ICICI Bank Limited
शाखा कार्यालयः आईसीआईसीआई बैंक, द्वितीय तल, वीडियोकॉन टॉवर, झण्डेवालान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के अन्तर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत निम्न वर्णित उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें उनको उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचनाओं में वर्णित धनराशियों का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
चूंकि उधारकर्तागण निर्धारित बकाया धनराशियों का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने निम्न-वर्णित तिथियों पर उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा ग्रहण कर लिया है। अतः इस संबंध में उधारकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि वे सम्पत्ति का लेन-देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई भी लेन-देन आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता का नाम/ ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का विवरण/प्रतीकात्मक कब्जे की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि	शाखा का नाम
1.	पेविक लाइफ स्टाइल प्रा. लि. /विक्रम हाडा/पूजा हाडा,/ एलबीएनओडी00002354684	यूनिट सं. सी6-002, भूतल, आईरियो द कॉरिडोर्स, सेक्टर 67ए, गुड़गांव/20 नवंबर, 2019	30 अक्टूबर, 2017 रु. 79,95,631/-	दिल्ली/ एनसीआर
2.	राजेश अरोड़ा/अचला अरोड़ा/ एलबीजीयूआर00003056412	टॉवर टी15, ग्राम वजीरपुर, मेवका क्रेसेंट पार्क टॉवर ए, सेक्टर-92, रामप्रस्थ, सारे रियलटी प्रा. लि., फ्लैट सं. टी-15 1006, गुड़गांव, हरियाणा-122003/20 नवंबर, 2019	31 अगस्त, 2019 रु. 68,58,412/-	दिल्ली/ एनसीआर
3.	सन एग्रीक्रेश इंडस्ट्रीज प्रा. लि/ नीलेशसिंह/ एलबीडीईएल00002095528	ब्लॉक 5, उन्नति द अरण्य हाईट्स, टॉवर 5, भूखण्ड सं. जीएच-02, सेक्टर-119, फ्लैट सं. पीएफ 04, चतुर्थ तल, नोएडा-201301/21 नवंबर, 2019	31 अगस्त, 2019 रु. 85,34,414/-	दिल्ली/ एनसीआर
4.	सन एग्रीक्रेश इंडस्ट्रीज प्रा. लि./ नीलेश सिंह/ एलबीडीईएल00002161397	टॉवर 5, उन्नति द अरण्य हाईट्स, भूखण्ड सं. जीएच-02, सेक्टर-119, फ्लैट सं. 1803, 18वां तल, नोएडा-201301/21 नवंबर, 2019	31 अगस्त, 2019 रु. 72,75,179/-	दिल्ली/ एनसीआर
5.	देवेन्द्र सिंह/सुषमा राजपूत/ एलबीएनओडी00002365554	16वां तल, टॉवर ए3, भूखण्ड सं. जीएच 02बी, यूनिट सं. ए3 1605, ग्रेटन नोएडा, उत्तर प्रदेश-201307/21 नवंबर, 2019	31 अगस्त, 2019 रु. 73,38,103/-	दिल्ली/ एनसीआर
6.	विनोद कुमार शर्मा/रीता शर्मा/ एलबीडीईएल00002210688	भूखण्ड सं. 10, फ्लैट सं. जीएफ-05, भूतल, टॉवर बी, गार्डेनिया गेटवे, सेक्टर-75, नोएडा-201305/21 नवंबर, 2019	19 जुलाई, 2019 रु. 58,66,075/-	दिल्ली/ एनसीआर
7.	मोहित सचदेवा/हरीश चन्द्र सचदेवा/ एलबीडीईएल00002065850	फ्लैट सं.-बी 1816, 18वां तल, गार्डेनिया गेटवे, भूखण्ड सं. -10, सेक्टर-75, नोएडा-201305/21 नवंबर, 2019	19 जुलाई, 2019 रु. 57,37,813/-	दिल्ली/ एनसीआर
8.	संजय रावत/संगीता रावत/एलबीडीईएल00002865565	फ्लैट सं. टीए-1807, भूतल, द अरण्य रेजिडेंसी, टॉवर-ए भूखण्ड सं. जीएच-02, सेक्टर-119, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर-201301/21 नवंबर, 2019	19 जुलाई, 2019 रु. 55,11,045/-	दिल्ली/ एनसीआर
9.	अमित विश्नोई/श्वेता सिंह विश्नोई/ एलबीजीयूआर00002272907	फ्लैट सं. टी 3-2001, 20वां तल, द अरण्य हाईट्स टॉवर, टी3 भूखण्ड सं. जीएच 02, सेक्टर-119, नोएडा-201301/21 नवंबर, 2019	19 जुलाई, 2019 रु. 53,34,194/-	दिल्ली/ एनसीआर
10	संजय कुमार/ज्योति चौण्डल/ एलबीडीईएल00002062029	फ्लैट सं. भूतल 14 इन टॉवर बी ऑन भूतल गार्डेनिया गेटवे, भूखण्ड सं.-10, सेक्टर-75, नोएडा-201305/21 नवंबर, 2019	19 जुलाई, 2019 रु. 43,20,926/-	दिल्ली/ एनसीआर
11.	अमित त्रिवेदी/रश्मि अग्निहोत्री/ एलबीडीईएल00002080710	12वां तल, टॉवर टी1, 12ए06, द अरण्य जो कि भूखण्ड सं. जीएच-02, सेक्टर-119, नोएडा-201301 में स्थित है/21 नवंबर, 2019	31 अगस्त, 2019 रु. 42,53,963/-	दिल्ली/ एनसीआर
12	सचिन कुमार/मोनिका वर्मा/ एलबीडीईएल00001764009	आउट रूफ टेरेस के साथ प्रथम तल भाग, निर्मित सम्पत्ति सं. 69 पॉकेट 9 सेक्टर-22 रोहिणी दिल्ली-110085 का भाग/21 नवंबर, 2019	28 सितंबर, 2012 रु. 27,22,255/-	दिल्ली/ एनसीआर
13	चिदंबरम नारायणन/ एलबीजीयूआर00002427707	16वां तल, टॉवर-15, सारे क्रेसेंट पार्क, फेज 4, सेक्टर-92, फ्लैट सं. 1701, गुड़गांव, हरियाणा-122001/20 नवंबर, 2019	31 अगस्त, 2019 रु. 78,34,145/-	दिल्ली/ एनसीआर
14	कुमार रंजन/सिद्धेश्वर प्रसाद/ एलबीडीईएल00002070700 एलबीडीईएल00002112147 एलबीडीईएल00002849445	भूखण्ड सं.-103, ब्लॉक-सी, सेक्टर-49, गौतमबुद्ध नगर, नोएडा-201301/20 नवंबर, 2019	29 अगस्त, 2019 रु. 76,16,993/-	दिल्ली/ एनसीआर
15	राकेश कुमार मिश्रा/बिन्दु मिश्रा/ एलबीडीईएल00002357759	फ्लैट सं. ई-002, भूतल टॉवर-ई, कैपिटल गेटवे, सेक्टर-111, गुड़गांव, हरियाणा/20 नवंबर, 2019	28 फरवरी, 2019 रु. 82,88,268/-	दिल्ली/ एनसीआर
16	आशुतोष अग्रवाल/मीनू अग्रवाल एलबीजीयूआर00003118370	फ्लैट सं.-1001, टी-7, 10वां तल, रुद्र एक्वाकासा, भूखण्ड सं. जीएच-05ए, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश, नोएडा/20 नवंबर, 2019	30 अप्रैल, 2019 रु. 28,85,133/-	दिल्ली/ एनसीआर
17	हिबा हुसैन/यूसुफ हामिद हुसैन/ एलबीडीईएल00002417908 एवं एलबीडीईएल00004364547	यूनिट सं. डी5-2007, 20वां तल, टॉवर सं. डी5, निराला ऐस्पायर जीएच-03, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा (पश्चिम), उत्तर प्रदेश/20 नवंबर, 2019	18 जून, 2019 रु. 28,20,817/-	दिल्ली/ एनसीआर
18	कनहाई लाल/वरुण गुप्ता/ एलबीजीयूआर00003218096	एफएफ-74, प्रथम तल, एसएस ओमनिया, एसएस सिटी, सेक्टर-86, गुड़गांव-122001, हरियाणा/20 नवंबर, 2019	31 अगस्त, 2019 रु. 12,32,526/-	दिल्ली/ एनसीआर
19	कमल भटनागर/प्रणव भटनागर एलबीडीईएल00002090600	फ्लैट सं.-1803, 18वां तल, अरण्य हाईट्स, टॉवर-5जीएच-2, सेक्टर-119, न

समय पर अचल संपत्ति का विवरण दें आईएएस

भाषा। नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों को समय पर अपनी अचल संपत्ति का विवरण देने, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करने को कहा है। कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह कहा गया है। देश भर में 5,205 आईएएस अधिकारी कार्यरत हैं। नियमों के अनुसार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी को एक निर्दिष्ट फॉर्म में वार्षिक रिटर्न दाखिल करना होता है। इसमें उन्हें विरासत में मिली अचल संपत्ति, उनके स्वामित्व वाली या उनके द्वारा खरीदी गई या उनके द्वारा पट्टे पर या गिरवी ली गई उन संपत्तियों का पूर्ण विवरण देना होता है, जो उनके नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य या अन्य व्यक्ति का नाम पर पंजीकृत है।

इस तरह की अचल संपत्ति का

● अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी: सरकार

वार्षिक रिटर्न साल में 31 जनवरी तक जमा करना होता है। कार्मिक मंत्रालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 444 आईएएस अधिकारियों का अपना नवीनतम अचल संपत्ति रिटर्न जमा करना बाकी है। कार्मिक मंत्रालय ने एक ताजा आदेश में कहा है कि उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में लोक सेवकों की विफलता अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित अन्य चीजों के लिए उपयुक्त और पर्याप्त कारण होंगे। अचल संपत्ति रिटर्न (आईपीआर) दाखिल करने की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कार्मिक मंत्रालय ने आईएएस अधिकारियों के संबंध में इस तरह के रिटर्न को ऑनलाइन दाखिल करने की शुरुआत की है।

इस मॉड्यूल के माध्यम से, अधिकारी आईपीआर इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं या हाथ से भरे गए आईपीआर की स्कैन की हुई प्रति अपलोड कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि कैलेंडर वर्ष 2019 का रिटर्न दाखिल करने के संबंध में यह ऑनलाइन मॉड्यूल 31 जनवरी, 2020 की निर्धारित समयावधि के बाद स्वत: बंद हो जाएगी। केंद्र सरकार के विभागों के सचिवों और राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को जारी किए गए आदेश में कहा गया है, इसलिए, मैं आपसे अपने मंत्रालयाविभाग और इसके विभिन्न संगठनों में काम करने वाले सभी आईएएस अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध करूँगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे 31 दिसंबर 2019 को वर्ष समाप्त हो रहे वर्ष के लिए आईपीआर मॉड्यूल में अपना आईपीआर ऑनलाइन जमा करें।

युद्ध में जान देने वाले सैनिकों के परिजन सरकारी आवास में एक साल तक रह सकते हैं : राजनाथ सिंह

नई दिल्ली (भाषा)। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी जिसमें युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिजनों को सरकारी आवास में तीन महीने की जगह एक साल तक रहने की अनुमति प्रदान करने की बात कही गई है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, वर्तमान में, शत्रु बलों के खिलाफ कार्वाई या शत्रु के हवाई हमलों में जान गंवाने वाले सशस्त्र बल कर्मियों के परिजनों को सरकारी आवास में तीन महीने तक रहने की अनुमति मिलती है जिसे अब बढ़ाकर एक साल कर दिया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया, जरूरतों और सेना के तीनों अंगों-थलसेना, नौसेना तथा वायुसेना की मांगों के मद्देनजर रक्षा मंत्रालय ने मौजूदा प्रावधानों की समीक्षा की और सेना कर्मियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए अवधि को बढ़ा दिया।

आतंकवाद वैश्विक शांति के समक्ष सबसे बड़ा खतरा : विदेश मंत्री

भाषा। नई दिल्ली

विदेश मंत्री एस जसशंकर ने मंगलवार को कहा कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के समक्ष सबसे बड़ा खतरा है तथा मानवाधिकार और लोकतंत्र के लिए खड़े होने वाले सभी लोगों को इस बुराई के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। जयशंकर ने मुंबई में 11 वर्ष पहले हुए जघन्य आतंकी हमले के संदर्भ में यह बात कही।

संविधान को अंगीकार किए जाने के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित एक समारोह में जयशंकर ने कहा, आज हमारी लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर जघन्य हमले की बरसी है। मुंबई में 11 साल पहले हुए इस आतंकी हमले ने भारतीयों की सामूहिक चेतना पर आघात करने का काम किया। भारतीय संविधान के संदर्भ में विदेश मंत्री ने कहा कि यह भारतीयों के जीवन का मौलिक हिस्सा है क्योंकि यह कठिन समय में लोगों को मार्ग दिखाने का काम करता है। उन्होंने

नई दिल्ली में मंगलवार को संविधान दिवस समारोह के दौरान राजनयिकों को संबोधित करते विदेश मंत्री एस जयशंकर

यह भी कहा कि भारतीय संविधान केवल अनुच्छेद एवं अनुसूचियों का समूह नहीं है, बल्कि यह लोगों की उम्मीदों एवं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है।

जयशंकर ने कहा, आपमें से बहुत से लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान अनुच्छेद एवं अनुसूचियों के समूहों से कहीं आगे है। यह हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है जो ऐसे समाज के लिए आदर्श है जिसकी हम कल्पना करते हैं। विदेश मंत्री ने कहा, संविधान भारतीयों के जीवन का बुनियादी हिस्सा है जो कठिन समय में हमें रास्ता दिखाता है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा संविधान पिछले सात दशकों से बना हुआ है।

एनआरसी के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में विपक्ष का हंगामा

भाषा। पटना

बिहार विधानसभा में विपक्ष ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के मुद्दे पर मंगलवार को हंगामा किया।

विपक्ष ने राज्य में एनआरसी को लागू नहीं किए जाने के लिए प्रस्ताव पारित कर केन्द्र को भेजने की मांग को लेकर हंगामा किया। हंगामे के बीच कुछ विधाई कार्यों को संपन्न किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर कांग्रेस, राजद और भाकपा-माले के विधायकों ने एनआरसी मुद्दे को लेकर अध्यक्ष के आसन के समक्ष आकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। विपक्षी सदस्य मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार को एनआरसी को वापस ले लेना चाहिए। एनआरसी बिहार में लागू नहीं किए जाने और इसके यहां कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए सदन एक प्रस्ताव पारित करे।

बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने विपक्षी सदस्यों से कहा कि वे उचित समय पर इस मुद्दे को उठाए जाने पर सरकार से जवाब मांगेंगे। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी विधायक नारेबाजी करते रहे। विपक्षी दलों के विधायकों द्वारा नारेबाजी जारी रखने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले तीनों विपक्षी दलों के सदस्यों ने एनआरसी को वापस लेने के लिए सदन के बाहर प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने एनआरसी को वापस लेने के साथ ही राज्य सरकार से एनआरसी के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की।

सदन के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए राजद के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा की गोद में बैठे होने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में एनआरसी के कार्यान्वयन को लेकर उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन से यह प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए कि एनआरसी को बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है तो विपक्ष राज्य सरकार के साथ होगा। सदन की कार्यवाही भोजनवाकाश के बाद शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी जारी रखी। इस बीच अध्यक्ष ने उपमुख्यमंत्री सह वित्तमंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पेश बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2019 और बिहार काराधान विवाद समाधान विधेयक 2019 को ध्वनि मत से पारित घोषित करने सहित अन्य विधाई कार्यों को संपन्न कर सदन की कार्यवाही बुधवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

पटना के मीलर स्कूल मैदान में राज्य सरकार के खिलाफ 'शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार' पर धरना के दौरान मंगलवार को राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाह के साथ एचएएम (एस) के प्रमुख जीतन राम मांझी, वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और अन्य लोग

दो विधेयक पारित, जीएसटी पंजीकरण में आधार हुआ अनिवार्य

पटना (भाषा)। बिहार विधानसभा में एनआरसी को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच सदन ने उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पेश किए गए बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2019 तथा बिहार काराधान विवाद समाधान विधेयक 2019 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधानसभा की कार्यवाही भोजनावकाश के बाद शुरू होने पर एनआरसी को वापस लिए जाने और इसे बिहार में लागू न करने के वास्ते सदन द्वारा एक प्रस्ताव पारित किए जाने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने आसन के समक्ष नारेबाजी की। इसके बीच उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी द्वारा पेश बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2019 और बिहार काराधान विवाद समाधान विधेयक 2019 को अध्यक्ष विजय कुमार चौधारी ने ध्वनिमत से पारित घोषित कर दिया। सुशील ने बिहार माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2019 के बारे में बताया कि जीएसटी परिषद की अनुशंसाओं के आलोक में बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व में निबंधन के लिए सीमा 20 लाख रुपए निर्धारित थी जिसे अब 40 रुपए लाख किया गया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी के अधीन निबंधन प्राप्त करने के लिए आधार संख्या को अनिवार्य बनाया गया है ताकि नवनिबंधित व्यवसायियों की ठोस पहचान की जा सके। सुशील ने कहा कि अधिनियम में हुए प्रथम संशोधन के तहत प्रावधान किया गया था कि कम्पोजिशन लेवी का कोई करदाता राज्य में अपने कारोबार का 10 प्रतिशत अथवा पांच लाख रुपए, जो भी अधिक हो की सीमा तक सेवाओं की आपूर्ति कर सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित संशोधन में मुख्य रूप से सेवाओं की आपूर्ति करने वाले 50 लाख रुपए कारोबार तक के व्यवसायियों के लिए भी कम्पोजिशन लेवी का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। सुशील ने कहा कि कम्पोजिशन लेवी के विकल्प का चुनाव करने वाले व्यवसायियों के लिए त्रैमासिक आधार पर विवरणी एवं त्रैमासिक कर भुगतान के प्रावधान हैं। प्रस्तावित संशोधन में कम्पोजिशन लेवी के व्यवसायियों के लिए मात्र वार्षिक विवरणी दाखिल किए जाने की व्यवस्था की गई है, पर कर का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बिहार काराधान विवाद समाधान विधेयक 2019 के बारे में बताया कि एकमुश्त कर समाधान योजना (ओटीएस) के तहत 31 दिसंबर तक सृजित विवादों का समाधान प्रास्तावित योजना में किया जा सकता है। प्रास्तावित समाधान योजना तीन माह की अवधि के लिए लागू होगी। उन्होंने कहा कि पिछली समाधान योजना में विवादित बकाया राशि के आधार पर वर्गीकरण किया गया था एवं बकाया के समाधान के लिए कर की अलग-अलग दरें निर्धारित थीं। प्रस्तावित समाधान योजना में विवाद में सन्निहित कर की राशि के आधार पर अलग अलग स्लैब के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया है। प्रस्तावित योजना में पहले के अधिनियमों के किसी भी अवधि एवं किसी भी राशि के विवादित कर बकाए को 35 प्रतिशत के भुगतान पर निपटारा किया जा सकेगा।

पश्चिम बंगाल में संवैधानिक प्रमुख के पद से गंभीर समझौता हुआ है : धनखड़

भाषा। कोलकाता

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के पद के साथ गंभीर समझौता हुआ है। धनखड़ का राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ कई मुद्दों पर टकराव चलता रहता है। उन्होंने कहा कि हालात अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण हैं और जनप्रतिनिधियों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। धनखड़ संविधान सभा द्वारा संविधान अंगीकार करने के 70 साल होने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस पर पश्चिम बंगाल विधानसभा में विशेष सत्र को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा, राज्य के संवैधानिक प्रमुख के पद से गंभीर समझौता हुआ है। यह अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण है। मैं जनप्रतिनिधियों से अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने का आह्वान करता हूं। जुलाई में पद संभालने के बाद से धनखड़ का कई मुद्दों पर राज्य सरकार के साथ टकराव हुआ है। जब वह सदन से चले गए तो तृणमूल कांग्रेस के विधायक जय बांग्ला, जय हिंद के नारे लगा रहे थे।

चिटफंड कारोबार में छोटे निवेशकों की सुरक्षा को लेकर राज्यसभा में जताई गई चिंता

भाषा। नई दिल्ली

राज्यसभा में मंगलवार को अधिकतर दलों के सदस्यों ने कहा कि सरकार को कम आय वर्ग के निवेशकों के खून-पसीने से कमाए गए धन की सुरक्षा के लिए समुचित प्रावधान करना चाहिए और उनके निवेश की सुरक्षा के लिए बीमा कवर देना चाहिए। उच्च सदन में चिट फंड (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सदस्यों ने छोटे निवेशकों के बारे में यह राय जताई।

इससे पहले विधेयक को चर्चा के लिए पेश करते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मकसद है कि चिट फंड में निवेश करने वाले छोटे व्यापारी और कम आय वर्ग के लोगों के हित को सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए चिट फंड कंपनियों का नियमन करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में किए गए एक प्रावधान के जरिए अब चिट खुलते समय ग्राहक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा सकेंगे।

ठाकुर ने कहा कि सरकार का मकसद है कि गरीबों से जुड़ा पैसा सुरक्षित रहना चाहिए। उन्हें उनका पैसा वापस मिलना चाहिए, इसमें कोई अवरोध नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कई लोगों में यह गलत धारणा है कि पोंजी और चिट फंड एक ही होते हैं। उन्होंने कहा कि पोंजी और चिट फंड में अंतर है। पोंजी अवैध होता है जबकि चिट फंड वैध कारोबार है। उन्होंने कहा कि चिट फंड की मौद्रिक सीमा को तीन गुना बढ़ाने तथा फोरमैन के कमीशन को सात प्रतिशत करने का इस विधेयक में प्रावधान किया गया है। गौरतलब है कि फोरमैन का आशय उस व्यक्ति से है जो चिट चलाता है।

ठाकुर ने कहा कि इसके तहत व्यक्ति के रूप में चिट की मौद्रिक सीमा को एक लाख रूपए से बढ़ाकर तीन लाख रूपए किया गया है जबकि फर्म के लिए इसे छह लाख रूपए से बढ़ाकर 18 लाख रूपए कर दिया गया है। यह विधेयक लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है। उच्च सदन में विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के पी भट्टाचार्य ने सरकार से मांग की कि इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेज दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सहित विभिन्न राज्यों में पोंजी स्कीमों के कारण कम आय वर्ग के लाखों लोगों को करोड़ों रूपए का चूना लगाया गया। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि क्या पोंजी स्कीम में अपने खून पसीने से कमाई गई पूंजी को गंवाने वाले लोगों को मदद के तौर कोई राशि मुहैया कराई गई है?

भट्टाचार्य ने कहा कि चिट फंड में कम आय वर्ग के लोग काफी निवेश करते हैं। सरकार को यह बताना चाहिए कि इस वर्ग के लोगों द्वारा निवेश किए गए धन की सुरक्षा के लिए वह कौन से उपाय कर रही है? मनोनीत नरेन्द्र जाधव ने कहा कि इस विधेयक के कुछ प्रावधान बहु प्रतीक्षित थे। उन्होंने चिट खोले जाने के समय वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए ग्राहकों की उपस्थिति को अनिवार्य करने के प्रावधान का स्वागत किया। जाधव ने पंजीकरण नहीं करने वाली चिट फंड कंपनी पर लगाए जाने वाले जुर्माने की राशि को अपर्याप्त बताया।

भाजपा के अनिल जैन ने कहा कि शुरू में समुचित कानून नहीं होने के कारण आम जनता में चिट फंड कंपनियों को चीटिंग कंपनी भी कहा जाता था। किंतु सरकार ने इस क्षेत्र के बेहतर नियमन के मकसद से कानून में समुचित संशोधन करने के लिए यह विधेयक तैयार किया है। उन्होंने कहा कि चिट फंड छोटे व्यापारियों एवं गरीब लोगों के लिए बचत का एक मुख्य साधन है। जैन ने कहा कि शुरू में लोग चिट फंड से इसलिए जुड़ते थे क्योंकि अधिकतर लोगों की बैंक तक पहुंच नहीं थी किंतु आज देश की 80 प्रतिशत आबादी की बैंकों तक पहुंच है।

शहरी सरकार बनाने में कांग्रेस की चली 35 निकायों में बना पार्टी का बोर्ड

भाषा। जयपुर

नगर निकाय चुनाव में अपनी बढ़त को कायम रखते हुए सत्तारूढ़ कांग्रेस 49 में से 35 निकायों में अपना अध्यक्ष यानी बोर्ड बनाने में सफल रही है। राज्य में 49 निकायों में बोर्ड अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को चुनाव हुआ। राज्य निर्वाचन विभाग के अनुसार, कुल मिलाकर 35 निकायों में अध्यक्ष पद पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की। वहीं 13 निकायों में भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष बनाने में सफल रही है। जैसलमेर नगरपरिषद में हरिवल्लभ कल्ला निर्दलीय के रूप में अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य में निकाय चुनाव के पहले चरण में 16 नवम्बर को तीन नगर निगमों, 17 नगर परिषदों व 29 नगरपालिकों में 2105 वार्ड पार्षदों के लिए चुनाव हुआ। इसका परिणाम 19 नवंबर को घोषित हुआ और इसमें कांग्रेस का दबदबा रहा। पार्टी कुल मिलाकर 965 वार्डों में जीती। 736 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी, 16 प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी, तीन प्रत्याशी माकपा के जीते तो 385 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने 49 नगर निकायों में से 35 नगर निकायों में कांग्रेस प्रत्याशियों के अध्यक्ष बनने पर खुशी व्यक्त की है। उन्होंने इसे जनता का कांग्रेस के प्रति प्रगाढ़ हुए विश्वास के फलस्वरूप मिले आशीर्वाद का परिचायक बताया है।

पायलट ने कहा कि राज्य में कांग्रेस सरकार के गठन के बाद हुए उपचुनाव व निकाय चुनाव में प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को सफल बनाकर स्पष्ट कर दिया है कि जनता राज्य सरकार की कार्यप्रणाली से पूर्णतया संतुष्ट है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस संगठन पूरी मुस्तैदी के साथ सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक ले जाकर उनके हित में सक्रियता से काम कर रहा है।

क्विक न्यूज

अवैध रूप से सीमा पार कर रहे 11 बांग्लादेशी पकड़े गए

कोलकाता (भाषा)। सीमा सुरक्षा बल के जवानो ने सोमवार से पश्चिम बंगाल के तीन जिलो मे 11 बांग्लादेशियो समेत 17 घुसपैठियो को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को बीएसएफ के एक बयान मे यह जानकारी दी गई। देश मे अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 24 परगना जिले के स्वरूप नगर मे विभिन्न जगहो पर आठ बांग्लादेशी नागरिको को पकड़ा गया, जबकि एक अन्य को उसी जिले के घोजाडंगा इलाके से गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर्स द्वारा जारी बयान मे कहा गया कि नदिया जिले के धनताला और राणाघाट थाना क्षेत्रो से दो अन्य बांग्लादेशियो को पकड़ा गया। बांग्लादेश की तरफ से अवैध रूप से भारत मे आने की कोशिश कर रहे पांच भारतीय नागरिको को उत्तरी 24 परगना जिले के गायघाट थाना क्षेत्र मे सीमा पर पकड़ा गया। बयान मे कहा गया है कि एक अन्य भारतीय व्यक्ति को घोजाडंगा इलाके मे पकड़ा गया है।

कार्बेट पार्क में गैंडे को बसाया जाएगा

देहरादून (भाषा)। कार्बेट टाइगर रिजर्व की भौगोलिक एवं पर्यावरणीय परिस्थितियो के गैंडे के अनुकूल होने के मद्देनजर वहां प्रायोगिक तौर पर गैंडे को बसाया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता मे मंगलवार को यहां राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक मे इस बात पर सहमति बनी कि कार्बेट पार्क मे गैंडे को बसाया जाए। इस संबंध मे प्रस्तुतिकरण मे बताया गया कि गैण्डे और मानव के बीच संघर्ष की संभावना के न होने के साथ ही यह अन्य जीवो के लिए भी सहायक होता है। यह भी बताया गया कि इससे राज्य मे पर्यटन गतिविधियां भी बढ़ेगी। इस पर बोर्ड ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व मे प्रायोगिक तौर पर गैण्डे को लाए जाने पर सहमति दे दी।

कश्मीर में दोपहर तक खुले बाजार, वाहनों की संख्या बढ़ी

भाषा। श्रीनगर

कश्मीर घाटी में मंगलवार को वाहनों की लगभग सामान्य आवाजाही के बीच दुकानदारों ने दोपहर तक दुकानें खोलीं जिनमें लोगों की काफी भीड़ दिखाई दी और इसके साथ ही घाटी में जनजीवन सामान्य होने की ओर लौटता नजर आया। अधिकारियों ने बताया कि दुकानदारों ने सुबह दुकानें खोलीं लेकिन उन्होंने पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त करने के आदेश के विरोध में शामिल होने के लिए दोपहर को दुकानें बंद कर दीं। अधिकारियों ने बताया कि दोपहर तक खुले बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। उन्होंने बताया कि आवागमन के अधिकतर साधन सड़कों पर नजर आए जिसके कारण कनेक्टिविटी में सुधार हुआ।

केन्द्र सरकार के अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाने के निर्णय के करीब तीन महीने बाद कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर पिछले कुछ हफ्तों में स्थिति सामान्य होती दिख रही थी, लेकिन दुकानदारों और सार्वजनिक वाहन परिचालकों को धमकी देने वाले पोस्टर लगाए जाने के बाद पिछले बुधवार से बंद दोबारा शुरू हो गया। पुलिस ने घाटी में पोस्टर लगाए जाने के मामले का संज्ञान लेते हुए तेजी से कार्वाई की और कुछ असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा हटाने और उसे दो केन्द्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की पांच अगस्त की केंद्र की घोषणा के बाद से अभी तक यहां प्री-पेड मोबाइल फोन और सभी इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं। शीर्ष स्तर एवं दूसरी पंक्ति के अलगाववादी नेताओं को एहतियातन हिरासत में रखा गया है। साथ ही दो पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला एवं महबूबा मुफ्ती समेत मुख्यधारा के नेताओं को या तो हिरासत में रखा गया है या नजरबंद किया गया है। सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं श्रीनगर से मौजूदा लोकसभा सांसद फारूक अब्दुल्ला को अब भी विवादित लोक सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत में रखा है।

पंथनिरपेक्षता खतरे में है: एम के नारायणन

भाषा। कोलकाता

पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एम के नारायणन ने मंगलवार को कहा कि संविधान में निहित पंथनिरपेक्षता खतरे में है। उन्होंने कहा कि विकास और लोकतंत्र में से एक चुनना संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास का अर्थ लोकतांत्रिक अधिकारों और उदारवादी मूल्यों का दमन करना नहीं है। संविधान दिवस के अवसर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, हमारे संविधान में निहित कई अन्य सिद्धांतों की भांति आज के हालात में पंथनिरपेक्षता खतरे में है। बहुलतावाद भी खतरे में है। उन्होंने देश के संघीय ढांचे को मजबूत करने के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विचार का भी समर्थन किया। नारायणन ने कहा कि राज्य केंद्र के अधीन नहीं हैं क्योंकि दोनों की शंक्तियां संविधान में निहित हैं।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी ने मंगलवार को मुंबई विश्वविद्यालय के वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान एक छात्र को डिग्री प्रदान करते हुए

संविधान दिवस पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित

संसद के केंद्रीय कक्ष में सांसदों से कर्तव्य निभाने का आह्वान

भाषा। नई दिल्ली

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसी केंद्रीय कक्ष में आयोजित समारोह में, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अधिकारों के साथ कर्तव्य निभाने के लिए आह्वान किया जहां 70 साल पहले संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंगीकार किया था। मंगलवार को संसद के दोनों सदनों की, संविधान दिवस पर आयोजित संयुक्त बैठक करीब एक घंटा 15 मिनट चली जिसमें 70 वर्ष पूर्व आज ही के दिन संविधान को स्वीकार किए जाने की स्मृतियां जीवंत हो उठीं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने करीब 20 मिनट के भाषण में संविधान के निर्माण में प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद, डॉ बाबासाहब भीमराव आंबेडकर, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य जे बी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हंसा मेहता, कृष्णास्वामी अय्यर, गोपालस्वामी अयंगर और सुचेता कृपलानी आदि के योगदान को याद किया। संयुक्त बैठक की शुरूआत राष्ट्रगान की धुन के साथ हुई। इससे पहले उपराष्ट्रपति नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगवानी की और उन्हें केंद्रीय कक्ष में लेकर आए।

अग्रिम पंक्ति में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री एस जयशंकर, भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य जे पी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर, रामविलास पासवान, थावर चंद गहलोत, स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद और हर्षवर्धन आदि बैठे थे।

संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंचासीन अतिथियों का स्वागत भाषण पढ़ा और उन्होंने जब प्रधानमंत्री मोदी को विश्वप्रिय नेता कहते हुए उनका स्वागत किया तो दोनों सदनों के भाजपा सदस्यों ने देर तक मेजें थपथपाकर उनका अभिनंदन किया। उपराष्ट्रपति नायडू ने जब अपना भाषण शुरू करने से पहले मंचासीन अतिथियों के नाम पुकारे तो उन्होंने राष्ट्रपति कोविंद, लोकसभा अध्यक्ष बिरला और प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद तथा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का भी नाम लिया।

आजाद और चौधरी हालांकि इस समारोह में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के साथ ही राकांपा, शिवसेना, तृणमूल कांग्रेस, राजद, द्रमुक और वामदलों समेत विपक्ष ने महाराष्ट्र के मुद्दे पर इस संविधान दिवस कार्यक्रम का बहिष्कार किया था। राष्ट्रपति कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने जहां हिंदी में भाषण दिया वहीं उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति नायडू ने पूरा भाषण अंग्रेजी में दिया और उसका एक अंश हिंदी में भी पढ़ा। नायडू ने अपने भाषण में एक जगह भाषा का उल्लेख आने पर मातृभाषा के प्रति विशेष अनुराग के साथ ही अन्य भाषाओं का भी ज्ञान रखने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने अपनी मातृभाषा तेलुगु में भी एक पंक्ति बोली। धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधता के साथ सौहार्द बढ़ाने पर जोर देते हुए नायडू ने हिंदी में अनेकता में एकता, भारत की विशेषता और अलग भाषा-अलग वेश, फिर भी अपना एक देश जैसे सूत्रवाक्य भी बोले।

नुसरत जहां ने संविधान दिवस उत्सव में लिया हिस्सा

नई दिल्ली। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां ने मंगलवार को संसद में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया जबकि उनकी पार्टी सहित कई विपक्षी दलों के नेता महाराष्ट्र के मुद्दे पर संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे थे और वह उस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुईं। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, राकांपा, द्रमुक, राजद, सपा, वामपंथी पार्टियों और शिवसेना ने महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद के शपथग्रहण का विरोध किया। ये विपक्षी पार्टियां संसद परिसर में बी आर आंबेडकर की प्रतिमा के नीचे उसी समय प्रदर्शन कर रही थीं जब संसद के सेंट्रल हॉल में संविधान दिवस का उत्सव चल रहा था। तृणमूल कांग्रेस के सांसद जहां इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे, वहीं जहां ने संविधान दिवस उत्सव में हिस्सा लिया। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि वह गलती से उस कार्यक्रम में पहुंच गई थीं।

● विरोध प्रदर्शन में नही हुई शामिल

कांग्रेस का संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार डॉ आंबेडकर का अपमान : प्रसाद

नई दिल्ली। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित संविधान दिवस समारोह का बहिष्कार किए जाने पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि यह, संविधान निर्माता डॉ बाबासाहब भीमराव आंबेडकर का अपमान है। कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा समेत विपक्षी दलों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस पर आयोजित संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का बहिष्कार किया। इन दलों ने महाराष्ट्र मुद्दे पर विरोध दर्ज कराते हुए संविधान दिवस कार्यक्रम में शामिल नहीं होने का फैसला किया। कानून मंत्री प्रसाद ने कहा, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है और यह दिन राजनीतिक मतभेदों से ऊपर है। केंद्रीय कक्ष में कांग्रेस की गैरमौजूदगी संविधान निर्माता डॉ आंबेडकर का अपमान है और यह कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस ने पहले भी उन्हें भारत रत्न नहीं देकर ऐसा ही किया था।

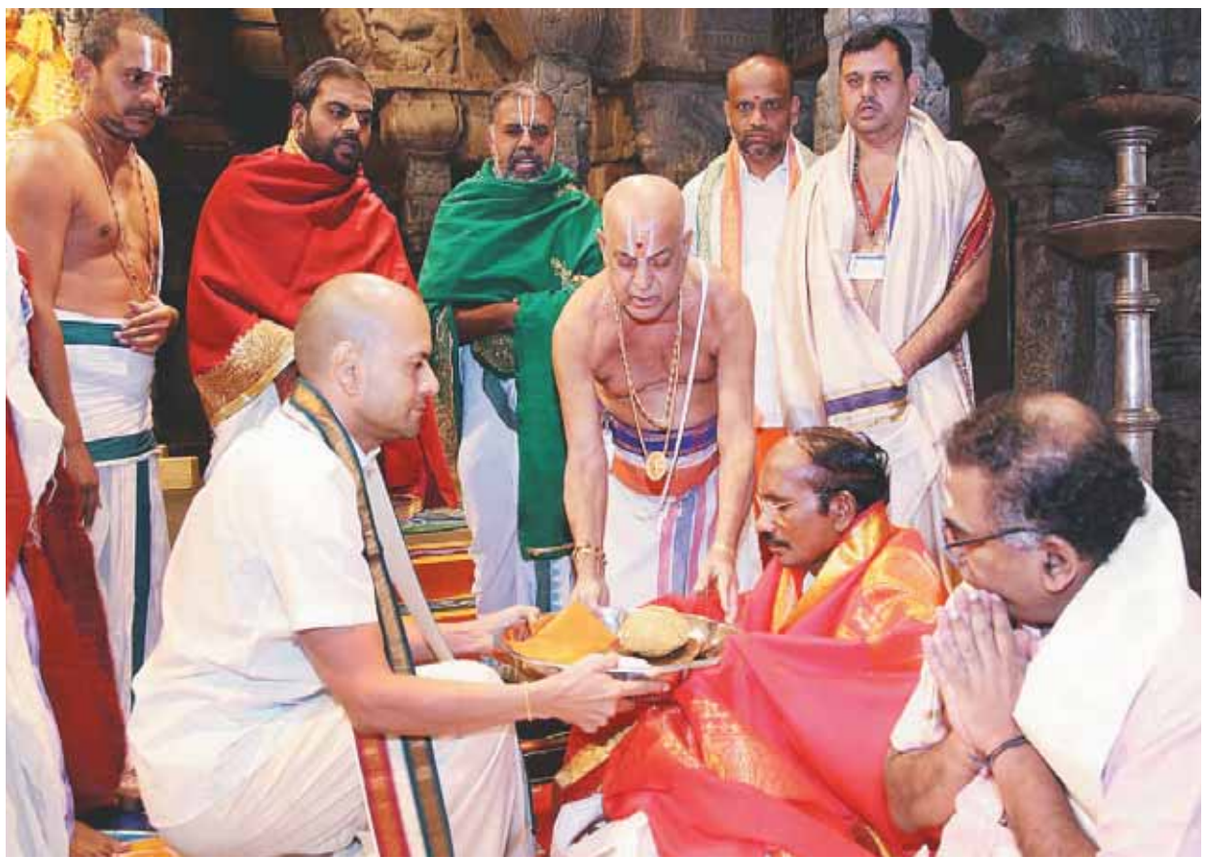

तिरूमाला के चित्तूर जिले में इसरो प्रमुख के. सिवान भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करने के बाद पूजा-अर्चना करते हुए

कार्टोसैट-3 के साथ 13 अन्य उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती शुरू

भाषा। चेन्नई

धरती की निगरानी एवं मानचित्र उपग्रह कार्टोसैट-3 के साथ अमेरिका के 13 नैनो उपग्रहों के प्रक्षेपण की 26 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अंतरिक्ष एजेंसी ने 27 नवंबर को सुबह नौ बजकर 28 मिनट पर कार्टोसैट-3 के प्रक्षेपण की योजना बनाई है। यह कार्टोसैट श्रृंखला का नौवां उपग्रह है जिसे यहां से 120 किलोमीटर दूर श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वितीय लांच पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा।

इसरो ने मंगलवार को कहा, पीएसएलवी-सी47 अभियान के प्रक्षेपण के लिए श्रीहरिकोटा में आज सुबह सात बजकर 28 मिनट पर 26 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हो गई। इसे 27 नवंबर बुधवार को सुबह नौ बजकर 28 मिनट पर प्रक्षेपित किया जाना है। पीएसएलवी-सी47 की यह 49वीं उड़ान है जो कार्टोसैट-3 के साथ अमेरिका के वाणिज्यिक उद्देश्य वाले 13 छोटे उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा। कार्टोसैट-3 तीसरी पीढ़ी का बेहद चुस्त और उन्नत उपग्रह है जिसमें हाई रिजोल्यूशन तस्वीर लेने की क्षमता है। इसका भार 1,625 किलोग्राम है और यह बड़े पैमाने पर शहरी नियोजन, ग्रामीण संसाधन और बुनियादी ढांचे के विकास, तटीय भूमि के उपयोग तथा भूमि कवर के लिए उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करेगा। इसरो ने कहा है कि पीएसएलवी-सी47 एक्सएल कनफिगरेशन में पीएसएलवी की 21वीं उड़ान है।

न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अंतरिक्ष विभाग के वाणिज्यिक प्रबंधों के तहत इस उपग्रह के साथ अमेरिका के 13 नैनो वाणिज्यिक उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया जा रहा है। इसरो ने बताया कि श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह 74वां प्रक्षेपण यान मिशन होगा। कार्टोसैट-3 का जीवनकाल पांच साल का होगा। कार्टोसैट-3 तथा 13 अन्य नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण गत 22 जुलाई को चंद्रयान -2 के प्रक्षेपण के बाद हो रहा है।

इसरो प्रमुख ने कार्टोसैट-3 के प्रक्षेपण से पहले तिरुमाला मंदिर मे दर्शन किए

तिरुपति। इसरो प्रमुख के सिवन ने भारत के उपग्रह कार्टोसैट-3 के प्रक्षेपण से पहले मंगलवार को तिरुपति स्थित तिरुमाला मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसरो बुधवार को श्रीहरिकोटा से पृथ्वी के चित्रण और मानचित्रण उपग्रह कार्टोसैट-3 के साथ ही अमेरिका के 13 अन्य छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए तैयार है। सिवन ने यहां तिरुमाला में भगवान वेंकटेश की पूजा-अर्चना की। उन्होंने बाद में संवाददाताओं से कहा कि चंद्रयान-2 का आर्बिटर अच्छी तरह काम कर रहा है और चंद्रमा के बारे में बहुत सी सूचनाएं भेज रहा है। चंद्रयान-2 के लैंडर विक्रम की सात सितंबर को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का प्रयास विफल हो गया था और इसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी। इसके साथ ही इसका जमीनी स्टेशन से संपर्क टूट गया था।

भारत की शेफ ने 87 घंटे 45 मिनट तक लगातार खाना पकाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया

इंदौर (मध्यप्रदेश)। भारत की 39 वर्षीय शेफ ने सबसे लम्बे समय तक खाना पकाने का विश्व कीर्तिमान कायम करते हुए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्ज में अपना नाम दर्ज कराया है। विश्व रिकार्ड बनाने वाली लता टंडन ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्ज ने उनके इस कारनामे को लॉन्गेस्ट कुकिंग मैराथन (व्यक्तिगत) के रूप में मान्यता देते हुए आधिकारिक प्रमाणपत्र जारी किया है। मध्यप्रदेश के रीवा से ताल्लुक रखने वाली विवाहिता ने बताया कि उन्होंने इसी शहर के एक होटल में तीन सितंबर से सात सितंबर के बीच लगातार 87 घंटे 45 मिनट तक करीब 1,600 किलोग्राम खाना पकाया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्ज के सामने कीर्तिमान का दावा पेश किया था। इस दौरान उन्होंने गैस के चूल्हे पर आठ बर्नरों का इस्तेमाल किया और चावल के अलग-अलग पकवान, छोले, राजमा, कई तरह की दालें, कढ़ी, वड़ा पाव, सैंडविच, हलवा और खीर समेत कोई 30 व्यंजन पकाए। उन्होंने बताया कि विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए उनका पकाया खाना करीब 20,000 लोगों को खिलाया गया, जिसमें अनाथालय में रहने वाले बच्चे, दिव्यांग लड़के-लड़कियां और वृद्धाश्रम के बुजुर्ग शामिल हैं। उन्होंने कहा, भारत का पारंपरिक खाना हर मामले में बेहतरीन है। मैं इस खाने के स्वाद को दुनिया भर में पहुंचाना चाहती हूं।

मुंबई में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, वाइस एडमिरल अजीत कुमार (दाएं) और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी 26/11 आतंकी हमले की याद में हुए कार्यक्रम के दौरान

जम्मू-कश्मीर में पहली बार मनाया संविधान दिवस

● राज्यो मे विशेष विस सत्रो का आयोजन

भाषा। नई दिल्ली

संविधान अंगीकृत किए जाने के 70 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य विधानसभाओं ने मंगलवार को विशेष सत्रों का आयोजन किया और नेताओं ने भीम राव आम्बेडकर की प्रशंसा की। दूसरी ओर, विपक्ष ने संविधान के खतरे में होने का दावा किया। पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का अलग संविधान और विशेष दर्जा समाप्त करते हुए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर ने संविधान दिवस के अवसर पर पहली बार कार्यक्रम आयोजित किए।

उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने संविधान की प्रस्तावना पढ़कर संविधान दिवस मनाया। जम्मू कश्मीर के विधान परिषद में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपराज्यपाल के सलाहकार फारूक खान, मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम, प्रशासनिक सचिव और सिविल सचिवालय के अधिकारी इस अवसर पर मौजूद रहे। पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का 1957 से पहले तक अपना अलग संविधान था लेकिन केंद्र के इसका विशेष दर्जा समाप्त करने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के पांच अगस्त के फैसले ने इस विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया।

केंद्र शासित प्रदेश में संविधान दिवस के अवसर पर आयुक्तों, विभाग प्रमुखों, पुलिस विभागों के प्रमुखों और सरकारी कार्यालयों समेत सभी संस्थाओं ने कार्यक्रम आयोजित किए। संविधान दिवस के अवसर पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आयोजित किए जाने की तर्ज पर उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और पंजाब में विधानसभा के विशेष सत्र आयोजित किए गए।

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख के पद के साथ गंभीर समझौता हुआ है। धनखड़ का राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार के साथ कई मुद्दों पर टकराव चलता रहता है। उन्होंने कहा कि हालात अप्रत्याशित और चुनौतीपूर्ण हैं और जनप्रतिनिधियों को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। दिल्ली की तरह, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को संविधान के लिए झटका करार दिया।

उत्तर प्रदेश में विपक्षी कांग्रेस ने विशेष सत्र का बहिष्कार कर दिया और भाजपा पर महाराष्ट्र में संविधान की हत्या करने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र में भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी जिसके बाद विपक्ष ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के इतर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण का जिक्र करते हुए इसे अंधेरे में की गई संविधान की हत्या करार दिया।

लोकपाल को लोगो आदर्श वाक्य मिला

नई दिल्ली। भ्रष्टाचार रोधी संस्था लोकपाल को मंगलवार को इसका लोगो और आदर्श वाक्य मिल गया। कार्मिक मंत्रालय के बयान के मुताबिक इसके लिए एक खुली प्रतियोगिता के जरिए 6,000 से अधिक प्रविष्टियां प्राप्त हुई थी। खुली प्रतियोगिता के तहत देश के विभिन्न हिस्से से विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से लोगो के लिए 2,236 तथा आदर्श वाक्य के लिए 4,705 प्रविष्टियां प्राप्त हुईं। कार्मिक मंत्रालय ने बताया कि लोगो का डिजाइन प्रविष्टियों में से चुना गया, लेकिन आदर्श वाक्य के लिए किसी भी प्रविष्टि को उपयुक्त नहीं पाया गया और इसे स्वयं लोकपाल ने चुना। त्रिस्तरीय चयन प्रक्रिया के आधार पर उत्तरप्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले प्रशांत मिश्र की डिजाइन को लोकपाल के लोगो के लिए चुना गया है। मिश्र ने बताया कि लोगो लोकपाल के शाब्दिक पर आधारित है। इसमें लोक का अर्थ जनता और पाल का मतलब देखभाल करने वाला है।

राजग गठबंधन का संयोजक एवं संयोजन समिति बनाई जाए: चिराग पासवान

नई दिल्ली। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में राजग गठबंधन मजबूत स्थिति में होने का दावा करते हुए इस गठबंधन में शामिल लोक जन शक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने सुझाव दिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर घटक दलों में बेहतर सामंजस्य के लिए एक संयोजक एवं संयोजन समिति बनाई जानी चाहिए। चिराग ने भाषा से बातचीत में कहा, बिहार में राजग गठबंधन के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है। हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि गठबंधन मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। इस बारे में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी स्थिति स्पष्ट कर चुके हैं।

लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि राजग गठबंधन मजबूत है जबकि महागठबंधन में बिखराव हो रहा है। चिराग पासवान ने दावा किया कि बिहार में राजग गठबंधन अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में 200 से अधिक सीट सीट जीतेंगी।

यह पूछे जाने पर कि पिछले कुछ समय में राजग में कई घटक दलों के अलग होने के कारण गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ा है, लोजपा अध्यक्ष ने कहा कि तेदेपा, उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी, जीतनराम मांझी की पार्टी और अब शिवसेना जैसे राजग के घटक दलों के अलग होने से कुछ चिंताएं जरूर उभरी इसलिए हमने राजग में संयोजक बनाने और संयोजन समिति गठित किए जाने की बात कही है।

उन्होंने कहा कि हाल ही में राजग की बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के समक्ष इस विषय को उठाया। संयोजक एवं संयोजन समिति बनने से घटक दलों में बेहतर संवाद हो सकेगा और सरकार की बातों को रखा जा सकेगा। झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी के अलग चुनाव लड़ने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम झारखंड में भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन सहमति नहीं बन पाई, ऐसे में हम राज्य में अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली में भी हम भाजपा के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं और अगर सहमति नहीं बनती है तब अकेले चुनाव लड़ेंगे। चिराग ने कहा, इसके साथ ही यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि भाजपा के साथ हमारा गठबंधन केवल बिहार के लिए है। दूसरे राज्यों में हमारे (लोजपा) अलग चुनाव लड़ने से गठबंधन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना दिवस है और हमारा लक्ष्य देश के अलग अलग प्रदेशों में पार्टी के विस्तार पर होगा।

बिहार में शिक्षा में सुधार को लेकर कुशवाहा का आमरण अनशन शुरू

भाषा। पटना

बिहार में विपक्षी महागठबंधन में शामिल रालोसपा प्रमुख और पूर्व केंद्रीय शिक्षा राज्यमंत्री उपेन्द्र कुशवाहा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर शिक्षा विरोधी और निरंकुश होने का आरोप लगाया और मंगलवार को पटना के मिलर हाईस्कूल मैदान में आमरन अनशन पर बैठ गए।

उपेन्द्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा शिक्षा के विरोधी निरंकुश नीतीश सरकार के विरुद्ध आज संविधान दिवस पर बाबा साहेब डॉ भीमराव आंबेडकर जी को नमन कर शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार संकल्प के साथ आमरण अनशन की शुरुआत।

उन्होंने नीतीश पर अपना प्रहार जारी रखते हुए कहा, माना कि उपेंद्र कुशवाहा से आपकी कोई राजनीतिक ईर्ष्या-द्वेष होगी लेकिन बिहार के लाखों बच्चों के भविष्य से कैसा ईर्ष्या-द्वेष ? आज इन नन्हें बच्चों के हाथों में कलम की बजाए शिक्षा सुधार वरना जीना बेकार की तख्तियां क्यों ? अपनी जद्दि छोड़िए।

कुशवाहा की नीतीश सरकार से मांग है कि सरकार केंद्र से स्वीकृत नवादा और औरंगाबाद के देव कुंड में केंद्रीय विद्यालय के लिए तत्काल जमीन दें और जिन जिलों में केंद्रीय विद्यालय नहीं हैं, वहां के लिए प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजें।

कुशवाहा के आमरन अनशन कार्यक्रम में विपक्षी महागठबंधन में शामिल राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी भी शामिल हुए।

भरत शाह और उनके बेटे को मिली गिरफ्तारी से अंतरिम राहत

भाषा। मुंबई

यहां की एक अदालत ने कारोबारी और फिल्म निर्माता भरत शाह और उनके बेटे को मंगलवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान किया। इन पर एक पुलिसकर्मी पर हमला करने का आरोप है। पिता-पुत्र दोनों ने मामला दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। शनिवार को एक पब में झगड़े के दौरान इन्होंने कथित तौर पर एक पुलिसकर्मी पर हमला किया था। इन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम संरक्षण की मांग की थी। अदालत ने मंगलवार को कहा कि उन्हें तीन दिसंबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। उसी दिन उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। शाह के पौत्र और दो अन्य व्यक्ति इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों पर दर्ज हजारों प्रकरण लिए वापस

भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत सरकार ने प्रदेश की भाजपा नीत पूर्व सरकार द्वारा विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज हजारों मामलों को वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश के विधि एवं विधाई कार्य मंत्री पीसी शर्मा ने अपने विभाग का एक साल का ब्योरा देते हुए मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया, प्रदेश की भाजपा नीत पूर्व सरकार ने समूचे राज्य में किसानों पर 45,000 से अधिक मामले दर्ज किए थे। इनमें से हजारों की तादाद में किसानों पर दर्ज प्रकरण हमारी सरकार ने वापस ले लिए हैं। इस समय वह यह नहीं बता सकते कि किसानों पर दर्ज कुल कितने मामलों को वापस लिया गया है। किसानों पर मंदसौर, देवास, भोपाल एवं अन्य जगहों पर दर्ज किए थे। शर्मा ने बताया कि भाजपा नीत पूर्व सरकार ने किसान विरोधी नीतियों का विरोध करने पर किसानों को प्रताड़ित करने के लिए जेल में बंद कर दिया था।

शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली भाजपा नीत पूर्व शासनकाल में अपनी उपजों के वाजिब दाम, कर्ज माफी एवं अन्य मांगों को लेकर किसानों ने वर्ष 2017 में एक जून से 10 जून तक राज्यव्यापी आंदोलन किया था। इसमें मंदसौर के पिपलिया मंडी में छह जून 2017 को पुलिस गोलीबारी में छह किसानों की मौत हुई थी, जिसके बाद प्रदेश में व्यापक पैमाने पर हिंसा, आगजनी, लूटपाट एवं तोड़फोड़ हुई थी, जिसको लेकर किसानों पर मामले दर्ज किए गए थे। तत्कालीन सरकार ने बिजली चोरी एवं बिजली बिलों का भुगतान न करने सहित अन्य कई प्रकार के मामलों में किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे। पूर्व भाजपा नीत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2003 से वर्ष 2018 तक के शासनकाल में कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं पर राजनीतिक दुर्भावना के चलते लगाए गए झूठे मुकदमों को हटाने की प्रक्रिया भी चल रही है।

महाराष्ट्र में शक्ति परीक्षण

राजनीतिक स्पष्टता हेतु आवश्यक

महाराष्ट्र में अवसरवाद के कारण पैदा टकराव समाप्त करने के लिए सदन का गठन फौरन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे सदन में शक्ति परीक्षण तथा व्यवस्था बहाल होने का रास्ता खुलेगा। नई सरकार को शपथ दिलाने के बाद राज्यपाल की जिम्मेदारी सदन आहूत करने तथा एक अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त करना है। विधायकों को शपथ दिलाने के बाद पूर्णकालिक अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि, सरकार ने राज्यपाल को भाजपा व रांकापा द्वारा दिए पत्रों जैसे तकनीकी मामलों पर गौर किया था, पर अब इनका कोई खास अर्थ नहीं है। वह इस तथ्य को भी अनदेखा नहीं कर सकता है कि आधिकारिक रूप से रांकापा व शिवसेना ने राज्यपाल को 154 विधायकों की सूची दी है तथा अदालत में भी दावा किया है। दावे की वैधता जांचने के लिए सदन बुलाना व शक्ति परीक्षण जरूरी हो गया है। आशा है कि सर्वोच्च न्यायालय जनता में लोकतंत्र के प्रति विश्वास पैदा करेगा, नहीं तो यह सामंती व्यवस्था जैसा हो जाएगा जहां शक्ति ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती थी। कर्नाटक में सर्वोच्च न्यायालय ने फौरन शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था जिससे येदियुरप्पा अपने लिए समर्थन नहीं जुटा पाए थे।

भाजपा के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस का कहना है कि उनको 170 विधायकों का समर्थन प्राप्त है जिसमें उनके 105 विधायक, रांकापा के सभी 54 तथा निर्दलीय व छोटी पार्टियों के सभी 11 विधायक शामिल हैं। इसके उलट शरद पवार अब भी दावा कर रहे हैं कि रांकापा उनके भतीजे व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बजाय उनके साथ है। कांग्रेस के 44, रांकापा के 54 व शिवसेना के 56 विधायकों तथा कुछ निर्दलीयों के साथ नए गठबंधन ने 162 विधायकों की सूची दी है। दोनों सूचियां बहुमत के 144 के आंकड़े

से अधिक हैं। पूरे प्रकरण में रिजार्ट की राजनीति भी हुई ताकि अपने विधायकों को प्रतियोगियों से बचाया जा सके। ऐसा लगता है कि जैसे विधायकों का अपना दिमाग नहीं है और उनको ललचाया या डराया जा सकता है। तथ्य यह है कि परंपरा अनुसार वे अपनी सीटों को संपदा मानते हैं और सबसे ज्यादा पैसा देने वाले के पास जाते हैं। निसंदेह देश में कई बार लोकतंत्र का मजाक उड़ चुका है और यह कटु सत्य है। हमारे राजनेताओं को यह अधिकार कौन देता है कि वे अशोभनीय आचरण करते हुए अपने पूर्व-घोषित विरोधियों के साथ चले जांए? विधायकों को परेड कराने की राजनीति भी शुरू हो गई है। भ्रष्टाचार-विरोध व कांग्रेस मुक्त भारत की बात करने वाली भाजपा ने दागी अजित पवार का साथ लेना पसंद किया है। अजित पवार द्वारा शपथ लेने के दो दिन बाद 70,000 करोड़ रुपये के महाराष्ट्र सिंचाई घोटाले के 9 मामले बंद किए गए हैं। विडंबना है कि 2014 में मुख्यमंत्री बनने के बाद फडनवीस ने ये मामले दर्ज कराने का पहला काम किया था। ऐसा लगता है कि अब भाजपा ने बेशर्मी को सामान्य बना दिया है। लेकिन अभी यह विश्वास करना कठिन है कि मूल रांकापा प्रमुख शरद पवार विद्रोह के खिलाफ कठोर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? विधायक दल नेता के पद से हटाने के अलावा अजित पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। क्या बुजुर्ग मराठा नेता को आशंका है कि उनको पार्टी से निकालने पर बड़ी संख्या में उनके विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं? अजित पवार अब भी शरद पवार को रांकापा का नेता मानते हैं। अफवाहें हैं कि भतीजे को चाचा के खिलाफ खड़े होने की जरूरत नहीं है और केन्द्रीय कैबिनेट का विस्तार होने पर पवार की बेटी सुप्रिया सुले को उसमें स्थान मिल सकता है। इसे वर्तमान स्वरूप में लोकतंत्र की मौत कहा जा सकता है।

कृषि क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन

प्रस्तावित बीज विधेयक तथा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के कुछ प्राविधानों में संशोधन की आवश्यकता है। ये संशोधन बहुराष्ट्रीय निगमों का किसानों पर वर्चस्व रोकने के लिए जरूरी हैं।

संध्या जैन
लेखिका नेहरू स्मारक संग्रहालय व पुस्तकालय में वरिष्ठ फेलो हैं)

किसान संगठनों को प्रस्तावित बीज विधेयक, 2019 तथा कीटनाशक प्रबंधन विधेयक के प्राविधानों से चिन्ता है। ये किसानों के अधिकार कमजोर कर बीजों पर कार्पोरेट का नियंत्रण बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही 'किसान' की परिभाषा में परिवर्तन कर इसमें व्यापारियों व निगमों को शामिल किया गया है। 'किसान' की मूल परिभाषा में वाणिज्यिक आधार पर खरीद-बिक्री में शामिल किसी व्यक्ति, कंपनी, व्यापारी या डीलर को बाहर रखा गया था। भारतीय कृषक समाज अध्यक्ष कृष्ण बीर चौधरी ने जोर दिया है कि यह परिभाषा बनी रहनी चाहिए।

प्रारूप के अनुसार, 'किसान का अर्थ कोई भी व्यक्ति है जिसके पास खेती योग्य भूमि हो या किसानों की कोई अन्य श्रेणी जो केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा घोषित कोई भी कृषि कार्य करता हो।' इसमें 'किसान' को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पहचाना गया है जिसके पास धारा 11 के अनुसार कृषि भूमि हो। इससे भूमि पर स्वामित्व रखने वाले सभी निगम 'किसान' के रूप में ही परिभाषित किए जाने योग्य होंगे, जबकि बीज अधिनियम की धारा-47 के अंतर्गत नए अपवाद में बहुराष्ट्रीय निगमों को किसी भी विनियमन से बाहर रखा गया है।

विधेयक के प्रारूप में बीजों की नई वाणिज्यिक परिभाषायें शामिल की गई हैं जो हमारी समृद्ध जैव-विविधता संरक्षण के बजाय बहुराष्ट्रीय निगमों को बाजार में आसान प्रवेश की अनुमति देती हैं। वह किसानों को बीज बचाने व उनके विनिमय का अधिकार नहीं देता है जिसका विकास उन्होंने किया है वे और परिस्थितिकी व कृषि-मौसम क्षेत्रों के उपयुक्त उच्च गुणवत्ता वाले, विश्वसनीय तथा सस्ते बीज सुनिश्चित करते हैं।

विधेयक में 'राष्ट्रीय बीज किस्म' व 'राज्य बीज किस्म' जैसी अवैज्ञानिक परिभाषायें दी हैं। धारा 17 के अनुसार, 'राष्ट्रीय बीज किस्म' का अर्थ वे किस्में हैं जिनकी खेती एक से अधिक राज्यों में होती है तथा धारा 31 के अनुसार 'राज्य बीज किस्म' का अर्थ वे किस्में हैं जिनकी खेती केवल एक राज्य में होती है।

बीज, आनुवांशिक गुणों या ट्रेट की विविधता के साथ कृषि-मौसम क्षेत्रों को भी अभिव्यक्ति देते हैं जहां किसान वे किस्में पैदा करते हैं जो अनुकूलित हो चुकी होती हैं। बीजों को ट्रेट या कृषि-मौसम क्षेत्रों के बजाय एक से अधिक राज्यों में उगाने पर 'राष्ट्रीय बीज' और केवल एक राज्य में उगाने पर 'राज्य बीज' के रूप में परिभाषित करना अवैज्ञानिक है। यह मार्केटिंग तथा बहुराष्ट्रीय निगमों-एमएनसी के महंगे और अविश्वसनीय बीजों के प्रसार में सुविधा के लिए उपयुक्त है।

1966 के बीज अधिनियम के अनुसार नए बीजों का मूल्यांकन 22 कृषि-मौसम क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज सुनिश्चित हो सकें। आश्चर्यजनक रूप से 2019 के बीज विधेयक ने इसे वैकल्पिक बना दिया है। इसके अनुसार, 'समिति परीक्षण व मान्यता के आंकलन हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और ऐसे अन्य संस्थानों का चयन कर सकती है जो निर्धारित मानक पूरे करते हों। वे किसी प्रकार या बीजों की किस्म के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकते हैं।'

बीज विधेयक को बीजों की विफलता पर किसानों को मुआवजा सुनिश्चित करना चाहिए। इसके बजाय उसने बीजों की विफलता की स्थिति में किसानों को उपभोक्ता कानून के अंतर्गत मुआवजे की मांग करने के लिए छोड़ दिया है। यदि बीजों की विफलता पर कोई जिम्मेदारी न हो तो जिम्मेदारी प्राविधान का कोई अर्थ नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 के अनुसार पंजीकृत बीजों या किस्मों के उत्पादक, वितरक या विक्रेता को 'तत्कालीन स्थितियों के अनुसार किसानों को दिए जाने वाले बीजों या अन्य किस्मों की संभावित उम्मीदों की जानकारी देनी चाहिए।' यदि बीज उम्मीद के अनुसार सफल नहीं होते हैं तो किसान उत्पादक, डीलर, वितरक या विक्रेता से मुआवजे का दावा कर सकते हैं।

2019 में विधेयक का प्रारूप एक अनिवार्य बीज प्रमाणन विधेयक है जिसके अंतर्गत बीज उत्पादकों व बीज प्रसंस्करण इकाइयों को पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराना होगा। अनुच्छेद 12 के अनुसार किसानों को 'कथित रजिस्टर में किसानों की बीज किस्मों का पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।' लेकिन धारा 47 के अंतर्गत अपवाद के रूप में किसानों के अधिकारों को कमजोर किया गया है।

इसके साथ ही महत्वपूर्ण रूप से 'ट्रांसजेनिक बीजों' को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 24 में 'बीजों' की परिभाषा में 'सिंथेटिक बीजों' की नई श्रेणी जोड़ी गई है। धारा 44 ट्रांसजेनिक किस्मों को शामिल करने का रास्ता खोलती है जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेज़ल कमेटी-जीईएसी ने अनुमति दी हो। 'ट्रांसजेनिक किस्मों के पंजीकरण के विशेष प्राविधान' के अंतर्गत यह बताती है कि 'धारा 14 में जो भी हो, किसी ट्रांसजेनिक किस्म के बीज का पंजीकरण उस समय तक नहीं हो सकता है जब तक प्रार्थी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्राविधानों के अंतर्गत आवश्यक अनुमति न मिली हो।' लेकिन जैवविविधता नियामक एजेंसी विफल रही है। उसने बीटी काटन बीजों को अनुमति दी थी जो बेकार हो रहे हैं, उसने बीटी बैंगन को अनुमति दी जिसे मंत्री ने खारिज कर दिया तथा उसने बीटी सरसों को अनुमति दी जिसकी उपज देशी सार्वजनिक किस्मों से भी कम है तथा वह प्रतिबंधित खरपतवार नाशक ग्लूफोसिनेट प्रतिरोधी है। सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचने से ही इस व्यापारीकरण पर रोक लग सकी। अब नया बीज विधेयक बीटी बैंगन व खरपतवार प्रतिरोधी सरसों के व्यापारीकरण की अनुमति दे देगा।

1966 के अंतर्गत गठित केन्द्रीय बीज समिति में प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति शामिल होता था। 2019 के बीज विधेयक ने यह प्राविधान बदल कर केन्द्र द्वारा आवर्ती आधार पर पांच प्रतिनिधियों के नामांकन की व्यवस्था की है। इस बीच कृषि विभाग के बीज प्रभाग ने विक्रेताओं से एक्सप्रेशन आफ इंटेंट-ईओआई की मांग की है जिसके अंतर्गत 'नेशनल सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम' के लिए बीज पैकेटों पर बार-कोडिंग व्यवस्था अनिवार्य होगी। निश्चित रूप से यह कदम उठाने के लिए संसद को यह विधेयक पास करना होगा। कीटनाशक प्रबंधन विधेयक-पीएमबी में भारत में तकनीकी श्रेणी के कीटनाशकों का अनिवार्य पंजीकरण जरूरी होगा। यह कीटनाशक आयात या कीटनाशक फार्मूलों के स्वदेशी उत्पादन के लिए जरूरी होगा। यह व्यवहार प्रमुख कृषि प्रधान देशों जैसे, अमेरिका, यूरोपी, ब्राजील, चीन, आस्ट्रेलिया व अर्जेन्टाइना में लागू है।

पीएमबी में कृषि रसायनों तथा कीटनाशकों के लिए डेटा संरक्षण नहीं लागू होना चाहिए क्योंकि ऐसे प्राविधान से बहुराष्ट्रीय निगमों के एकाधिकार का विस्तार होगा। इनको पहले ही डब्लूटीओ के पेटेंट संरक्षण में 20 साल का संरक्षण प्राप्त है और यह भारत में 2005 से लागू है। अतिरिक्ट डेटा संरक्षण का अर्थ पेटेंट की एवरग्रीनिंग होगा। कृषि रसायनों के क्षेत्र में डेटा के विशिष्ट संरक्षण से जेनेरिक्स के प्रवेश में विलम्ब होगा तथा भारतीय किसानों के लिए कृषि रसायनों व कीटनाशकों की कीमतें बहुत अधिक हो जाएंगी। कीटनाशकों की सूची कीटनाशक अधिनियम, 1968 का अभिन्न अंग है। इससे प्रार्थियों व नियामकों को यह तय करने में आसानी होती है कि पंजीकरण आवश्यक है या नहीं।

पीएमबी द्वारा निर्यात पर कठोर नियमन से कीटनाशकों के निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जबकि कीटनाशकों के निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है तथा स्वदेशी कृषि रसायन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। कीटनाशक उत्पादों के लिए निर्यात के आदेश समयबद्ध होते हैं और वे विभिन्न देशों में कृषि मौसम के अनुसार होते हैं। इनकी समय पर आपूर्ति आवश्यक होती है नहीं तो ग्राहक कहीं और जा सकते हैं। सभी आयातकर्ता देशों के अपने नियमन व पंजीकरण कानून होते हैं जिसे प्रत्येक निर्यातकर्ता को पूरा करना होता है। इसलिए अनावश्यक डेटा आवश्यकताओं को थोपना तथा निर्यातोन्मुख उत्पादों में अनुचित कमियां पैदा करने से उनकी कीमत बढ़ेगी तथा सप्लाई में विलम्ब होगा। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटा को पंजीकरण अधिकारियों द्वारा स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि निर्यात अलग-अलग देशों के अनुकूल होते हैं। प्रस्तावित विधायनों को पास करने के पहले कृषि मंत्रालय को इन मुद्दों का सावधानी से समाधान करना चाहिए।

बीजिंग को स्वीकार्य नहीं हांगकांग में लोकतंत्र

गुइन डायर
(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)

हांगकांग में मौन बहुसंख्यक, जिनके बारे में हुकूमत के समर्थकों को उम्मीद है कि वे लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों से तंग आ चुके हैं और पिछले पांच महीनों में शहर को हिलाकर रख दिया है, अब न केवल मौन बल्कि गैर अस्तित्वमान हो चुके हैं।

रविवार को जिला काउंसिलों के चुनावों की शुरुआत में, अधिसंख्य काउंसिलों पर बीजिंग समर्थक पार्टियों का नियंत्रण था। समय के साथ-साथ लगभग तीन मिलियन वोट 24 नवंबर की रात को गिने गए थे, 18 में से 17 काउंसिलें लोकतंत्र समर्थक काउंसेलरों के हाथों में थीं। यह महान विजय थी, लेकिन हांगकांगवासियों को फिर भी लोकतंत्र नहीं हासिल होने वाला।

जिला कौंसिलें महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेती हैं, वे मुख्यत: बसों की समय सारिणी एवं कचरा एकत्र करने जैसे काम संभालती हैं, और विशुद्ध रूप से यही कारण है कि बीजिंग में बैठी हुकूमत उन्हें वास्तविक लोकतंत्र बनने दे रही है। हालांकि, इस बार, कौंसिलों के चुनाव इस पर जनमत संग्रह की तरह हैं कि हांगकांग के नागरिक अभी भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हैं, और यह जाहिर भी हो गया कि वे करते हैं।

प्रशासन के उच्च स्तरों पर, जहां अधिक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, लोकतंत्र अनुपस्थित नजर आता है। सरकार का मुखिया, मुख्य कार्यकारी होता है जिसका चयन 12,00 सदस्यों की एक समिति के द्वारा किया जाता है, जिनमें से एक दस से भी कम लोकप्रिय मत द्वारा चुने जाते हैं। उनकी पसंद को बीजिंग में विद्यमान सरकार की मंजूरी लेनी होती है। यह व्यवस्था बदलने वाली नहीं है, क्योंकि चीनी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता सदैव सत्ता के कम्युनिस्ट एकाधिकार को संरक्षित रखना है और वह अपने भूक्षेत्र में कहीं भी पूर्ण लोकतंत्र स्थापित होना स्वीकार नहीं करेगी। हांगकांग में लोकतंत्र व्यापक देश में अन्य स्थानों पर रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक उदाहरण बन सकती है, अत: इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती।

यह सच है कि हांगकांग के लोगों को वे

अधिकार प्राप्त हैं जो अन्य चीनियों को प्राप्त नहीं है, जैसे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र न्यायालय। यह एक देश, दो व्यवस्थाओं की गारंटी 50 वर्षों के लिए चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा पत्र 1997 के द्वारा दी गई थी, जब ब्रिटेन ने हांगकांग उपनिवेश को वापस चीन को सौंप दिया था। हालांकि, उसमें अनियंत्रित लोकतंत्र का वादा शामिल नहीं था। आगामी मूलभूत कानून जो हांगकांग के संविधान की तरह काम करता है, यह नहीं कहता कि अंतिम ध्येय है मुख्य कार्यकारी का सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा चुना जाना, लेकिन कोई भी वकील यही कहेगा कि अंतिम ध्येय एक ऐसी चीज है जिसे सदा के लिए टाला जा सकता है। बेहतर गारंटी यह तथ्य है कि बीजिंग सरकार की दिलचस्पी शहर को ऐसा बनाए रखने में है जहां विदेशी बिजनेस प्रसन्न रहें जिसके लिए कानून का शासन व अदालतों का स्वतंत्र होना आवश्यक है। लेकिन, अभी यह केवल सशर्त गारंटी है, क्योंकि बीजिंग की सर्वोच्च प्राथमिकता बिजनेस के बजाए नियंत्रण करना है। प्रदर्शनकारियों ने उल्लेखनीय रूप से अपनी प्रतिबद्धता व सफलता अभिव्यक्त की है। उन्होंने मुख्य कार्यकारी, कैरी लैम, को प्रस्तावित कानून त्यागने पर मजबूर किया है, तथा उन्होंने हांगकांग निवासियों के प्रत्यर्पण तथा चीन अदालतों में सुनवाई को रोकने में सफलता पाई है। इससे शहर में कानून का शासन मजबूत हुआ है क्योंकि चीनी अदालतें वही करती हैं जो सरकार चाहती है।

पहले स्थान पर, लैम संभवत: बीजिंग को चेतावनी देना चाहती थीं कि यह एक बुरा विचार है, लेकिन वो स्वतंत्र नहीं थीं। कई महीने पूर्व, उन्होंने एक निजी बिजनेस मीटिंग में यह कहा था। उनको दो मालिकों, बीजिंग व हांगकांग की जनता की सेवा करनी थी, और इसके लिए गुंजाइश अत्यधिक सीमित थी। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि मुझे पसंद करने का अवसर मिलता तो मैं हृदय से माफी मांगकर इस्तीफा दे देती।

लेकिन, उनके पास अपनी पसंद का अवसर नहीं था, न ही उनके पास ऐसा कोई अवसर था जहां वो विरोधियों को रियायतें दे सकती थीं। बीजिंग द्वारा प्रत्यर्पण कानून वापस लिए जाने के बाद इन चुनाव परिणामों से उसे समझ लेना चाहिए कि थोड़ा आगे बढ़ने की आवश्यकता है। यदि लैम विरोधियों की मांगों पर थोड़ा आगे बढ़ती हैं तो प्रदर्शकारी इसे अपनी विजय के रूप में प्रकट करेंगे। उनको सभी गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को माफी देने तथा कथित पुलिस अत्याचारों की स्वतंत्र जांच का आदेश देने चाहिए। यह प्रदर्शनकारियों की विजय होगी क्योंकि उनकी प्रतिबद्धता ने बीजिंग को हांगकांग पर आने वाले वर्षों में नियंत्रण बढ़ाने से फिलहाल रोक दिया है।

यदि वे मुख्य कार्यकारी तथा विधायिका से सबको मताधिकार देने वाले स्वतंत्र चुनावों की मांग करते हैं तो देर-सबेर बीजिंग हस्तक्षेप करने को मजबूर हो जाएगा, तथा इससे भले ही चाहे जितना वित्तीय या छवि का नुकसान हो, उनको कुचल देगा। अब हम यहां से कहां जा सकते हैं? यह कहना कठिन है। प्रदर्शनकारी वार्ता के माध्यम से एक बड़ी बाधा पार करने में सफल हुए हैं और वे स्वीकृत नेता बनाने से बचे हैं। यह बात समझ में आती है क्योंकि किसी निश्चित नेता को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता। मगर इससे समझौता करने में कठिनाई होती है। प्रदर्शनकारियों के केंद्र में रहे छात्र निश्चित रूप से शक्तिशाली हैं। अत:, उनको दूरगामी दृष्टिकोण से सोचते हुए त्रासदी से बचना होगा।

आप की बात

लोकतंत्र पर भारी राजनीति

महाराष्ट्र में देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को झकझोर देने वाला सत्ता हासिल करने का दंगल अब चरम पर पहुंच गया है। राज्य में देश के शीर्ष राजनीतिज्ञों के द्वारा पूरे जोशोखरोश के साथ पिछले एक माह से जबदस्त सियासी राजनीति की ऐसी कुटिल चाले चली जा रही हैं, जो कि इस जबरदस्त सियासी घमासान को खत्म होने देने का नाम ही नहीं ले रही हैं। देशवासियों को लगता है कि इस घटनाक्रम का अब जल्द ही पटाक्षेप हो जाये और राज्य को नई स्थाई सरकार मिल जायेगी, लेकिन राजनीति की साम दाम दंड भेद वाली चाणक्य नीति के चलते देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री व अजीत पवार के उप मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद भी सरकार की स्थिति स्पष्ट नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति के महासंग्राम में जहां एकतरफ भाजपा सत्ता बरकरार रखने के लिए इस युद्ध को जीतना चाहती है। वहीं शिवसेना, एनसीपी व कांग्रेस के सत्ता हासिल करने की जबरदस्त चाह में, ये दल भी कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। जिस तरह से सत्ता हासिल करने के लिए रातों रात छिपकर सरकार बनाने वाली पार्टी विद डिफरेंस की बात करने वाली भाजपा व अन्य दल सत्ता पर काबिज होने की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है।

– **दीपक कुमार त्यागी**, मेल से

संसद में अनुशासन

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जिन्होंने पिछले लोकसभा सत्र में 108 प्रतिशत कार्य-निष्पादन का रिकॉर्ड बनाया था, इस सत्र में अनुशासन स्थापित करने के मामले में और अधिक सतर्क नजर आ रहे हैं। उन्होंने सदन के वेल में आकर बेनर लहरा रहे दो कांग्रेस सदस्यों, टीएन प्रतापन और हीबी इडन, को एक दिन के लिए सदन से निलंबित करते हुए मार्शलों द्वारा बाहर करवा दिया। लगभग 50 वर्ष बाद ऐसी घटना घटी है। तीसरी से पांचवी लोकसभा में तो यह कार्य अक्सर ही होता रहता था। राम मनोहर लोहिया सांसद थे। लगभग प्रत्येक सप्ताह उन्हें मार्शल उठाकर सदन से बाहर ले जाते थे। सुश्री तारकेश्वरी सिन्हा केन्द्रीय मंत्रिमंडल में थीं। उनकी अक्सर लोहियाजी से नोक-झोंक हो जाती एक दिन स्पीकर ने पुन: लोहियाजी को सदन से निकालने का आदेश दिया। मार्शलों ने उन्हें उठाकर बाहर ले जाना प्रारंभ किया, तो वे सुश्री सिन्हा की ओर इशारा करके बोले, हम ही जब न होंगे इस महफ़िल के अंदर, किसे देखकर आप शरमाइयेगा? सारा सदन खिलखिला उठा। अनुशासन कठोरता के साथ-साथ जिदादिली के उदाहरण उन दिनों आम थे अब सदन की प्रतिष्ठा जन-सामान्य की दृष्टि में भी गिर गई है।

– **अजय मित्तल,** मेरठ

नवीन तकनीक के लाभ

स्नातक स्तर तक साक्षरता दरों में सुधार हुआ है और यह 79.63 प्रतिशत तक पहुंच गई है। लेकिन प्राथमिक साक्षरता की 46 प्रतिशत दर बढ़ाने की आवश्यकता है। मानव पूंजी सूचकांक में भारत की कम दरों में सुधार के लिए नीति आयोग ने शिक्षा पर आबंटन को वर्ष 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद-जीडीपी के 6 प्रतिशत तक बढ़ाने का सुझाव दिया है जो वर्तमान समय में 3 प्रतिशत है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत लंबे समय तक गतिहीन रही है और हम चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार नहीं हैं। ई-कक्षाओं के माध्यम से आनलाइन शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के माध्यम कौशल प्रशिक्षण दे कर सरकारी स्कूलों की शिक्षण गुणवत्ता में सुधार किया जा सकता है। गावों में स्कूलों की संरचना ठीक नहीं होती है औरशिक्षक-छात्र अनुपात भी खराब है। बाइजू जैसे ई-लर्निंग मंच हैं जो पूरे देश में लोकप्रिय हो रहे हैं, लेकिन इनके बारे में जागरूकता की अभी कमी है। डिजिटलीकरण से महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों तथा प्रथम व द्वितीय श्रेणी के शहरों में 'घर पर रह कर रोजगार' की संभावनायें पैदा हो सकती हैं।

– **सुमन वर्मा**, आगरा

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते है।

फरमाया

संसद में आज हुई घटना से मैं आहत हूं। यह अस्वीकार्य है और इसे सहन नहीं किया जाएगा।

– **ओम बिड़ला**
लोकसभा अध्यक्ष

सुरक्षाकर्मियों ने हमारी महिला सांसदों से अभद्रता की। हमें कभी संसद के भीतर ऐसा अनुभव नहीं हुआ था।

– **अधीर रंजन चौधरी**
कांग्रेस नेता

हांगकांग में चाहे जो स्थिति हो, यह पूर्णत: स्पष्ट है कि विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के रूप में यह चीन का हिस्सा बना हुआ है।

– **वांग यी**
चीनी विदेश मंत्री

हजरतगंज स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात मंत्रिमंडल सहयोगियों के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

संविधान दिवस पर सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते मुख्यमंत्री

महात्मा गांधी की प्रतिमा पर भी मुख्यमंत्री ने किया माल्यार्पण

कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया जाना ऐतिहासिक फैसला : राज्यपाल

- कांग्रेस ने किया विशेष सत्र का बहिष्कार
- विधानमंडल सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

संविधान दिवस की 70वी वर्षगांठ के मौके पर विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र आहूत किया गया। इसके संयुक्त अधिवेशन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दोनों सदनों के सदस्यों को संबोधित किया। इस मौके पर कांग्रेस के सदस्यों ने सत्र का बहिष्कार किया। देर शाम विधानसभा सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

सत्रह मिनट के सम्बोधन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और उसकी भावी योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। अपने अभिभाषण के दौरान राज्यपाल ने केन्द्र सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35ए हटाए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में एक विधान, एक निशान और एक संविधान का सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की जनकल्याणकारी विभिन्न योजनाओं को राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना, कुंभ तथा अयोध्या में दीपावली के मौके पर आयोजित समारोह का उल्लेख करते हुए कहा कि इन आयोजनों से स्पष्ट है कि प्रदेश सरकार जनाकांक्षाओं की कसौटी पर खरी उतरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां 25 लाख से अधिक आवास निर्मित किए गए। प्रधानमंत्री आवास निर्माण में उत्तर प्रदेश ने देशभर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि स्वच्छता अभियान को जन-जन तक पहुंचाने की गरज से ग्रामीण क्षेत्रों दो करोड़ 61 लाख इज्जत घर देकर देश भर में यूपी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके साथ प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में अर्न्तगत 96 हजार गरीब कन्याओं का विवाह संपन्न कराया गया। राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन के अंर्तगत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, किशोरी बालिका सशक्तीकरण योजना सबला, स्वाधार योजना, उज्जवला योजना, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना तथा महिला हेल्पलाइन जैसी योजनाओं का प्रदेश में सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस की सार्थकता के अभी काफी प्रयास किए जाने शेष हैं। इस मौके पर उन्होंने दोनों सदनों के सदस्यों का आवाहान किया कि अपने सामजिक जीवन में ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करें जिनसे नागरिकों में संवैधानिक चेतना का प्रसार हो। विधानसभाध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि भारत का संविधान भिन्न प्रकृति और प्रकार का है। कोई भी देश बिना नियमों और संविधान के नहीं चल सकता। देश के संविधान का इतिहास काफी प्राचीन है। ऐसा अनुकरणीय संविधान विश्व के किसी दूसरे देश में देखने को नहीं मिलता।

सपा सदस्यों ने संविधान बचाओ के नारों के साथ किया प्रदर्शन

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

विधान भवन परिसर में स्थित चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्थल पर विधानमंडल विशेष सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों ने लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ के नारों के साथ जबर्दस्त प्रदर्शन किया। सपा विधायकों द्वारा गन्ना, धान की बोरी और बिजली मीटर के साथ जनसमस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया। विधानसभा में नेता विरोधी दल रामगोविन्द चौधरी, नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद अहमद हसन, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल के साथ, राजपाल कश्यप, राजेश यादव, नफीस अहमद, आनन्द भदौरिया एवं संग्राम सिंह के अलावा नवनिर्वाचित विधायक डॉ. तंजीम फातिमा, सुभाष राय एवं गौरव रावत सहित सभी विधायकगण इस प्रदर्शन में शामिल थे।

महाराष्ट्र सहित कई प्रदेशों में भाजपा ने संविधान की धज्जियां उड़ाईं: रामगोविन्द चौधरी

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- संविधान की दुहाई वो लोग दे रहे हैं जिन्होंने सदनों में मारपीट तक की: सुरेश कुमार खन्ना

विधानमंडल के एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान विधानसभा में चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राम गोविन्द चौधरी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण सुनकर नहीं लगा कि यह संविधान दिवस का भाषण था, बल्कि लग रहा था कि यह राज्यपाल का बजट अभिभाषण है। उन्होंने कहा कि इस सत्र के जरिये विपक्ष को धोखा दिया गया है। संविधान को सामने रखकर सरकार ने अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कम से कम संविधान पर चर्चा करने के लिए कम से कम दो दिन का सत्र आहूत होना चाहिए था। संविधान दिवस के मौके पर यह सत्र केवल सरकार द्वारा अपनी उपलब्धियां बखान करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि संविधान दिवस मना रही सरकार ने सबसे ज्यादा संविधान की हत्या की है उसकी मर्यादा को तार-तार किया है। चार दिन पहले जो महाराष्ट्र में हुआ वह सबके सामने है।

महाराष्ट्र में जिस दल ने दावा ही नहीं किया उसकी सरकार बनवा दी गयी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र से पहले बिहार, कर्नाटक, अरूणांचल प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाई गयीं। प्रदेश तोड़ने, दिल तोड़नेवाली भारतीय जनता पार्टी का वश चले तो वह अपने स्वार्थ के लिए देश भी तोड़ दे। उन्होंने भाजपा पर राज्यों को खण्डित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाया गया वैसे नागालैण्ड से 371ए क्यों नहीं हटायी गयी। संविधान की आड़ में लोगों में नफरत पैदा की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा और उसकी सरकारों ने संवैधानिक संस्थाओं को भी अपनी कठपुतली बना लिया है। चुनाव आयोग भी निष्पक्ष नहीं रह गया है। नेता प्रतिपक्ष के इन तर्कों को खारिज करते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा इस सदन में राज्यपाल की भूमिका पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संविधान की दुहाई वो लोग दे रहे हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा सदनों में हंगामा, मारपीट और हाथापाई की।

बसपा विधान मण्डल दल के नेता लालजी वर्मा ने कहा कि भाजपा और उसकी सरकार ने संविधान दिवस पर संविधान की गरिमा गिराने का काम किया है। सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ानेवाली भारतीय जनता पार्टी आज लोगों को संविधान की प्रासंगिकता समझा रही है। संविधान विरोधी कृत्यों को अंजाम देने में भाजपा का कोई सानी नहीं है। राज्यपाल के अभिभाषण में जो भी उपलब्धियां गिनायी गयी हैं। हकीकत से वे सब कोसों दूर हैं। इस चर्चा में अपना दल के नेता नीलरतन पटेल ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में जनता से किये गये वायदों को अमलीजामा पहनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहा सो किया के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। इस चर्चा में कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, बेसिक शिक्षा मंत्री डॉ.सतीश द्विवेदी, विधायक पंकज सहित सदन के अन्य सदस्यों ने भी हिस्सा लिया।

राज्यपाल ने राजभवन में दिलायी मूल कर्तव्यों के पालन की शपथ

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज यहां राजभवन के गांधी सभागार में संविधान दिवस के अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भारत के संविधान में दिए गये मूल कर्तव्यों के पालन की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव राज्यपाल हेमन्त राव, राज्यपाल के परिसहाय डॉ अभिषेक महाजन, विशेष सचिव डॉ अशोक चन्द्र, विधि परामर्शी संजय खरे, अपर विधि परामर्शी कामेश शुक्ला, विशेष कार्याधिकारी केयूर सम्पत सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने शपथ ली।

आकाश और आनंद के नाम पर फैलाया जा रहा है भ्रम: मायावती

लखनऊ। सोशल मीडिया में आकाश आनंद और आनंद कुमार को लेकर चल रही भ्रामक बातों को लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मायावती ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद और अब आनंद कुमार के नाम पर भी आए दिन सोशल मीडिया में अनेक प्रकार की गलत, तथ्यहीन व भ्रामक बातें प्रचारित की जा रही हैं, जिससे बीएसपी के लोग सावधान रहें। उन्होंने कहा है कि पार्टी के नाम पर इनका सोशल मीडिया में कोई भी अकाउंट नहीं है। इससे पूर्व अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए संविधान दिवस पर मायावती ने देश की जनता को बधाई देते हुए कहा कि संविधान दिवस पर संविधान शिल्पी बाबा साहेब डॉ.भीमराव अम्बेडकर का केवल नाम जपते रहने से काम नहीं चलेगा क्योंकि यही छल कांग्रेस भी करती रही है बल्कि केन्द्र व राज्य सरकारों को संविधान की जनहिताय,

समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है यूजीसी: प्रो. डीपी सिंह

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

- संविधान दिवस पर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय में संगोष्ठी आयोजित

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन प्रो. डीपी सिंह ने कहा है कि यूजीसी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है। शिक्षा का उद्देश्य अच्छे नागरिकों का विकास करना है। हम श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित हो सकें इसके लिए संवेदनशील और सजग रह कर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि यूजीसी ने बहुत सी ऐसी गतिविधियां शुरू की हैं जिसके माध्यम से संविधान के मूल में निहित सत्य, अहिंसा, शांति, दया, करूणा, प्रेम जैसे भावों को विद्यार्थियों में विकसित करने का प्रयास किया जायेगा। प्रो. सिंह मंगलवार को संविधान दिवस पर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय के स्कूल आफ लीगल स्टडीज द्वारा आयोजित संगोष्ठी को सम्बोधित कर रहे थे।

इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल, इकनोमिक, पॉलीटिकल जस्टिस-इश्यूज़ एंड चैलेंजेज़ विषय पर पक्ष रखते हुए यूजीसी के चेयरमैन ने कहा कि हम संविधान की प्रस्तावना के अनुरूप कार्य कर रहे हैं ताकि उसके मूल भाव को विद्यार्थियों में पोषित कर सकें। प्रो. डीपी सिंह ने कहा कि हमे अपनी संवैधानिक मर्यादा और कर्तव्यों के प्रति सजग रहते हुए देश के विकास में योगदान करना होगा। आज हम अपना 70 वां संविधान दिवस मना रहे हैं, इतने लंबे कालखंड और उतार-चढ़ाव के बाद भी हमारा संविधान प्रासंगिक है। हमारे देश ने संविधान के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाई है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. एसके भटनागर ने कहा कि 70 साल बाद भी भारतीय संविधान प्रासंगिक है तो इसका मुख्य कारण इसका लचीलापन है जो यथास्थिति को बनाए रखने वाला नहीं है। यह एक बदलाव का दस्तावेज है, जिसका मुख्य उद्देश्य बदलते समाज में न्याय और कानून को बरकरार रखना।

संविधान व संस्थानों को बचाना हो हर भारतीय की प्राथमिकता

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा है कि 26 नवम्बर 1949 को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अगुवाई में भारत के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित गया था। संविधान में ही नागरिकों की स्वतंत्रता और चतुर्दिक सुरक्षा का मूल निहित है। इस संविधान से ही हम भारतीयों को समानता और सम्मान से जीने का अधिकार मिला। लेकिन मौजूदा सत्ता में इसकी मौलिकता पर हो रहा प्रहार हमें एकजुट हो इसकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध करता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में संविधान एवं संस्थानों को बचाना हर भारतीय की प्राथमिकता होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने यह बात मंगलवार को पार्टी मुख्यालय के डॉ. राममनोहर लोहिया सभागार में कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कही। इस मौके पर छिबरामऊ कन्नौज की कु. मन्नू पाल ने जो यशभारती सम्मान प्राप्त लॉन बाउल्स की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं तथा इलाहाबाद के कुछ छात्र नेताओं ने भी भेंट की। उन्होंने कहा कि छात्रसंघ के चुनाव होने चाहिए। इसके साथ ही जिला चंदौली के ग्राम बेनशहाबगंज के गनेश यादव और ग्राम बरहुआ सैदपुर के रामभजन मौर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से भेंट की। इसके अलावा उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के एडवोकेट एवं सामाजिक.धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े दिवाकर चमौली भेंट करने वालों में रहे। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में सघन जनसम्पर्क करते रहें। संविधान बचाने के लिए जागरूकता आवश्यक है। हमें संविधान की मूलभावना की जानकारी जनता तक पहुंचाना होगा। अखिलेश यादव ने कहा कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भाजपा सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना अपना राजनीतिक कर्म मानती है। नैतिक मूल्यों के प्रति भाजपा की रूचि नहीं है। वह येनकेन प्रकारेण सत्ता से जुड़कर अपने स्वार्थ साधन में लगी रहती है। उससे राजनीति में शुचिता तथा पारदर्शिता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। यह लोकतंत्र के साथ धोखा है।

संविधान दिवस पर निकाला गया मार्च पास्ट

- न्यायिक, प्रशासन व पुलिस अधिकारी हुए शामिल
- अपने कर्तव्यों की सही तरीके से पालन करें : जनपद न्यायाधीश

संविधान दिवस पर शहर में मार्च पास्ट निकालते अधिकारी

ललितपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ से प्राप्त निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 26.11.2019 को 'संविधान दिवस' के अवसर पर जनपद न्यायालय, ललितपुर से रिजर्व पुलिस लाइन ललितपुर तक एवं रिजर्व पुलिस लाइन ललितपुर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का प्रारम्भ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यापर्ण एवं दीप प्रज्जवलन किया गया। तत्पश्चात प्रांगण में जनपद न्यायाधीश द्वारा स्काउट गाइड व एन.सी.सी. कैडेट्स के साथ मार्च पास्ट को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया एवं प्रमुख मार्गो से होते हुए रिजर्व पुलिस लाइन ललितपुर पहुंचा। रैली में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जनपद न्यायालय के न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक/पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण सहित लगभग 500 जन द्वारा प्रतिभाग किया। रिजर्व पुलिस लाइन ललितपुर में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम जनपद न्यायाधीश द्वारा उपस्थित समस्तजन को संविधान की प्रस्तावना एवं मूल कर्तव्यों के अनुपालन की शपथ दिलायी गयी। मंचासीन अतिथियों द्वारा संविधान दिवस के अवसर पर अपने अपने विचार प्रकट किये गए। जनपद न्यायाधीश मदन लाल निगम ने भारतीय नागरिकों के अधिकारों के बारे में बृहद रूप से अवगत कराया गया एवं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों का समायोजन एवं उसकी उपयोगिता पर बल दिया गया। यदि हम अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन करेगें तो अधिकारों की आवश्यकता नहीं होगी। डीएम योगेश कुमार शुक्ल ने भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त समरसता के मौलिक अधिकार के द्वारा ही आमजन को भी उच्चतम पद तक पहुंचने के समान अवसर प्राप्त होने एवं प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय संविधान पर गर्व होने एवं भारतीय नागरिक के रूप में प्रत्येक व्यक्ति को ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु प्रेरित किया गया। एसपी एम.एम. बेग ने संविधान की पृष्ठभूमि एवं संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार में नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी का दायित्व निर्धारण स्वीकार करते हुए मूल कर्तव्यों में पर्यावरण के प्रति सजग रहने जैसे कि प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करने एवं जल व वायु प्रदूषण से मुक्ति हेतु अधिकाधिक वृक्षारोपण करने हेतु दो सुगम अवसर जन्मदिन/सालगिरह प्राप्त होने और उनका भरपूर उपयोग करने हेतु सभी को प्रेरित किया गया। अपर जिला जज अनुपम गोयल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए किसी भी देश के नागरिकों की प्रसन्नता को उस देश का खुशहाल/उन्नतशील होने का पैमाना मानते हुए देश की विषम समस्याओं (जनसंख्या नियंत्रण एवं संशाधनो का उचित उपयोग) के निराकरण पर बल दिया। एडीजे उमेश कुमार सिरोही ने भारतीय संविधान दिवस मनाये जाने के औचित्य के रूप में अधिकार और कर्तव्य दोनों को एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में बताया गया एवं एक दूसरे के अभाव में एक-दूसरे का अस्तित्व स्वत: समाप्त होने संबंधी अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये गये। प्राचार्य दिनेश बाबू ने संविधान में प्रदत्त विधि व्यवस्था के द्वारा नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ-साथ राज्यों के संचालन की व्यवस्था पर प्रकाश डाला एवं संविधान में आम नागरिकों को प्रदत्त अधिकार एवं कर्तव्यों के निर्वहन पर बृहद रूप से अवगत कराया गया। एनसीसी कमाण्डेण्ट नेमवि डा.पंकज शर्मा ने भारतीय नागरिकों को अपनी स्वतंत्रता एवं सम्प्रभुता व सांस्कृतिक परम्पराओं को अक्षुण बनाये रखने की प्रेरणा, भारतीय संविधान से प्राप्त होना बताया एवं भारतीय संविधान के निर्माण के इतिहास पर प्रकाश डाला गया। विधि छात्र पुष्पेन्द्र सिंह ने भारत के संविधान के गठन हेतु विभिन्न देशों के संविधानों के अनुच्छेदों नीति निर्देशक तत्वों के समायोजन एवं विशालतम गणराज्य होने के कारण विशाल संविधान के गठन के औचित्य पर प्रकाश डाला गया। जिसकी मूल प्रति को लिखने वाले द्वारा इटेलिक अक्षरों के प्रयोग को छ: माह के अनथक परिश्रम के द्वारा संविधान को मूर्तरूप प्रदान किया गया। इस संविधान में भारतीय नागरिकों से अधिकारों एवं कर्तव्यों के ईमानदारी से पालन करने की अपेक्षा की गयी। संचालन डा. अनुपम गोयल, अपर जिला जज (एफटीसी) द्वारा किया गया एवं सूरज मिश्रा सिविल जज (सी.डि.)/प्रभारी सचिव द्वारा सभी आगुन्तकों का आभार प्रकट किया गया।

इस दौरान जगदीश कुमार, अपर जिला जज (एससी/एसटी एक्ट), मनोज कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अजय पाल सिंह, अपर जिला जज (डकैती), निर्भय प्रकाश, अपर जिला जज (एफटीसी-2), रवि कुमार गुप्त, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनोज कुमार तिवारी, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनुभव कटियार, सिविल जज (जूडि), प्रज्ञा सिंह, सिविल जज (जूडि), गरिमा सक्सेना अपर सिविल जज (जूडि), अर्चना सक्सेना, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनिल कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी, पीयूष चन्द्र राय, जिला सूचना अधिकारी, मनोज कुमार सरोज, तहसीलदार ललितपुर, श्रीप्रकाश चौबे एड., अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, हरीराम निरंजन एड., मंत्री जिला अधिवक्ता संघ व अधिवक्ता संघ के विद्वान अधिवक्तागण, राजेश दुबे एड., डीजीसी क्रिमिनल, बृजेन्द्र सिंह यादव, एडीजीसी क्रिमिनल, पत्रकारों में कृष्णबिहारी उपाध्याय, शैलेन्द्र जैन, लकी जैन, अविनाश त्रिपाठी, रविन्द्र दिवाकर, सुनील जैन, केदार नाथ तिवारी, निदेशक शिक्षक/शिक्षिका अरविन्द सिंह, द्रोपदी सिंह,चन्द्रशेखर सोनी, राजेश साहू, मनोज कुमार झां, राजीव निरंजन जिला संगठन कमांडेण्ट, स्काउट गाइड, नेहरू महाविद्यालय, श्रीवर्णी जैन इंटर कॉलेज व राजकीय इण्टर कॉलेज के एनसीसी/स्काउट गाइड के छात्र-छात्राएं, पुलिस बल, न्यायालय, प्रशासन एवं पुलिस विभाग के कर्मचारीगण एवं आम नागरिक उपस्थित हुये।

रांची में झारखण्ड विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन, उनके पुत्र हेमंत सोरेन व पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण

महाराष्ट्र के सियासी खेल के नायक बने राकांपा नेता शरद पवार

भाषा। मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष शरद पवार ने गत 21 अक्टूबर को हुए विधानसभा चुनाव के लिए महाराष्ट्र के सतारा में बारिश के बीच चुनावी रैली को संबोधित किया था लेकिन तब कुछ ही लोगों को अहसास होगा कि 79 वर्षीय पवार राज्य की नई सरकार के मुख्य कर्ता-धर्ता होंगे। शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रही हैं और भाजपा विरोधी इस गठबंधन को मूर्त देने तथा भाजपा को सत्ता से बेदखल करने में पवार की अहम भूमिका रही। विधानसभा चुनाव में अपनी मेहनत के बल पर पवार अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही राकांपा को मजबूत स्थिति में ले आए लेकिन उनकी कोशिशों को उस समय झटका लगा जब भतीजे ने उन्हें स्तब्ध करते हुए भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली।

भाजपा की यह सरकार अजित पवार के निजी कारणों से उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने और उसके कुछ घंटे बाद ही देवेंद्र फडणवीस के भी मुख्यमंत्री पद छोड़ने के ऐलान करने से पहले महज 80 घंटे ही अस्तित्व में रही और गैर भाजपा गठबंधन की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले राकांपा को कई झटके लगे थे लेकिन शरद पवार ने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी ली और पूरे राज्य का दौरा किया। उनकी कोशिशें रंग लाईं और पार्टी 288 सदस्ईय सदन में 54 सीटें जीतकर आई, जो 2014 के मुकाबले 13 सीटें अधिक है। निर्भीक शरद पवार राज्य में सरकार बनाने और भाजपा को सत्ता से दूर रखने में सभी को जोड़ने वाली ताकत के रूप में उभरे। उनका 52 साल का राजनीतिक करियर है जिसमें वह रक्षा मंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और तीन बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। शरद पवार सात-सात बार महाराष्ट्र विधानसभा और लोकसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं। वह 27 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने और 38 साल की उम्र में कांग्रेस की सरकार गिरा दी।

राकांपा अध्यक्ष को 1978 में उस समय ख्याति मिली जब उन्होंने वंसंतदादा पाटिल की सरकार गिराकर जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। उस समय उनकी उम्र मात्र 38 साल थी और वह महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री थे। शरद पवार जून 1988 से जून 1991 और मार्च 1993 से मार्च 1995 तक मुख्यमंत्री रहे। वे जून 1991 और मार्च 1993 तक देश के रक्षामंत्री रहे।

विद्युत विभाग की घर बैठे बिल देने की योजना

बरेली। विद्युत विभाग अब उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए घर बैठे बिल लेने की योजना पर काम कर रहा है। इसके लिए जल्द ही पेटीएम कंपनी, बिलिंग एजेंसी और मध्यांचल निगम के बीच समझौता होने जा रहा है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ ही स्थानों पर शुरू किया जाएगा। बाद में इसे वृहत रूप दिया जाना है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक संजय गोयल के मुताबिक अब उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए बिल जमा करने के लिए बिलिंग केंद्रों पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अब उपभोक्ता घर बैठे ही मीटर रीडर के पेटीएम पर नगद बिल जमा कर सकेंगे। उपभोक्ता को तुरंत रसीद भी मिल जाएगी। उपभोक्ता चाहे तो मीटर रीडर के पेटीएम पर नगद बिल जमा कर सकता है। इसके लिए मीटर रीडर को अतिरिक्त पारिश्रमिक मिलेगा पर उपभोक्ता से कोई सर्विस चार्ज नहीं लिया जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को मोबाइल पर मैसेज भी आ जाएगा। फिलहाल प्रदेश की राजधानी में अगले महीने से यह सेवा शुरू हो रही है। रीडरों के लिए एक परिचय पत्र भी जारी किया जाएगा। वे लोग अधिशासी अभियंता और एसडीओ को जानकारी और सूचना भी देंगे। एजेंसी के मीटर रीडर पेटीएम कंपनी की ओर से ई वालेट बनाकर रकम क्रेडिट करेंगे। इसकी गारंटी बिलिंग कंपनी को लेनी पड़ेगी। मीटर रीडर उपभोक्ता से जितना कैश लेकर बिल जमा करेगा उतना पैसा ही उसके खाते से कट जाएगा।

संविधान दिवस पर लगा विधिक जागरूकता शिविर

बरेली। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के तत्वाधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली द्वारा शहर में संविधान दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया। बरेली मोहनपुर ठिरिया के साबरी पब्लिक स्कूल में लगे विधिक शिविर में छात्र व छात्राओं को देश के संविधान के प्रति जागरुक करने के लिए प्राधिकरण सचिव श्री हरिशचन्द्र उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय प्रतिमा द्वारा किया गया। सचिव हरिशचन्द्र द्वारा छात्र व छात्राओं को संविधान के बारे में बहुत ही स्पष्ट और सरल तरह से बताया गया साथ ही संविधान के शुरु होने और संविधान में हमारे नैतिक कर्तव्यों को भी श्री हरिशचन्द्र ने बताया। विधिक सेवा प्राधिकरण बरेली से अधिवक्ता आरपी शुक्ला द्वारा छात्र व छात्राओं को शपथ दिलाने के साथ शिविर का समापन किया।

पेज एक का शेष

महाराष्ट्र में ...

बाद शक्ति परीक्षण होगा। राज्यपाल कोश्यारी ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर मंगलवार की शाम कोलाम्बकर को अस्थायी विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया। न्यायालय ने बुधवार को शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है। राकांपा प्रवक्ता नवाब मलिक के अनुसार, उद्धव एक दिसंबर को शिवाजी पार्क में शपथ ग्रहण करेंगे। नेता चुने जाने के बाद उद्धव ने सोनिया गांधी और अन्य लोगों को धन्यवाद देते हुए कहा कि कभी उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन महाराष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। संयुक्त बैठक को संबोधित करते शिवसेना प्रमुख ने कहा कि परस्पर विश्वास रखते हुए वह लोग देश को एक नई दिशा दे रहे हैं। उनके लिए केंद्र में बैठे लोग नहीं बल्कि किसान ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हिंदुत्व पर अपने विचार रखते और भाजपा पर वार करते उद्धव ने कहा कि झूठ कभी भी हिंदुत्ववादी सोच का हिस्सा नहीं रही है। हाल की घटनाओं का परोक्ष हवाला देते उद्धव ने यह भी कहा कि वे अपनी सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्योता भेजेंगे। जबर्दस्त ड्रामे और सस्पेंस के साथ सिर्फ 80 घंटे पहले दूसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। इससे थोड़ी ही देर पहले राकांपा नेता अजीत पवार ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देकर उपमुख्यमंत्री की कुर्सी त्यागी थी। देश की वित्तीय राजधानी में एक महीने से जारी सत्ता के खेल की बाजी रातोरात पलटने वाली भाजपा को आज सुबह तब करारा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मुख्यमंत्री फडणवीस विधानसभा में बुधवार को ही बहुमत साबित करें। जिसके भरोसे पर शपथ ली थी- वह खंभा (अजीत पवार) ही ढह गया था। दूसरा कोई विकल्प था नहीं लिहाजा मायूस दिखते फडणवीस ने स्वीकार किया कि उनके पास संख्या बल नहीं रह गया है और फिर, राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। फ्लोर टेस्ट से पहले ही फडणवीस के इस्तीफा देने के पीछे प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मिला संदेश बताया जा रहा है। सर्वोच्च अदालत का फैसला आने के बाद मोदी और शाह ने बैठक कर महाराष्ट्र की मौजूदा स्थिति पर विचार किया। इसके पश्चात, फडणवीस से कहा गया कि वे राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दें। चार दिन पुरानी फडणवीस सरकार के गिरने के बाद घटनाक्रम तेजी से बदला। शिवसेना, राकांपा और कांग्रेस नेताओं ने ट्राइडेंट होटल में संयुक्त बैठक की जिसमें उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार चुना गया। राकांपा विधायक दल के नेता जयंत पाटिल ने (अगले) मुख्यमंत्री के रूप में ठाकरे का नाम प्रस्तावित किया और प्रदेश कांग्रेस प्रमुख बालासाहेब थोराट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। संयुक्त बैठक में शिवसेना सुप्रीमो के अलावा राकांपा प्रमुख शरद पवार, पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल, कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण, स्वाभिमानी शेतकारी संगठन के राजू शेट्टी, समाजवादी पार्टी के अबू आजमी और उक्त दलों के सभी विधायक मौजूद थे। महाराष्ट्र में सत्ता की बिसात पर भाजपा के चाणक्य अमित शाह को करारी शिकस्त देने वाले राकांपा नेता शरद पवार ने न सिर्फ भतीजे अजीत को मनाकर फडणवीस सरकार गिरा दी बल्कि, उनकी घर वापसी सुनिश्चित कर परिवार की एकजुटता भी बनाए रखी। देर शाम अजीत पवार गठबंधन की संयुक्त होटल में शामिल होने ट्राइडेंट पहुंचे जहां हाथ में अजीत दा-वी लव यू की तख्ती लिए राकांपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। देर रात अजीत अपने चाचा शरद पवार के घर गए जहां भविष्य को लेकर उनके बीच लंबी बातचीत हुई। फडणवीस ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा देने के बाद संवाददाताओं से कहा कि सुबह अजित पवार उनसे मिले और व्यक्तिगत कारणों से गठबंधन में आगे नहीं रह सकने की बात कहकर अपना इस्तीफा सौंपा था। राकांपा नेता ने सहयोग करने का फैसला किया था जिसके आधार पर उन लोगों ने सरकार सरकार बनाई। चूंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है इसलिए अब उनके पास बहुमत नहीं है। यह महसूस कर कि आवश्यक संख्या बल नहीं है और भाजपा खरीद-फरोख्त में शामिल नहीं होना चाहती इसलिए इस्तीफे का फैसला लिया गया। इसके बाद शिवसेना पर बरसते फडणवीस ने आरोप लगाया कि वह मुख्यमंत्री पद पाने को लालायित थी और इसके लिए अपने हिंदुत्व के एजेंडे को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के चरणों में रख दिया।इससे पहले, भाजपा को करारा झटका देते सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को निर्देश दिया कि वह बुधवार को शाम पांच बजे तक विधानसभा में अपना बहुमत साबित करें। इसमें विलंब होने से खरीद फरोख्त की आशंका है। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने 19 पृष्ठों के अपने आदेश में कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा हुए एक महीना हो गया लेकिन अभी तक अनिश्चितता बनी हुई है। इसे समाप्त करना, खरीद फरोख्त जैसी गैरकानूनी गतिविधयों पर अंकुश लगाना और स्थिर सरकार सुनिश्चित करते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना न्यायालय के लिए जरूरी हो गया है। सदन में तत्काल शक्ति परीक्षण ही इसका सबसे प्रभावशाली तरीका है। शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कहा कि वह अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त करें और यह तय करें कि सारे निर्वाचित सदस्य बुधवार को शाम पांच तक शपथ ग्रहण कर लें ताकि सदन में शक्ति परीक्षण हो सके। न्यायालय ने निर्देश दिया कि शक्ति परीक्षण के लिए गुप्त मतदान नहीं होगा और सदन की सारी प्रक्रिया का सीधा प्रसारण होगा। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि अस्थाई अध्यक्ष की नियुक्ति सिर्फ इसी कार्य के लिए तत्काल की जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ...

अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत को सदन में विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया था। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। यह फैसला उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश केएम जोसेफ, जो इस समय सुप्रीम कोर्ट में ही न्यायाधीश हैं, की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया था। इसी तरह, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक विधानसभा में भाजपा के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को शाम चार बजे तक विश्वास मत हासिल करने का आदेश देने संबंधी अपने 18 मई, 2018 के फैसले का भी हवाला दिया है। न्यायालय ने कहा था कि यह पता लगाने के लिए कि क्या येदियुरप्पा को बहुमत प्राप्त है या नहीं, सदन में शक्ति परीक्षण करना होगा। इन सभी फैसलों का मुख्य आधार 1994 में कर्नाटक के एस आर बोम्मई प्रकरण में शीर्ष अदालत की नौ सदस्यीय संविधान पीठ की व्यवस्था है] जिसमें न्यायालय ने कहा था कि जब भी यह सवाल उठे कि क्या मंत्रिपरिषद सदन का विश्वास खो चुकी है तो इसका एकमात्र तरीका सदन में ही शक्ति परीक्षण है। संविधान पीठ ने अपने फैसले में कहा था कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना असंवैधानिक है क्योंकि राज्यपाल ने ऐसा करने से पहले सदन में शक्ति परीक्षण के माध्यम से बहुमत साबित करने का अवसर प्रदान नहीं किया था। इसी तरह, न्यायालय ने 1999 के बहुचर्चित जगदम्बिका पाल बनाम भारत सरकार प्रकरण का भी हवाला दिया जिसमें शीर्ष अदालत ने उप्र विधानसभा में समेकित शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था ताकि यह पता लगाया जा सके कि राज्यपाल रोमेश भंडारी द्वारा मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त किए गए कल्याण सिंह के पास बहुमत है या फिर उनके उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त कांग्रेस के जगदम्बिका पाल के पास बहुमत है। इसी तरह की स्थिति झारखंड विधान सभा में 2005 में पैदा हुई और एक बार फिर शीर्ष अदालत ने मार्च 2005 में सदन में ही शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था ताकि यह पता लग सके कि अर्जुन मुण्डा या शिबू सोरेन में से किसके पास बहुमत है।

पर्दे के ...

में बने रहने के लिए मनाया जा रहा था। इस काम में पहले उनके भाई श्रीकृष्ण पवार आगे आए। इसके बाद सुप्रिया सुले के पति सदानंद भालचंद्र सुले ने अजीत से संपर्क किया। सदानंद ने मुंबई के एक पांच सितारा होटल में अजीत से मुलाकात की।मंगलवार को खुद शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत से बातचीत की। उनको पार्टी और परिवार का साथ देने के लिए मनाया गया। सूत्रों के मुताबिक अजीत को मनाने में शरद पवार की पत्नी प्रतिभा पवार का भी अहम योगदान रहा। प्रतिभा ने भी अजीत से परिवार के साथ बने रहने को कहा। परिवार के दबाव का ही असर था कि सोमवार को फडणवीस की बैठक में अजीत की कुर्सी खाली नजर आई। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने अजीत से कहा था कि वह माफ करने को तैयार हैं लेकिन पहले इस्तीफा देना होगा।अजीत को राजी करने में शरद पवार ने पारिवारिक दबाव के साथ ही सियासी सूझबूझ का भी परिचय दिया। पवार ने अजीत को विधायक दल के नेता पद से तो हटा दिया लेकिन उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता नहीं दिखाया। ऐसा करके शरद ने भतीजे के लिए दरवाजे खुले रखे। उन्होंने संकेत दिया कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है और अजीत अगर मन बदलते हैं तो उन्हें माफ किया जा सकता है। पवार ने साथ ही कोई कड़वाहट बढ़ाने वाली टिप्पणी भी नहीं की। बगावत करते हुए अजित के उप मुख्यमंत्री बनने के बावजूद शरद ने सिर्फ इतना कहा कि यह अजीत का निजी फैसला है और पार्टी से इसका कोई लेना-देना नहीं है। शरद पवार ने भतीजे की घर वापसी के लिए अपनी पार्टी के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी। पिछले दरवाजे से ये नेता लगातार अजीत से बातचीत करते रहे। पहले पवार ने संदेशवाहक के रूप में जयंत पाटिल को अजीत के पास भेजा। इसके बाद भी बात नहीं बनी तो उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल को मनाने के काम में लगाया। पटेल, भुजबल, जयंत पाटिल और वाल्से पाटिल समेत कई बड़े एनसीपी नेता अजीत से संपर्क करते रहे और आखिरकार मराठा क्षत्रप शरद पवार ने बाजी पलट दी।

चुनौतियों का ...

मजबूती के कारण ही हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरफ आगे बढ़ पा रहे हैं। भारतीयों के लिए गरिमा और भारत की एकता.. संविधान ने इन दो मंत्रों को साकार किया है। उन्होंने कहा कि संविधान अधिकारों के प्रति सजग एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाता है, ऐसे में हमें नागरिक के तौर पर अधिकारों एवं कर्तव्यों में संतुलन बनाना होगा। मोदी ने कहा, क्या हम अपने कर्तव्यों को लेकर उतने ही सजग हैं जितनी हमारा संविधान और हमारे देशवासी हमसे अपेक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारों और कर्तव्यों के बीच के इस रिश्ते और इस संतुलन को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने बखूबी समझा था। आज जब देश पूज्य बापू की 150वीं जयंती का पर्व मना रहा है तो उनकी बातें और भी प्रासांगिक हो जाती हैं। उन्होंने ने कहा, भारतीयों के लिए गरिमा और भारत की एकता.. संविधान ने इन दो मंत्रों को साकार किया है। मोदी ने कहा, हमारा संविधान वैश्विक लोकतंत्र की सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि है। यह न केवल अधिकारों के प्रति सजग रखता है बल्कि हमारे कर्तव्यों के प्रति जागरूक भी बनाता है। मोदी ने कहा कि हमारे संविधान की मजबूती के कारण ही हम एक भारत-श्रेष्ठ भारत की दिशा में आगे बढ़ पाए हैं। हमने तमाम सुधार संविधान की मर्यादा में रहकर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई आतंकवादी हमले के मृतकों को भी अपने संबोधन में श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संविधान निर्माता डॉ. बीआर अंबेडकर और प्रथम राष्ट्रपति बाबू राजेन्द्र प्रसाद को भी याद किया।

संयुक्त बैठक ...

एनसीपी, राजद, भाकपा, माकपा, तृणमूल कांग्रेसऔर शिवसेना सहित अन्य विपक्षी दलों के नेता शामिल थे। यह पहला मौका है जबकि कांग्रेस द्वारा आयोजित विरोध प्रदर्शन को शिवसेना का समर्थन मिला। प्रदर्शन की अगुवाई सोनिया गांधी ने की। इन नेताओं ने हाथों में बैनर ले रखा था जिस पर संकट में संविधान संकट लिखा हुआ था। उन्होंने संविधान की हत्या बंद करो के नारे लगाए। संविधान को अंगीकार करने के 70 वर्ष पूरा होने के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। महाराष्ट्र में सरकार गठन के मुद्दे पर भाजपा का विरोध करते हुए कांग्रेस, शिवसेना, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक, वाम दलों और राष्ट्रीय जनता दल (राजद) समेत विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्य संविधान दिवस पर आयोजित समारोह में शामिल नहीं हुए। हालांकि तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सदस्य नुसरत जहां की इस समारोह में उपस्थिति चर्चा की विषय रही। संयुक्त बैठक में भाजपा और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उसके सहयोगी दलों जनता दल यू (जदयू), अकाली दल, अपना दल, अन्नाद्रमुक और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के अलावा बहुजन समाज पार्टी (बसपा), तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा), तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस), बीजू जनता दल (बीजद), वाईएसआर कांग्रेस आदि दलों के दोनों सदनों के सदस्य उपस्थित थे। इस दौरान बसपा के राज्यसभा सदस्य सतीश चंद्र मिश्र और लोकसभा सदस्य दानिश अली तथा मलूक नागर, तेदेपा के लोकसभा सदस्य राममोहन नायडू, टीआरएस के राज्यसभा सदस्य के केशव राव, लोकसभा सदस्य नमा नागेश्वर राव, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सदस्य विजय साई रेड्डी और लोकसभा सदस्य मिथुन रेड्डी तथा रघु रामकृष्ण राजू आदि उपस्थित थे। प्रदर्शन में द्रमुक के टीआर बालू, शिवसेना के अरविंद सावंत, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय और एनसीपी के माजिद मेमन सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया।

अयोध्या मामले ...

करने का अधिकार सिर्फ बोर्ड अध्यक्ष फारूकी को ही होगा। हालांकि अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्ष का संरक्षण कर रहे आल इण्डिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने गत 17 नवम्बर को उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में जमीन न लेने का फैसला किया था। पर्सनल ला बोर्ड ने उम्मीद जताई थी कि सुन्नी वक्फ बोर्ड उसके फैसलों का सम्मान करेगा। हालांकि कम से कम पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के मसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने उससे अलग राह अख्तियार कर ली है। ज्ञातव्य है कि उच्चतम न्यायालय ने गत नौ नवम्बर को अयोध्या मामले में अपने निर्णय में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण कराने और मस्जिद बनाने के लिए सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में किसी प्रमुख स्थान पर पांच एकड़ जमीन उपलब्ध कराने का सरकार को आदेश दिया था।

मोदी सरकार के कार्यकाल में सुलझा लेंगे देश में छुट्टा गायों की समस्या: गिरिराज सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को घोषणा की कि मोदी सरकार के वर्तमान कार्यकाल में देश में छुट्टा घूमने वाली गायों की समस्या सुलझा ली जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका पशुपालन मंत्रालय इस समस्या से निजात पाने के लिए समाधान खोजने पर काम कर रहा है। योजना के विस्तार में न जाते हुए सिंह ने कहा, पहले प्रयोग होने दीजिए।

राष्ट्रीय दुग्ध दिवस पर यहाँ एक सम्मलेन को संबोधित करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि 2025 तक गोवंश में कृत्रिम गर्भाधान सौ प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। सिंह ने संवाददाताओं से कहा, आने वाले वर्षों में सड़क पर छुट्टा पशु घूमते दिखाई नहीं देंगे। मैं इस पर चिंतित हूँ। गाय के गोबर और गोमूत्र के प्रयोग से असहाय गाएं दूसरों को सहायता दे सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस मसले पर मंत्रालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के साथ मिलकर प्रयोग कर रहा है और पूरी कार्ययोजना उसके बाद बनाई जाएगी।

विरोध प्रदर्शन करने वाले किसानों ने की पेप्सिको के पंजीकृत आलू किस्म की बुवाई

अहमदाबाद। पेप्सिको कंपनी के खिलाफ आवाज उठाने वाले किसानों ने मंगलवार को कंपनी द्वारा पंजीकृत आलू की किस्म एफएल-2027 की बुवाई की। पेप्सिको का दावा है कि आलू की यह किस्म उसकी है। किसानों ने इस दावे के विरोध में इस आलू बीज की यहां बुवाई की। गुजरात के किसान दावा करते रहे हैं कि पौध किस्म का संरक्षण एवं किसान अधिकार प्राधिकार-2001 (पीपीवीएफआर) के तहत वे कंपनी की अनुमति के बिना भी बीज की बुवाई कर सकते हैं। पेप्सिको ने 2016 में एफएल-2027 किस्म को पंजीकृत कराया और इसे खेती के लिए गुजरात में पेश किया था। कंपनी इसका इस्तेमाल अपने लेज ब्रांड के चिप्स उत्पादन में करती है। इस साल 23 सितंबर को पेप्सिको ने पीपीवीएफआर कानून से संबंधित प्राधिकरण को लिखे एक पत्र में कहा था कि एफएल-2027 के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र धारक के रूप में उसके पास उसके अधिक

राज्यसभा ने अधिकारों की सुरक्षा विधेयक को मंजूरी दी

भाषा। नई दिल्ली

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करने के मकसद से लाए गए उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई। राज्यसभा में चर्चा के बाद ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी गई। लोकसभा गत अगस्त में संसद के पिछले सत्र के दौरान इस विधेयक को पारित कर चुकी है। हालांकि विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने कहा कि इस विधेयक में ट्रांसजेंडर की परिभाषा, ट्रांसजेंडर होने का जिलाधिकारी से प्रमाणपत्र हासिल करने की प्रक्रिया, सार्वजनिक स्थलों पर इन्हें अपमानित करने और इनके यौन शोषण संबंधी प्रावधान अपूर्ण हैं। शिवा ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाए जाने का जिक्र करते हुए सरकार से इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। उन्होंने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव भी दिया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, टीआरएस के के केशव राव, कांग्रेस के आनंद शर्मा और बसपा के सतीश चंद्र मिश्रा ने भी शिवा के सुझाव से सहमति व्यक्त करते हुए इसे प्रवर समिति के समक्ष भेजने की मांग की। हालांकि शिवा के इस प्रस्ताव को सदन में हुए मतविभाजन के आधार पर 55 के मुकाबले 74 मतों से

● ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करने के मकसद से लाए गए उभयलिंगी या ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंगलवार को संसद की मंजूरी मिल गई

खारिज कर दिया गया।उच्च सदन में विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने कहा कि विधेयक में संसद की स्थाई समिति की ज्यादातर सिफारिशों को शामिल किया गया है। उन्होंने इस विधेयक को विचारार्थ प्रवर समिति के समक्ष भेजने के विपक्ष के सदस्यों के सुझाव को यह कहते हुए स्वीकार करने में असमर्थता जताई कि प्रवर समिति के समक्ष उन्हीं विधेयकों को भेजा जाता है जो स्थाई समिति में नहीं भेजे जाते हैं। गहलोत ने कहा कि स्थाई समिति पहले ही इस विधेयक पर विचार कर चुकी है। इसलिए इसे प्रवर समिति के पास भेजने का कोई औचित्य नहीं है। हालांकि गहलोत ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और सामाजिक भेदभाव से उन्हें बचाने के लिए सदस्यों द्वारा पेश सुझावों को इसे कानून के रूप में

पारित करने के लिए बनाए जाने वाले नियमों में शामिल करने का प्रयास करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित होने से ट्रांसजेंडर समुदाय के हितों की रक्षा होगी।मंत्री ने कहा कि इस वर्ग के लिए शिक्षा के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार और उनके कल्याण को लेकर कई कदम उठाए जा रहे हैं।गहलोत ने कहा कि ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि विधेयक में, ट्रांसजेंडर लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है।उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी। गहलोत ने कहा कि इस विधेयक का मकसद हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध भेदभाव और दुर्व्यवहार खत्म करने के साथ ही इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा। इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर सामाजिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने कहा कि विधेयक के उद्देश्य एवं कारणों से ही स्पष्ट है कि ट्रांसजेंडर समुदाय, समाज में हाशिए पर है, क्योंकि वे पुरूष या स्त्री लिंग समूह में फिट नहीं होते हैं। ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक बहिष्कार से लेकर भेदभाव, शिक्षा सुविधाओं की कमी, बेरोजगारी, चिकित्सा सुविधाओं की कमी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ के मामले में 15 अप्रैल 2014 को दिए अपने आदेश में अन्य बातों के साथ केंद्र और राज्य सरकारों को उभयलिंगी समुदाय के कल्याण के लिए विभिन्न कदम उठाने का और संविधान के अधीन एवं संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन उनके अधिकारों की सुरक्षा के प्रयोजन में उन्हें तृतीय लिंग के रूप में मानने का निर्देश दिया। विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करने, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरूद्ध विभेद का निषेध करने तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति को उसी के रूप में मान्यता देने का अधिकार देने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पहचान प्रमाणपत्र जारी करने के साथ ही जोर दिया गया है कि नियोजन, भर्ती, प्रोन्नति और अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित विषयों में किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति के विरूद्ध विभेद नहीं किया जाएगा। प्रत्एक स्थापना में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने तथा ट्रांसजेंडर व्यक्ति परिषद स्थापित करने एवं उपबंधों का उल्लंघन करने पर दंड देने का भी प्रावधान किया गया है। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए द्रमुक के तिरुचि शिवा ने ट्रांसजेंडर समुदाय के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए 2004 में पेश अपने निजी विधेयक का हवाला देते हुए कहा कि उच्च सदन ने इस विधेयक को पारित किया था लेकिन लोकसभा में यह पारित नहीं हो सका। उन्होंने सरकार द्वारा पेश विधेयक में ट्रांसजेंडर की परिभाषा, ट्रांसजेंडर होने का जिलाधिकारी से प्रमाणपत्र हासिल करने की प्रक्रिया, सार्वजनिक स्थलों पर इन्हें अपमानित करने और इनके यौन शोषण संबंधी प्रावधानों को अपूर्ण बताया। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए शिक्षा और नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण देने का सुझाव देते हुए शिवा ने विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की मांग की। साथ ही उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाए जाने का जिक्र भी किया। वाईएसआर कांग्रेस के विजयसाई रेड्डी, अन्नाद्रमुक के ए नवनीत कृष्णन और भाजपा की रूपा गांगुली ने विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि इसके प्रावधान ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों को सुनिश्चित कर इनके साथ सदियों से हो रहे भेदभाव को खत्म करेंगे।

मुंबई में 1.32 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन बरामद अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार

एजेंसी। मुंबई

पुलिस ने यहां 42 वर्षीय एक अफ्रीकी नागरिक को गिरफ्तार किया है जिसके पास से 1.32 करोड़ रुपए मूल्य की कोकीन बरामद हुई है।महानगर पुलिस के मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि एक गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सोमवार शाम उपनगरीय अंधेरी में साकीनाका में एक होटल के बाहर जाल बिछाया और आरोपी को पकड़ा, जिसकी पहचान अल्ला कौआदियो बोरिस के रूप में हुई है। वह पश्चिम अफ्रीका के आइवरी कोस्ट का निवासी है। अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने उसके पास से 1.32 करोड़ रुपए मूल्य की उच्च गुणवत्ता वाली 220 ग्राम कोकीन बरामद की है। पुलिस उपायुक्त (मादक पदार्थ रोधी प्रकोष्ठ) शिवदीप ने बताया कि बोरिस यहां कोकीन का मुख्य डीलर था और ज्यादातर पश्चिमी उपनगरों में काम करता था। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।

मौजूदा सरकार के हाथों में संवैधानिक मूल्य सुरक्षित नहीं: मनमोहन

एजेंसी। नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय द्वारा देवेंद्र फडणवीस सरकार को महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार शाम तक बहुमत साबित करने का निर्देश देने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा सरकार में संवैधानिक मूल्य सुरक्षित नहीं हैं। सिंह ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, उच्चतम न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसका सम्मान होना चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने यह भी कहा, जिस तरह से केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र में कदम उठाया है उससे साफ है कि मौजूदा शासन के हाथों में संवैधानिक मूल्य सुरक्षित नहीं हैं। उच्चतम

● पूर्व पीएम ने कहा संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा, उच्चतम न्यायालय ने जो भी फैसला दिया है उसका सम्मान होना चाहिए

न्यायालय ने मंगलवार को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस बुधवार को विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करें। न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की तीन सदस्ईय खंडपीठ ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त से बचने के लिए यह जरूरी है।

झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 260 उम्मीदवार चुनाव मैदान में

भाषा। नई दिल्ली

झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में विभिन्न दलों के 260 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। दूसरे चरण में 20 सीटों पर सात दिसंबर को मतदान होगा। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में राज्य की राजधानी रांची सहित सात जिलों की 20 विधानसभा सीटों पर मतदान के बारे में मंगलवार को जारी तथ्यों के आधार पर बताया कि इस चरण में 260 उम्मीदवार चुनाव मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। इस चरण में शामिल सीटों के लगभग 48.25 लाख मतदाता मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दलों के अलावा झामुमो और राजद सहित चार राज्य स्तरीय दलों और अन्य दलों के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। इनमें 10492 सर्विस वोटर भी शामिल हैं। दूसरे

● आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के लिए सात दिसंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 6066 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं

चरण के चुनाव में 231 पुरुष और 29 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें भाजपा के 20, कांग्रेस के छह, झामुमो के 14 और झारखंड विकास मोर्चा के 20 के अलावा अन्य प्रमुख दलों में शामिल बसपा के 14, माकपा एवं भाकपा के तीन, राकांपा का एक, तृणमूल कांग्रेस के पांच और 73 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। आयोग द्वारा जारी ब्योरे के अनुसार दूसरे चरण वाली सीटों में सर्वाधिक 20 उम्मीदवार जमशेदपुर पूर्व और जमशेदपुर पश्चिम सीट पर चुनाव मैदान में हैं, जबकि सबसे कम सात उम्मीदवार सरायकेला सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि दूसरे चरण के लिए सात दिसंबर को 20 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के लिए 6066 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं। इस चरण के लिए मतदान करने वाले सभी मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा चुके हैं। उल्लेखनीय है कि झारखंड की 81 सदस्ईय विधानसभा के लिए 30 नवंबर से 20 दिसंबर तक पांच चरणों में मतदान होगा और 23 दिसंबर को मतगणना होगी। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल अगले साल पांच जनवरी तक है।

कश्मीर में पुलिस ने दी सलाह: मुठभेड़ क्षेत्रों में नहीं जाएं लोग

जम्मू। जम्मू-कश्मीर पुलिस ने एक परामर्श जारी कर घाटी के लोगों को सलाह दी है कि वे मुठभेड़ क्षेत्रों में नहीं जाएं क्योंकि वहां विस्फोटक सामग्रियों के कहीं भी रखे होने का खतरा है।यह परामर्श ऐसे समय में जारी किया गया है, जब सोमवार को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए थे।एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि नागरिकों से मुठभेड़ क्षेत्र में नहीं जाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि कहीं भी विस्फोटक सामग्री पड़ी होने की आशंका के कारण यह क्षेत्र खतरनाक साबित हो सकता है।उन्होंने बताया कि मारे गए आतंकवादियों के शव मुठभेड़ स्थल से बरामद कर लिए गए हैं। आतंकवादियों की पहचान करने और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उनका संबंध किस आतंकवादी संगठन से है।

महाराष्ट्र : न्यायालय के आदेश के बाद विधान भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई

भाषा। मुंबई

महाराष्ट्र विधानसभा में बुधवार को शक्ति परीक्षण कराने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में यहां विधान भवन और उसके आस-पास की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।पुलिस अधिकारी ने बताया कि विधानसभा परिसर के बाहर किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए बड़े पैमाने पर पुलिस का बंदोबस्त किया गया है।उन्होंने बताया, विधानसभा के सुरक्षा अधिकारी सदन के भीतर सुरक्षा व्यवस्था की देख-रेख कर रहे हैं। अधिकारी ने बताया कि मुंबई के पुलिस आयुक्त संजय बार्वे और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने सोमवार को विधान भवन के सुरक्षा इंतजाम की समीक्षा की।उन्होंने बताया, विधान भवन में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश के लिए पास केवल उन्हीं लोगों को जारी किया जाएगा जो परिसर में दाखिल होने के लिए अधिकृत होंगे। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि विधानसभा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए बहुमत साबित करने के वास्ते बुधवार को शक्ति परीक्षण कराया जाए। अदालत ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सदन के सभी सदस्य बुधवार को ही शपथ लें। अदालत ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया शाम पांच बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए।शीर्ष अदालत ने पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण कराने तथा शक्ति परीक्षण के दौरान गुप्त मतदान नहीं कराने का भी निर्देश दिया है।

मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा सौंपने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते देवेंद्र फडणवीस

जम्मू-कश्मीर में दरगाहों की सुरक्षा बढ़ाने का डीजीपी को निर्देश

भाषा। जम्मू

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने दक्षिण कश्मीर के त्राल में सूफी दरगाह को आग के हवाले करने की कोशिश की मंगलवार को निंदा की और पुलिस प्रमुख से केंद्र शासित प्रदेश की सभी दरगाहों की सुरक्षा कड़ी करने को कहा। पुराने त्राल उपनगर के काउंसरबल (क्रूसबल) मोहल्ला में आग लगने की एक घटना हुई थी। वहां शरारती तत्वों ने 25-26 नवंबर की दरम्यानी रात को एक स्थानीय मस्जिद से सटी दरगाह में आग लगा दी थी।एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि उपराज्यपाल ने इस कायराना कृत्य की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी हरकतें लोगों में गुस्सा पैदा करने और उनकी भावनाओं को आहत करने के लिए की जाती हैं लेकिन उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि इस घृणित कार्य को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के हवाले किया जाएगा। प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस ने दोषियों को पकड़ने के लिए खोज शुरू कर दी है। मुर्मू ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की है। साथ ही उपराज्यपाल ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को पूरे जम्मू-कश्मीर की दरगाहों की सुरक्षा कड़ी करने का निर्देश भी दिया।अधिकारी ने कहा कि मुर्मू ने कश्मीर के संभागीय आयुक्त को क्षतिग्रस्त सूफी दरगाह की मरम्मत कर उसे मूल रूप में वापस लाने के लिए तत्काल कदम उठाने को भी कहा है।

संविधान के प्रत्येक शब्द का पालन होना चाहिए: ममता

भाषा। कोलकाता

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि देशवासियों को भारतीय संविधान में निहित आदर्शों का पालन करना चाहिए। संविधान दिवस के मौके पर बनर्जी ने भारतीय संविधान तैयार करने में डॉ. बी आर आंबेडकर के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।बनर्जी ने ट्वीट किया, संविधान दिवस के अवसर पर, डॉ बी आर आंबेडकर और संविधानसभा को

● केंद्र ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी

श्रद्धांजलि, जिन्होंने हमारे महान लोकतंत्र को आकार दिया। हमें संविधान के प्रत्एक शब्द को अमल में लाना चाहिए: स्वायत्त, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, भाईचारा और समानता।

सरकार 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर मना रही है क्योंकि इसी दिन 1949 में संविधान को अंगीकृत किया गया था और बाद में 26 जनवरी, 1950 को यह लागू हुआ था जहां से भारत की एक गणतंत्र के रूप में शुरुआत हुई। केंद्र ने 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी।

दलाई लामा के पूर्व चिकित्सक डॉ. एशी धोंडेन का निधन

भाषा। धर्मशाला

प्रख्यात तिब्बती डाक्टर और दलाई लामा के पूर्व चिकित्सक एशी धोंडेन का मंगलवार को तड़के हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार के एक सदस्य ने कहा कि धोंडेन ने सोमवार को साँस लेने में दिक्कत होने की शिकायत की जिसके बाद देलक अस्पताल के डॉ सेतन दोरजी को बुलाया गया। परिवार के सदस्य ने कहा, श्वास की परेशानी के अलावा उन्हें कोई अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं थी। आज तड़के लगभग तीन बजे उन्होंने अंतिम साँस ली। धोंडेन का अंतिम संस्कार शुक्रवार की सुबह मैक्लोडगंज में किया जाएगा। धोंडेन का जन्म 15 मई 1927 को हुआ था और वह पारंपरिक तिब्बती औषधीय पद्धति से चिकित्सा करते थे। उन्होंने मैक्लोडगंज में 1969 में अपना निजी चिकित्सालय शुरू किया था।

सबरीमला जा रही महिला अधिकार कार्यकर्ताओं को पुलिस सुरक्षा देने से इनकार

भाषा। कोच्चि

श्रद्धालुओं, दक्षिणपंथी संगठनों के सदस्यों और भाजपा के विरोध प्रदर्शनों के बीच भगवान अयप्पा मंदिर में पूजा करने के लिए सबरीमला जा रही तृप्ति देसाई के नेतृत्व में महिला अधिकार कार्यकर्ताओं के एक दल को पुलिस सुरक्षा दिए जाने से मंगलवार को इनकार कर दिया गया।केरल सरकार ने देसाई की सबरीमला जाने की कोशिश को षड्यंत्र करार दिया।महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का दल यहां हवाईअड्डा पहुंचते ही सबरीमला जाने के लिए सुरक्षा की मांग को लेकर शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचा, लेकिन पुलिस ने उन्हें सुरक्षा देने से इनकार कर दिया और इसके लिए सबरीमला में सभी आयु वर्गों की महिलाओं को मंदिर में जाने की अनुमति देने के उच्चतम न्यायालय के 2018 के फैसले पर पुनर्विचार के न्यायालय के हालिया फैसले का हवाला दिया।अयप्पा श्रद्धालु, भाजपा और सबरीमला कर्म समिति के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता देसाई और महिला अधिकार कार्यकर्ताओं का विरोध करने के लिए आयुक्तालय के बाहर एकत्र हुए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि भगवान अयप्पा मंदिर के दर्शन करने जा रही महिला अधिकार कार्यकर्ता बिंदू अम्मिनी पर हिंदू संगठन के एक सदस्य ने कथित रूप से हमला कर दिया। सभी आयुवर्ग की महिलाओं को मंदिर जाने की न्यायालय द्वारा अनुमति दिए जाने के बाद मंदिर के दर्शन कर इतिहास रचने वाली अम्मिनी महिला अधिकार कार्यकर्ता तृप्ति देसाई की अगुवाई में मंदिर के दर्शन के लिए जा रहे महिला कार्यकर्ताओं के समूह में शामिल थीं।अम्मिनी पर पुलिस आयुक्तालय के बाहर हिंदू संगठन के एक सदस्य ने मिर्ची स्प्रे से हमला किया। पुलिस ने बताया कि हमलावर की पहचान श्रीनाथ पद्मनाभन के तौर पर हुई है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है।टीवी चैनलों पर वीडियो में अम्मिनी पर हमला होता दिखाया गया। अम्मिनी के वकील ने बताया कि उन्हें यहां अस्पताल में भर्ती कराया गया और उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। पुलिस अधिकारियों से यह आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन समाप्त कर दिया कि महिला कार्यकर्ताओं को मंदिर जाने के लिए सुरक्षा नहीं दी जाएगी।उल्लेखनीय है कि महिला अधिकार कार्यकर्ताओं अम्मिनी और कनकदुर्गा ने मंदिर में सभी आयुवर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के न्यायालय के फैसले के बाद पुलिस सुरक्षा के साथ अयप्पा मंदिर के दर्शन किए थे।माकपा नीत एलडीएफ सरकार ने इस मामले पर सावधानी से प्रतिक्रिया देते हुए अम्मिनी पर हमले की निंदा की लेकिन यह स्पष्ट किया कि 10 से 50 वर्ष आयु वर्ग की किसी भी महिला को मंदिर जाने के लिए पुलिस सुरक्षा तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक उच्चतम न्यायालय इस संबंध में आदेश नहीं देता। केरल देवस्वोम मंत्री के. सुरेंद्रन ने मंगलवार को महिला अधिकारों की कार्यकर्ता तृप्ति देसाई के सबरीमला आने के निर्णय के पीछे कोई साजिश होने का आरोप लगाया। सुरेंद्रन ने पत्रकारों से कहा, सरकार को तृप्ति देसाई के सबरीमला आने के निर्णय के पीछे किसी साजिश की आशंका है। वह पुणे से आई हैं और संघ तथा भाजपा में उनकी अच्छी पकड़ है। मंत्री ने आरोप लगाया कि यह कदम सबरीमला में शांतिपूर्ण तीर्थयात्रा में बाधा उत्पन्न करने के लिए उठाया गया है। त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड अध्यक्ष एन वसु ने कहा कि बोर्ड को मंदिर आने की उनकी योजना के बारे में सूचित नहीं किया गया था।अम्मिनी ने कहा कि न्यायालय ने सभी आयुवर्ग की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश की अनुमति देने के अपने आदेश पर रोक नहीं लगाई है। ऐसे में वे पुलिस सुरक्षा नहीं देने को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ शीर्ष अदालत में अवमानना याचिका दायर करेंगी।न्यायालय में सबरीमला मामले में दलीलें पेश करने वाले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि देसाई जैसे लोग सक्रियतावाद के नाम पर केवल अति कर सकते हैं जबकि सबरीमला मंदिर पर अंतिम निर्णय अब भी न्यायालय में लंबित है। उन्होंने ट्वीट किया, मंदिर से जुड़े लोगों की भावनाओं का कम से कम अंतिम फैसले में अधिकार दिए जाने तक सम्मान किया जाना चाहिए। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता रमेश चेन्नीतला ने आरोप लगाया कि इसके पीछे माकपा और भाजपा का षड्यंत्र है ताकि सबरीमला मंदिर की जारी तीर्थयात्रा को नुकसान पहुंचाया जा सके।

मुंबई हमले के 11 साल पूरे होने पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते मुंबई पुलिस के जवान

मुनाफावसूली के कारण सेंसेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आया, 68 अंक टूटा

भाषा। मुंबई

बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स मंगलवार को नई ऊंचाई पर पहुंच कर नीचे आ गया और सोमवार के मुकाबले 68 अंक की गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार के जानकार लोगों के अनुसार देश की आर्थिक वृद्धि को लेकर चिंता और महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच दूरसंचार, आईटी और वाहन कंपनियों के शेयरों में मुनाफावसूली से बाजार नीचे आया। कारोबार के दौरान 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स एक समय 41,120.28 अंक तक चला गया था। हालांकि अंत में यह पिछले दिन की तुलना में 67.93 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की गिरावट के साथ 40,821.30 अंक पर बंद हुआ।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी रिकार्ड 12,132.45 अंक पर पहुंचने के बाद नीचे आ गया और अंत में 36.05 अंक यानी 0.30 प्रतिशत की गिरावट के साथद 12,037.70 अंक पर बंद हुआ। सेंसेक्स के शेयरों में सर्वाधिक नुकसान में भारती एयरटेल रही। इसमें 4.34 प्रतिशत की गिरावट आई। लाइसेंस शुल्क के साथ स्पेक्ट्रक उपयोग शुल्क के संदर्भ में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) को लेकर उच्चतम न्यायालय के आदेश के मद्देनजर उम्मीद के मुकाबले अधिक प्रावधान से रेटिंग एजेंसी इक्रा द्वारा कंपनी की दीर्घकालीन रेटिंग घटाए जाने के बाद कंपनी का शेयर नीचे आया। निवेशकों की मुनाफावसूली से प्रमुख आईटी कंपनियों में टीसीएस और इन्फोसिस में भी क्रमश: 1.6 प्रतिशत और 1.05 प्रतिशत की गिरावट आई। एचसीएल टेक 1.29 प्रतिशत नीचे आया। वहीं वृद्धि को लेकर चिंता के कारण मारुति (1.52 प्रतिशत), महिंद्रा एंड महिंद्रा (1.67 प्रतिशत) और टाटा मोटर्स (1.36 प्रतिशत) नीचे आए। इसके अलावा पावर ग्रिड (2.26 प्रतिशत), सन फार्मा (1.75 प्रतिशत) में भी गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक 2.26 प्रतिशत, इंडस इंड बैंक 1.46 प्रतिशत, टाटा स्टील 1.17 प्रतिशत और आईटीसी 0.52 प्रतिशत मजबूत हुए। फिच समूह की कंपनी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में घटकर 4.7 प्रतिशत रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह 2012 के बाद लगातार छठी तिमाही होगी जब जीडीपी वृद्धि दर घटेगी। साथ ही एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान को 6.1 प्रतिशत से घटाकर 5.6 प्रतिशत कर दिया है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, चीन-अमेरिका के बीच व्यापार समझौता तथा घरेलू स्तर पर कंपनियों की कमाई बेहतर रहने की उम्मीद से बाजार रिकार्ड ऊंचाई तक गया। हालांकि वायदा एवं विकल्प खंड में अनुबंधों के निपटान से पहले बाजार में उतार-चढ़ावा आया। साथ ही महाराष्ट्र में राजनीतिक ड्राम और जीडीपी आंकड़े को लेकर सतर्क रुख के साथ निवेशकों ने कुछ मुनाफावसूली की। उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजी प्रवाह बढ़ने तथा सरकार द्वारा राजकोषीय अंतर को विनिवेश के जरिए पाटने से बाजार में तेजी बनी रह सकती है। एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई और जापान का तोक्यो बाजार बढ़त में रहे जबकि हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। यूरोप के प्रमुख बाजारों में शुरूआती कारोबार में मिला-जुला रुख रहा।

वृद्धि दर दूसरी तिमाही में 4.7 प्रतिशत, 2019-20 में 5.6 प्रतिशत रहने का अनुमान: इंडिया रेटिंग्स

भाषा। नई दिल्ली

देश की आर्थिक वृद्धि दर में चल रही गिरावट का सिलसिला अनुमानत: लगातार छठवीं तिमाही जुलाई-सितंबर,2019 में भी बना रहा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मंगलवार को अपनी आकलन रपट में चालू वित्त वर्ष के लिए चौथी बार जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) वृद्धि दर के अनुमान को और कम किया है और इस बार जुलाई-सितंबर की तिमाही में इसके 4.7 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सरकरी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में वृद्धि 5 प्रतिशत थी। यह 2013 के बाद किसी तिमाही में न्यूनतम आर्थिक वृद्धि दर थी। इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत रह सकती है। अगर ऐसा होता है तो यह 2012 के बाद लगातार छठी तिमाही होगी जब जीडीपी वृद्धि दर घटेगी। यह अनुमान तब आया है जब सरकार ने कंपनी कर में कटौती समेत राजकोषीय प्रोत्साहन के कई कदम उठाए हैं। रेटिंग एजेंसी ने एक बयान में कहा, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2019-20 के लिए जीडीपी वृद्धि दर अनुमान को संशोधित कर 5.6 प्रतिशत कर दिया है। यह लगतार चौथा मौका है जब रेटिंग एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष के लिए आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम किया है। एक महीने पहले ही एजेंसी ने इसके 6.1 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।

बयान के अनुसार आंकड़ों की समीक्षा जरूरी हो गई थी क्योंकि उच्च आवृत्ति वाला आंकड़ा बताता है कि वित्त वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही में 5 प्रतिशत से अधिक वृद्धि दर का पूर्व का अनुमान बरकरार नहीं रह पाएगा। नए अनुमान के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में यह 4.7 प्रतिशत रह सकती है। दूसरी तिमाही के आंकड़े शुक्रवार को जारी किए जाने की संभावना है। इंडिया रेटिंग्स ने कहा, अनुकूल तुलनात्मक प्रभाव के बावजूद वृद्धि की गति में गिरावट यह संकेत देता है कि 2019-20 की दूसरी छमाही में आर्थिक वृद्धि दर पूर्व के अनुमान से कमजोर रह सकती है और इसके 6.2 प्रतिशत रहने की संभावना है। बयान के अनुसार देश का आर्थिक परिदृश्य इस साल और कमजोर हुआ है। समस्या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों से शुरू हुई और धीरे-धीरे खुदरा कंपनियों, वाहन कंपनियों, मकान बिक्री और भारी उद्योग इससे प्रभावित हुई। इंडिया रेटिंग्स का वृद्धि अनुमान मूडीज इनवेस्टर्स सर्विस के संशोधित परिदृश्य 5.8 प्रतिशत से कम है। यह स्थिति तब है जब मोदी सरकार ने आर्थिक वृद्धि को थामने के लिए कदम उठाया है। सितंबर में सरकार ने कंपनी कर की दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया। साथ ही विनिर्माण कार्य में लगी नई कंपनियों के लिए कंपनी आयकर की दर घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया। इसके अलावा बैंकों में पूंजी डालना, 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का चार में विलय, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में व्यय के साथ स्टार्टअप के लिए कर लाभ भी दिए गए।

मारुति की आल्टो ने 38 लाख के बिक्री आंकड़े को पार किया

नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजूकी इंडिया (एमएसआई) ने मंगलवार को कहा कि उसकी शुरुआती स्तर की छोटी कार आल्टो ने 38 लाख का बिक्री आंकड़ा पार कर लिया है। कंपनी की यहां जारी विज्ञप्ति में इसकी जानकारी देते हुए कहा गया है कि आल्टो ने 10 लाख का बिक्री आंकड़ा 2008 में पार कर लिया था। इसके बाद 2012 में 20 लाख और 2016 में 30 लाख कारों के आंकड़े को पार कर लिया। कंपनी ने यह कार 2000 में बाजार में उतारी थी। एमएसआई ने कहा कि मारुति आल्टो लगातार 15 साल तक भारत की सबसे बेहतर बिक्री वाली कार बनी रही। एमएसआई के कार्यकारी निदेशक (विपणन और बिक्री) शशांक श्रीवास्तव ने कहा, बेहतर डिजाइन, आसान परिचालन, उच्च ईंधन क्षमता, उन्नत सुरक्षा उपायों और आसान रखरखाव के चलते आल्टो पहली बार कार खरीदने वाले ग्राहकों की पहली पसंद रही है। कंपनी ने इस साल बीएस6 मानकों पर खरी उतरने वाली आल्टो को पेश किया है जिसकी ईंधन दक्षता 22.05 किलोमीटर प्रति लीटर तक है। इसमें एयर बैग, ताला-तोड़ रोधक प्रणाली और उन्नत ब्रेक प्रणाली के साथ ही रिवर्स पार्किंग सेंसर, गति चेतावनी प्रणाली और चालक और सह-चालक दोनों के लिए सीट बेल्ट की याद दिलाने वाली प्रणाली सहित तमाम नए उपाय किए गए हैं। मारुति आल्टो का यह नया मॉडल विभिन्न श्रेणियों में सीएनजी ईंधन विकल्प के साथ 2.89 लाख से लेकर 4.09 लाख रुपए में उपलब्ध है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति पर वाणिज्य मंत्रालय ने मांगे अन्य विभागों से सुझाव

भाषा। नई दिल्ली

वाणिज्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के मसौदे पर इस्पात, जहाजरानी और अन्य सभी मंत्रालयों से सुझाव मांगे हैं। इस नीति का मकसद देशभर में सामानों का बाधारहित आवागमन सुनिश्चित करना है। नीति मसौदे में व्यापारियों के लिए लॉजिस्टिक की ऊंची लागत को भी कम करने पर विचार किया गया है।सरकार इस नीति को चलन में लाना चाहती है, क्योंकि देश की आर्थिक वृद्धि और निर्यात को तेज करने के लिए लॉजिस्टिक क्षेत्र की वृद्धि अहम है। एक अधिकारी ने कहा, हमने सभी मंत्रालयों और विभागों से नीति पर कुछ कार्वाई किए जाने योग्य सुझाव मांगे हैं। नीति का मसौदा वाणिज्य मंत्रालय के लॉजिस्टिक विभाग ने जारी किया है। देश में लॉजिस्टिक की लागत सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 13 से 14 प्रतिशत के बराबर है। अन्य देशों के मुकाबले यह बहुत अधिक है। इससे घरेलू उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में पिछड़ जाते हैं। निर्यातकों और घरेलू व्यापारियों की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार एक प्रमुख कारक है। परिवहन की लागत और समय घटाने एवं सामानों की आवाजाही तेज करने से इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। मंत्रालय ने फरवरी में 23 पन्नों के इस मसौदे को जारी किया था। इसमें देश में उपलब्ध सभी लॉजिस्टिक और व्यापार सुविधाओं के लिए एक सूत्रीय संदर्भ तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है, यह लोगों के बीच जानकारियां साझा करने का भी एकल मंच होगा। मसौदे में एक राष्ट्रीय लॉजिस्टिक ई-मार्केटप्लेस बनाने समेत कई और कदम प्रस्तावित हैं जो देश में लॉजिस्टिक व्यवस्था को बाधारहित बनाएंगे।

ओयो होटल्स का शुद्ध घाटा 2018-19 में बढ़कर 2,385 करोड़ रुपए रहा

भाषा। नई दिल्ली

होटल कंपनी ओयो होटल्स एंड होम्स को 31 मार्च 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में 2,384.69 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ। ओयो होटल्स द्वारा कंपनी पंजीयक के पास जमा मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार इससे पूर्व वित्त वर्ष में कंपनी को 360.43 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। कंपनी की परिचालन आय 2018-19 में बढ़कर 6,456.90 करोड़ रुपए रही जो इससे पूर्व वित्त वर्ष में ।,413.02 करोड़ रुपए थी।ओयो होटल्स के अनुसार वित्तीय परिणाम का अभी आडिट नहीं हुआ है और इसे मूल्यांकनकर्ताओं ने तैयार किया है न कि आडिटरों ने। कंपनी ने कहा मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में कंपनी का परिचालन खर्च बढ कर 6,131.65 करोड़ रुपए रहा जबकि मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में यह ।,246.84 करोड़ रुपए था। वर्ष के दौरान कर्मचारी लाभ पर व्यय भी उछल कर ।,538.85 करोड़ रुपए रहा। गुड़गाव की इस कंपनी का निवेश पश्चात मूल्य 5.32 अरब डालर आंका गया है।

अमेरिका और चीन शुरुआती व्यापार समझौते को लेकर आगे बढ़ेंगे सहमत

बीजिंग (एपी)। चीन और अमेरिका के शीर्ष व्यापार वार्ताकारों ने फोन पर बातचीत कर उनके बीच चल रहे व्यापार युद्ध को शांत करने की दिशा में पहल करते हुए शुरुआती समझौते पर काम करते रहने पर सहमति जताई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय ने एक संक्षिप्त प्रपत्र में कहा की चीन के उप- प्रधानमंत्री लिउ हे और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि राबर्ट लाइटहाइजर और वित्त मंत्री स्टीवन म्नुचिन से मंगलवार प्रात: बातचीत की। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने कहा, दोनों पक्षों ने एक दूसरे की मुख्य चिंताओं से जुड़े मुद्दों के समाधान पर गौर किया और इस बात पर सहमति जताई कि इनसे जुड़े मुद्दों का भी उपयुक्त तरीके से समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि पहले दौर की बातचीत में जो मुद्दे रह गए हैं उनको लेकर आपस में संपर्क में बनाए रखेंगे। चीन के वाणिज्य मंत्रालय की इस घोषणा की हालांकि, अमेरिका की तरफ से तुरंत कोई पुष्टि नहीं की गई। यह घोषणा सोमवार को अमेरिका के शेयर बाजार वॉल स्ट्रीट के नई रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आई है। चीन की सरकार द्वारा पेटेंट और कॉपीराइट सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए जाने की घोषणा के बाद अमेरिका के शेयर बाजारों में तेजी का रुख रहा।

आयकर विभाग के 21 और भ्रष्ट अधिकारियों को सेवानिवृत्त से पहले ही चलता किया गया

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों में संलिप्त अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाने के अभियान के पांचवें चरण में आयकर विभाग के 21 और अधिकारियों को समय से पहले सेवानिवृत्ति कर दिया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवा नियमावली के नियम 56 (जे) के तहत जनहित में बी समूह के 21आय कर अधिकारियों को भ्रष्टाचार और दूसरे आरोपों में अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया है। इस साल जून के बाद से यह पांचवां मौका है जब सरकार ने भ्रष्ट कर अधिकारियों को नौकरी से निकाला है। इसी के साथ 85 कर अधिकारियों को बाहर किया जा चुका है। इनमें 64 उच्चस्तर के अधिकारी थे। इन उच्चस्तरीय अधिकारियों में 12 सीबीडीटी के थे। इससे पहले सितंबर महीने में सरकार ने 15 कर अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृति दे दी थी। सूत्रों ने कहा कि इस बार जिन अधिकारियों को निकाला गया है उनमें सीबीडीटी के मुंबई कार्यालय के तीन और ठाणे के दो अधिकारी शामिल हैं। अन्य अधिकारी विशाखापत्तनम , हैदराबाद , राजमुंदरी , बिहार के हजारीबाग , महाराष्ट्र में नागपुर , गुजरात के राजकोट , राजस्थान के जोधपुर , माधोपुर तथा बीकानेर और मध्य प्रदेश के इंदौर एवं भोपाल में तैनात थे। सूत्रों ने कहा कि यह कार्वाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाल किले से दिए गए भाषण के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने लालकिले से अपने संबोधन में कहा था कि कर विभाग में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं और करदाताओं को बेवजह परेशान करते हैं। ए लोग ईमानदार करदाताओं को अपना निशाना बनाते हैं या फिर मामूली अथवा प्रक्रियात्मक उल्लंघन जैसे छोटे मोटे उल्लंघनों को लेकर जरूरत से ज्यादा कार्वाई करते हैं। जिन अधिकारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दी गई है। उनमें आधे से ज्यादा अधिकारियों को सीबीआई ने कथित तौर पर रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।

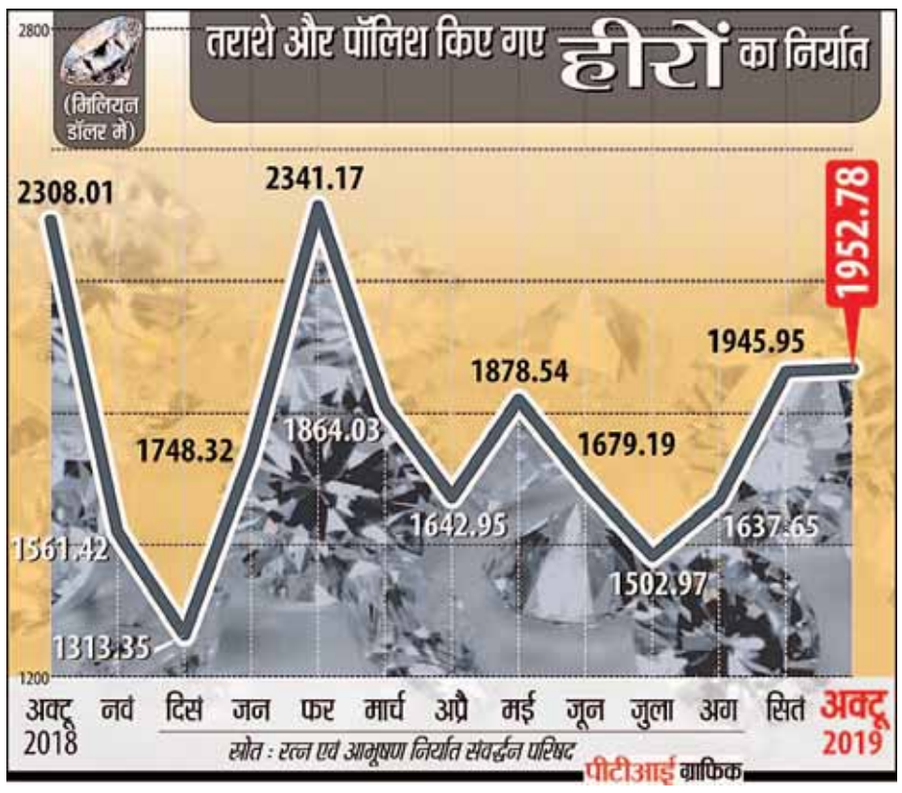

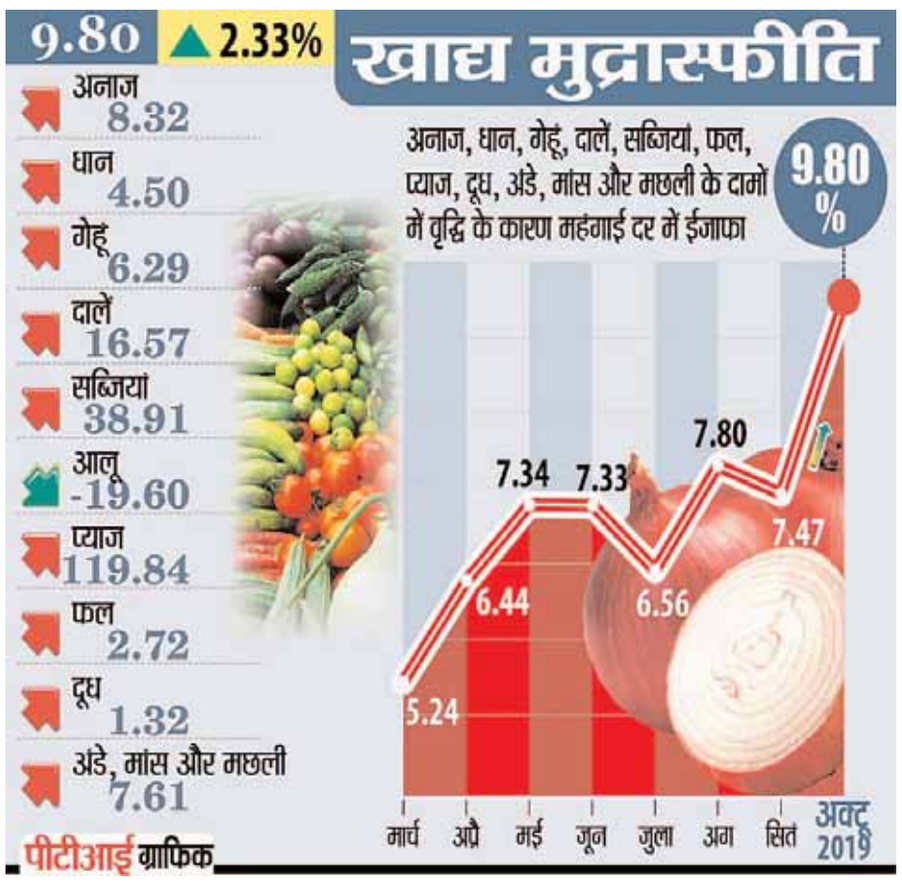

पेट्रोल पंप नीति: कंपनियों को लगाने होंगे कम से कम 100 पेट्रोल पंप, 5 प्रतिशत दूरदराज इलाकों में हों

भाषा। नई दिल्ली

सरकार ने ईंधन क्षेत्र में नई उदारीकृत खुदरा नीति जारी की है। इसके तहत ईंधन की खुदरा बिक्री के क्षेत्र में उतरने वाली कंपनियों को देशभर में कम से कम 100 पेट्रोल पंप लगाने होंगे और उनमें से पांच प्रतिशत पेट्रोल पंप दूरदराज इलाकों में होने चाहिए। सरकार ने पिछले महीने ही कंपनियों के लिए पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में ढील दी थी। सरकार ने गैर-पेट्रोलियम कंपनियों को इस क्षेत्र में उतरने की अनुमति दी है। नई नीति के मुताबिक देश में पेट्रोल पंप का लाइसेंस पाने के संशोधित प्रावधानों के तहत संबंधित कंपनी को न्यूनतम 100 पेट्रोल पंप लगाने होंगे, जिनमें कम से कम पांच प्रतिशत दूरस्थ इलाके में होने चाहिए।

एक राजपत्र अधिसूचना में पेट्रोल पंप लगाने के संशोधित प्रावधानों की जानकारी दी गई है। इसके तहत लाइसेंस पाने वाली कंपनी को पेट्रोल पंप का परिचालन शुरू होने के तीन साल के भीतर सीएनजी, बायो ईंधन, एलएनजी, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन आदि जैसे वैकल्पिक माध्यमों में से किसी एक के विपणन की सुविधा भी लगानी होगी। इससे पहले पेट्रोल पंप के लिए लाइसेंस पाने के लिए एक कंपनी को पेट्रोलियम क्षेत्र में दो हजार करोड़ रुपए निवेश करने की जरूरत होती थी। अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोलियम उत्पादों के खुदरा विपणन का लाइसेंस पाने के लिए आवेदन करते समय कंपनी का न्यूनतम नेट वर्थ 250 करोड़ रुपए होना चाहिए। सरकार ने पेट्रोल पंप पाने का आवेदन शुल्क 25 लाख रुपए तय किया है।अधिसूचना के अनुसार, लाइसेंस मिलने के पांच साल के भीतर कंपनी को देश भर में कम से कम 100 पेट्रोल पंप खोलने होंगे जिनमें कम से कम पांच प्रतिशत पेट्रोल पंप दूरस्थ इलाकों में अवस्थित होने चाहिए।

सरकार ने इससे पहले 2002 मे पेट्रोल पंप लाइसेंस आवंटन के प्रावधानों को संशोधित किया था। इस नीति की समीक्षा उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद की गई है। सरकार के पेट्रोलियम विपणन क्षेत्र में गैर- पेट्रोलियम कंपनियों को प्रवेश देने की नीति से वैश्विक स्तर की कंपनियों जैसे की फ्रांस की टोटल एसए, सउदी अरब की आरामको, ब्रिटेन की बीपी पीएलसी और ट्राफिगुरा की विपणन कंपनी पमा एनर्जी को भारतीय बाजार में आने का रास्ता मिलेगा। इससे पहले फ्रांस की टोटल कंपनी अदाणी समूह के साथ मिलकर नवंबर 2018 में देश में।,500 खुदरा पेट्रोल और डीजल पंप के लिए लाइसेंस का आवेदन कर चुकी है। बीपी ने भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर पेट्रोल पंप खोलने के वास्ते भागीदारी की है। हालांकि कंपनी ने अभी तक औपचारिक तौर पर आवेदन नहीं किया है। पुमा एनर्जी ने खुदरा लाइसेंस के लिए आवेदन किया है जबकि अरामको क्षेत्र में उतरने के लिए बातचीत कर रही है। फिलहाल देश में वर्तमान में चल रहे 66,408 पेट्रोल पंपों में से ज्यादातर पंप सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के ही हैं। इनके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, न्यारा एनर्जी (पूर्व में एस्सार आयल) और रायल डच शेल निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियां भी पेट्रोल पंप चला रही हैं लेकिन उनकी मौजूदगी बहुत कम हे। रिलायंस के।,400 पेट्रोल पंप हैं जबकि उसकी सहयोगी बीपी ने भी 3,500 पेट्रोल पंप के लिए आवेदन किया है लेकिन अभी शुरू नहीं किए हैं।

क्विक न्यूज

विस्तार, एसबीआई ने साझेदारी में पेश किया क्रेडिट कार्ड

नई दिल्ली। भारतीय स्टेट बैंक और एयरलाइन कंपनी विस्तार ने मंगलवार को एक प्रीमियम क्रेडिट कार्ड पेश किया। इसके जरिए उपयोगकर्ता मुफ्त टिकट रद्द करने , लाउंज सेवा और अतिरिक्त फ्लाइर प्वाइंट जैसी सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। विस्तार ने एक विज्ञप्ति में कहा, कई लाभ और सुविधाओं के साथ क्लब विस्तार एसबीआई कार्ड के दो संस्करण पेश किए गए है। इसमें मुफ्त टिकट रद्द करने , क्लब विस्तार सिल्वर । बेस श्रेणी की मेंबरशिप और यात्रा की श्रेणी को अपग्रेड करने के लिए वाउचर जैसी सुविधाएं शामिल है। इसके अलावा यात्रा बीमा सुरक्षा , विश्रामगृह के लिए वाउचर और आकर्षक रिवॉर्ड भी मिलेगा।

साइबर सुरक्षा पर उन्नत कार्यक्रम शुरू करेगा आईआईटी कानपुर

हैदराबाद। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान , कानपुर (आईआईटी - कानपुर) ने साइबर सुरक्षा एवं साइबर रक्षा पर एक उन्नत सर्टिफिकेट प्रोग्राम शुरू करने की मंगलवार को घोषणा की। इसके लिए उसने टैलेटसप्रिट के साथ साझेदारी की है। आईआईटी कानपुर के कार्यक्रम निदेशक और कंप्यूटर साइंस के प्राध्यापक मनिंद्र अग्रवाल ने यहां मीडिया से कहा , यह कार्यक्रम साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकियों में हो रहे नए - नए बदलावों को जानने के इच्छुक पेशेवरों के लिए तैयार किया गया है। इसका पहला ई - सत्र 2020 के शुरू में चालू होगा। उन्होंने कहा, मोबाइल , इंटरनेट ऑफ थिंग्स और क्लाउड कंप्यूटिंग के तेजी से बढ़ते उपयोग से सुरक्षा संबंधी जोखिम बढ़ रहे है और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के लिए इन खतरों से निपटने की जरूरत बढ़ती जा रही है।

तेजस नेटवर्क का भारत इलेक्ट्रानिक्स के साथ समझौता

नई दिल्ली। दूरसंचार गीयर निर्माता तेजस नेटवर्क्स ने मंगलवार को कहा कि उसने भारत इलेक्ट्रानिक्स के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत तेजस नेटवर्क्स कंपनी भारत और विदेशों में टर्नकी परियोजनाओं के लिए आप्टिकल ट्रांसमिशन और डेटा स्विचिंग उत्पादों की पेशकश करेगी। तेजस नेटवर्क्स ने बंबई शेयर बाजार को भेजी नियामकीय सूचना में कहा है कि दोनों कंपनियों के बीच आपसी सहमति को लेकर जिस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए है उसमें मेक-इन-इंडिया कार्यक्रम के तहत रक्षा दूरसंचार, रणनीतिक संचार, समार्ट सिटी, घरेलू सुरक्षा, मेट्रो और राज्य नेटवर्क परियोजनाओं के क्षेत्र में उभरते अवसरों का मिलकर लाभ उठाने की पहल होगी। इसके तहत संयुक्त रूप से घरेलू और निर्यात बाजारों में उभरते अवसरों का लाभ उठाते हुए तेजस आप्टिकल ट्रांसमिशन, पहुंच स्थापित करना और डेटा स्विचिंग उत्पादों के क्षेत्र में रणनीति सहयोग किया जाएगा। कंपनी ने कहा है कि उसे रक्षा समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी भारत इलेक्ट्रानिक्स से 60 करोड़ रुपए का खरीद आर्डर प्राप्त हुआ है। इस आर्डर के तहत कंपनी भारत इलेक्ट्रानिक्स की विभिन्न परियोजनाओं के लिए आप्टिकल और डेटा नेटवर्किंग उपकरणों की आपूर्ति करेगी और सेवाएं देगी। इसमें केरल फाइबर आप्टिक नेटवर्क, रक्षा संचार नेटवर्क्स और समार्ट सिटी परियोजनाएं शामिल है।

रिजर्व बैंक ने मुद्रा योजना के तहत बढ़ते फंसे कर्ज पर चिंता जताई

मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एम के जैन ने मंगलवार को छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई मुद्रा रिण योजना में कर्ज वसूली की बढ़ती समस्या को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बैंकों से कहा कि वह इस योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज पर करीबी नजर रखे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2015 में मुद्रा कर्ज योजना की शुरुआत की थी। यह योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को जरूरी वित्तपोषण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। जैन ने यहां भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के सूक्ष्म वित्त पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, मुद्रा योजना पर हमारी नजर में है ... इस योजना से जहां एक तरफ देश के कई लाभार्थियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में बड़ी मदद की हो वही इसमें कई कर्जदारों के बीच गैर- निष्पादित राशि के बढ़ते स्तर को लेकर कुछ चिंता भी है। उन्होंने बैंकों को सुझाव दिया है कि वह इस तरह के कर्ज देते समय दस्तावेजों की जांच-परख के स्तर पर कर्ज किस्त के भुगतान की क्षमता पर भी गौर करे और इस तरह के कर्ज का उनकी पूरी अवधि तक करीब से निगरानी करे।

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने सेना प्रमुख का कार्यकाल बढ़ाने संबंधी अधिसूचना पर रोक लगाई

● यह फैसला बाजवा की 29 नवंबर को होने जा रही सेवानिवृत्ति से ठीक पहले आया है

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अभूतपूर्व कदम उठाते हुए सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के कार्यकाल को तीन वर्ष के लिए और बढ़ाने संबंधी अधिसूचना पर मंगलवार को रोक लगा दी। यह फैसला बाजवा की 29 नवंबर को होने जा रही सेवानिवृत्ति से ठीक पहले आया है। प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा ने सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने के बाद सुनवाई बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी।

प्रधानमंत्री इमरान खान ने क्षेत्रीय अशांत वातावरण का हवाला देकर जनरल बाजवा के कार्यकाल को और तीन साल बढ़ाने के लिए 19 अगस्त को मंजूरी दी थी। भारत द्वारा पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के फैसले के बाद दोनों देशों के बीच संबंध खराब हो गए थे।

अधिसूचना के मुताबिक, जनरल कमर जावेद बाजवा को उनके मौजूदा कार्यकाल पूरा होने के बाद से और तीन साल के लिए सेना प्रमुख नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीश खोसा ने सुनवाई के दौरान कहा कि सेना प्रमुख के कार्यकाल को केवल पाकिस्तान के राष्ट्रपति बढ़ा सकते हैं। साथ ही उन्होंने इस पर भी गौर किया कि जब मामले पर कैबिनेट में चर्चा हुई थी तब 25 में से केवल 11 सदस्यों ने इस विस्तार को स्वीकृति दी थी।अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने प्रधान न्यायाधीश की टिप्पणी के विरोध में दलील दी कि कार्यकाल के विस्तार की घोषणा राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद की गई थी। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश ने कार्यकाल विस्तार संबंधी अधिसूचना पर रोक लगा दी और आगे की कार्यवाही के लिए अगली सुनवाई तय की। सेना प्रमुख के कार्यकाल को बढ़ाए जाने के खिलाफ रइज राही नामक व्यक्ति ने याचिका दायर की थी जिसने बाद में इसे वापस लेने के लिए आवेदन भी दिया था।

लेकिन न्यायाधीश खोसा ने याचिका वापस लेने का आवेदन रद्द कर दिया और याचिका को अनुच्छेद 184 के तहत जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार किया। यह पहली बार है जब शीर्ष अदालत ने शक्तिशाली सेना प्रमुख की सेवा बढ़ाने संबंधी सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाई है। सेना ने इस घटनाक्रम पर अब तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

इमरान खान पर अदालत की अवमानना का आरोप लगाने वाली याचिका खारिज

भाषा। इस्लामाबाद

पाकिस्तान की एक अदालत ने न्यायपालिका का मजाक उड़ाने को लेकर प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अदालत की अवमानना कार्यवाही की मांग करने वाली एक याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि खान ने अपने एक भाषण में न्यायपालिका का मजाक उड़ाया और अदालत की गंभीर अवमानना की। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला ने इससे पहले याचिका के सुनवाई योग्य होने या नहीं होने के विषय के बारे में शुरूआती दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जियो टीवी की खबर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश मिनाल्ला ने प्रधानमंत्री खान के खिलाफ दायर अवमानना कार्यवाही याचिका खारिज कर दी। यह याचिका अधिवक्ता सलीमुल्ला खान द्वारा सोमवार को दायर की गई थी। इसमें प्रधानमंत्री खान के एक हालिया भाषण के दौरान उनके द्वारा की गई टिप्पणी का जिक्र किया गया है। खान ने यह टिप्पणी रावलपिंडी से 140 किमी दूर हजारा मोटरवे के एक खंड के उद्घाटन समारोह में की थी। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने (न्यायालय की) गंभीर अवमानना की है। मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्ला ने इससे पहले मंगलवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए वादी से पूछा, प्रधानमंत्री के भाषण से आपको क्या समस्या है? याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री ने न्यायपालिका का मजाक उड़ाया है। न्यायमूर्ति मिनाल्ला ने कहा, अदालत आलोचना का स्वागत करती है। क्या आप निर्वाचित प्रधानमंत्री पर मुकदमा चाहते हैं? क्या आप इस तरह के कदम का नतीजा चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री को अयोग्य करार दिया जाए? खान ने अपने भाषण में पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश आसिफ सईद खोसा और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुलजार अहमद से न्यायपालिका में लोगों का भरोसा बहाल करने का अनुरोध किया था।

क्विक न्यूज

अर्जेंटीना के स्कूल में बधिर बच्चों के यौन उत्पीड़न के दोषी को 40 वर्ष की कारावास

मेंडोजा, अर्जेंटीना (एपी)। अर्जेंटीना के एक कैथोलिक स्कूल में बधिर बच्चों का यौन शोषण करने के दोषी दो पादरियों को 40 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई है। मेंडोजा में तीन न्यायाधीशों के पैनल ने सोमवार को 83 वर्षीय पादरी निकोला कोरादी को 42 वर्ष कारावास की और 59 वर्षीय पादरी होरासियो कोरबाचो को 45 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। दोनों पादरियों को वर्ष 2016 में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने माली अरमांडो गोम्ज को भी 18 साल जेल की सजा सुनाई है। पादरियों ने इन कुकृत्यों को वर्ष 2005 से 2016 के बीच अंजाम दिया था। सभी 10 पीड़ित यौन शोषण के दौरान नाबालिग थे।

महिला उत्पीड़न के खिलाफ दुनियाभर में हजारों लोगों ने रैली निकाली

पेरिस (एए।ऊपी)। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दिवस के मौके पर दुनियाभर में लाखों लोगों ने रैली निकाली। इस मौके पर फ्रांस ने घरेलू हिंसा से निपटने के लिए नए कदमों की घोषणा की। ग्वाटेमाला, रूस, सूडान और तुर्की जैसे देशों में भी सोमवार को प्रदर्शनकारी एकत्र हुए। तुर्की के इस्तांबुल में दंगा निरोधी पुलिस ने करीब दो हजार प्रदर्शनकारियों का रास्ता रोका और उसके बाद उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने प्लास्टिक की गोलियां भी चलाई। फ्रांस की सरकार ने घोषणा की कि वह चिकित्सकों के लिए हिंसा के लिहाज से संवेदनशील महिलाओं के बारे में जानकारी साझा करने को सुगम बनाएगी और मनोवैज्ञानिक धोखाधड़ी की अवधारणा को कानून में शामिल करेगी। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक वर्ष 2017 में दुनियाभर में अनुमानित 87,000 महिलाओं और लड़कियों की हत्या हुई।

हथियारबंद लोग विमान को अगवा कर उसमें लदा सामान चोरी करके भाग निकले

काकोपो, पापुआ न्यू गिनी (एएफपी)। पापुआ न्यू गिनी में एक चार्टर एयरलाइन ने मंगलवार को कहा कि कुछ सशस्त्र लोगों ने उनके एक विमान का अपहरण कर पायलट पर उसे एक सुनसान हवाईपट्टी पर ले जाने का दबाव बनाया और वहां जा कर विमान में लदा सामान चुरा कर भाग निकले। ट्रॉपिकेयर ने एएफपी को बताया कि विमान जब न्यू ब्रिटेन के द्वीप गास्माता में ईंधन भरवा रहा था तब आठ सशस्त्र लोग वहां आए और उन्होंने पायलट को विमान उड़ाने के लिए बाध्य किया। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि विमान में कोई यात्री सवार नहीं था। मैथ्यू ब्रुटनॉल ने बताया, हवाई पट्टी पर पहुंचने के बाद सशस्त्र लोगों ने सामान और विमान में लदा माल चुरा लिया और फिर वहां से भाग निकले।

देशद्रोह मामले में लाहौर उच्च न्यायालय ने मुशर्रफ की याचिका विचारार्थ स्वीकार की

भाषा। लाहौर

● लाहौर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से 28 नवम्बर तक जवाब भी मांगा है

लाहौर उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली। मुशर्रफ ने अपनी याचिका में विशेष अदालत द्वारा देशद्रोह मामले में सुरक्षित रखे गए फैसले को बृहस्पतिवार को सुनाने पर रोक लगाने की मांग की है। द डॉन न्यूज ने खबर दी है कि लाहौर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सैयद मजहर अली अकबर नकवी ने इसकी आपत्तियों को हटा दिया और दुबई में रह रहे मुशर्रफ की याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर लिया। लाहौर उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय से 28 नवम्बर तक जवाब भी मांगा है।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में गृह मंत्रालय की तरफ से एक अलग याचिका दायर की गई है जिसमें मुशर्रफ के खिलाफ विशेष न्यायाधिकरण द्वारा देशद्रोह मामले में फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति नकवी ने मुशर्फ के वकील ख्वाजा अहमद को निर्देश दिया था कि याचिका सुनवाई योग्य है अथवा नहीं इस पर अपनी दलीलें दें। जियो न्यूज ने खबर दी कि लाहौर उच्च न्यायालय ने पूछा कि क्या याचिका उसके सुनवाई के अधिकार क्षेत्र में आता है अथवा नहीं क्योंकि 76 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति इस्लामाबाद के निवासी हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि मामला उच्चतम न्यायालय के पास है और परिस्थितियों के तहत याचिकाकर्ता को उच्चतम न्यायालय से संपर्क करना चाहिए।

इंडोनेशिया के जकार्ता पुलिस मुख्यालय में मंगलवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान चीनी धोखाधड़ी के संदिग्धों को ले जाते हुए पुलिस अधिकारी

वैश्विक तापमान में बढ़ने से जलवायु पर ज्यादा विनाशकारी असर होगा

भाषा। जेनेवा

● संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में मंगलवार को यह चेतावनी दी गई

पेरिस जलवायु समझौते के तहत यदि बिना शर्त वाली सभी मौजूदा प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया जाता है तो भी इस सदी के अंत तक वैश्विक तापमान में 3.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र की एक नई रिपोर्ट में मंगलवार को यह चेतावनी दी गई। इसमें यह भी कहा गया है कि इस तरह की स्थिति से जलवायु पर ज्यादा विनाशकारी असर देखने को मिलेगा।

संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यक्रम के वार्षिक उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट के मुताबिक सभी देशों को अपने प्रतिबद्ध योगदान (एनडीसी) महत्वाकांक्षाओं को तीन गुना बढ़ाना चाहिए ताकि दो डिग्री सेल्सियस से नीचे के लक्ष्य को हासिल किया जा सके। साथ ही, 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पांच गुना से अधिक योगदान (एनडीसी) करना चाहिए। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई कि पेरिस समझौते के अंतर्गत अगर सभी बिना शर्त वाली प्रतिबद्धताओं को पूरा कर लिया जाता है तो इस सदी के अंत तक तापमान में 3.2 डिग्री बढ़ोतरी होने का अनुमान है।इसमें कहा गया है, अगर सशर्त एनडीसी को भी प्रभावी तरीके से लागू किया जाए तो तापमान में करीब 0.2 डिग्री सेल्सियस की कमी की संभावना है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस में 7.6 फीसदी की कमी की जानी चाहिए, ताकि पेरिस समझौते के मुताबिक वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि रखने के लक्ष्य को पूरा किया जा सके। रिपोर्ट में कहा गया है, जब तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 2020 और 2030 के बीच प्रति वर्ष 7.6 फीसदी की कमी नहीं होती है तब तक पेरिस समझौते के तहत डेढ़ डिग्री सेल्सियस तापमान के लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकेगा।

अल्बानिया में भूकंप: 13 लोगों की मौत, 300 से अधिक घायल

एपी। तिराना (अल्बानिया)

पश्चिमी अल्बानिया के डुरेस में मंगलवार को 6.4 तीव्रता के भूकंप के बाद क्षतिग्रस्त इमारत के बगल में खड़े लोग

अल्बानिया में मंगलवार तड़के आए भीषण भूकंप के कारण कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक लोग घायल हो गए।

बचावकर्मी भूकंप के कारण ढही इमारतों के बीच फंसे लोगों को बचाने के प्रयास कर रहे हैं। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के अनुसार 6.4 तीव्रता के साथ आए भूकंप का केन्द्र राजधानी तिराना से 30 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसके बाद 5.1 और 5.4 की तीव्रता वाले कई झटके महसूस किए गए। यूनान और कोसोवो ने अल्बानिया में बचावकर्ताओं की मदद का वादा किया है। अल्बानिया के प्रधानमंत्री एदी रमा ने मदद की पेशकश करने वाले देशों को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि यूरोपीय संघ, पड़ोसी देशों और अमेरिका ने मदद की पेशकश की है।

भूकंप के कारण कम से कम तीन इमारतें गिर गईं। बचावकर्मी फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि मलबे में कितने लोग दबे हो सकते हैं। अल्बानिया के राष्ट्रपति इलिर मेटा ने कहा कि थुमाने में स्थिति काफी गंभीर है। लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि तिराना से 33 किलोमीटर दूर दुंस में ढही इमारत से तीन शव बाहर निकाले गए। थुमाने शहर में भी एक इमारत ढहने के बाद मलबे से दो लोगों का शव निकाला गया था। वहीं, एक अन्य घटना में कुर्बिन में भूकंप आने पर घबरा कर अपने घर से बाहर छलांग लगा देने के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपात सेवा के अधिकारियों ने बताया कि दुंस में भूकंप के झटके की वजह से एक इमारत ढहने के कारण एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ओर्गेता मानास्तीर्लियू ने बताया कि दुंस, तिराना और थुमाने में करीब 300 घायलों का इलाज चल रहा है। रमा ने बताया कि सभी सरकारी एजेंसियां चौकन्नी हैं और दुंस और थुमाने में लोगों की जान बचाने के लिए काम कर रही हैं।

इजराइली राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने संविधान दिवस पर भारत को बधाई दी

यरूशलम (भाषा)। इजराइली राष्ट्रपति रूवेन रिवलिन और प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने संविधान को अंगीकृत किए जाने की 70वीं वर्षगांठ पर भारत को मंगलवार को बधाई दी और इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया, जो देश की अनोखी संस्कृति एवं इतिहास को दर्शाता है। दोनों शीर्ष नेताओं ने कहा कि वे भारत के विकास और अर्थव्यवस्था से प्रभावित हैं। नेतन्याहू ने मंगलवार सुबह ट्वीट किया, मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के लोगों को भारत के संविधान दिवस की 70वीं वर्षगांठ पर बधाई।

शीर्ष अधिकारी के भागने के बाद श्रीलंका में हवाईअड्डे अलर्ट पर

एएफपी। कोलंबो

श्रीलंका सरकार ने एक शीर्ष खुफिया अधिकारी के देश से भागने के बाद पुलिस जासूसों को बिना अनुमति विदेश जाने से रोकने के लिए देश के हवाई अड्डों को अलर्ट कर दिया है।

खबर है कि सीआईडी निरीक्षक निशांत सिल्वा जान से मारने की कथित धमकियों के बाद देश छोड़कर भाग गए। यह घटनाक्रम राष्ट्रपति चुनाव में गोटबाया राजपक्षे की जीत के बाद हुआ। संबंधित इंस्पेक्टर ने गोटबाया के खिलाफ भी जांच की थी। पुलिस प्रवक्ता रुवन गुणशेखर ने बताया कि सीआईडी के 704 अधिकारियों के नाम आव्रजन अधिकारियों को भेजे गए हैं। उन्होंने कहा, कदम यह सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी अधिकारी विदेश यात्रा के लिए अनुमति प्राप्त करने की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना देश न छोड़ पाए।

निर्देश तब आया जब सिल्वा रविवार को स्विट्जरलैंड में कथित तौर पर शरण मांगने के लिए देश छोड़कर भाग गए। पुलिस ने उनके भागने के मामले में जांच शुरू कर दी है। सिल्वा ने हत्या और भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों में जांच की थी जिनमें पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजपक्षे के प्रशासन के लोग शामिल बताए जाते हैं। महिन्दा 2015 तक एक दशक तक देश के राष्ट्रपति रहे। वह नवनिर्वाचित राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के भाई हैं। गोटबाया ने राष्ट्रपति बनने के बाद अपने भाई महिन्दा को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। पछली बार महिन्दा जब कुछ समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने सिल्वा को सीआईडी से हटा दिया था, लेकिन महिन्दा के हटने के बाद उन्हें फिर बहाल कर दिया गया था।

मुंबई हमले के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए : अमेरिका

भाषा। वाशिंगटन

मुंबई में करीब एक दशक पहले हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों को याद करते हुए अमेरिका ने कहा है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए।

यह भारत के इतिहास में, सर्वाधिक भयावह आतंकवादी हमलों में से एक था। इस हमले में 166 लोगों की मौत हो गई थी और 300 से अधिक लोग घायल हो गए थे। 26 नवंबर 2008 को पाकिस्तान से, समुद्री रास्ते से आए दस आतंकवादियों ने मुंबई में इस आतंकवादी हमले को अंजाम दिया था। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोर्गन ओर्टागस ने हमले की 11 वीं बरसी पर ट्वीट किया, 11 साल पहले आतंकवाद की कायर कार्वाई में छह अमेरिकी नागरिकों समेत 166 लोगों की जान चली गई थी। ओर्टागस ने कहा, आज हम मुंबई आतंकवादी हमले के पीड़ितों को याद करते हैं। हम, इस जघन्य अपराध के जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के उनके परिजन की मांग के साथ हैं।

भारतीय अमेरिकी तथा विभिन्न संगठन वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास के समक्ष, मुंबई आतंकवादी हमले में देश (पाकिस्तान) की भूमिका पर विरोध जताते हुए एक रैली निकालेंगे। विरोध रैली के आयोजकों ने कहा कि मुंबई आतंकवादी हमले के दोषी पाकिस्तान में आजादी से घूम रहे हैं। पाकिस्तानी मूल के कनाडाई तारिक फतेह ने ट्वीट किया, साल 2008 में आज ही के दिन लश्कर ए तैयबा के 10 पाकिस्तानी जिहादी आतंकवादी समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचे और 166 से अधिक निर्दोष लोगों को मार डाला। इनमें से कुछ ताज होटल में और कुछ यहूदी सेंटर में आतंकियों के हमले में मारे गए।

माली में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 13 फ्रांसीसी सैनिकों की मौत

पेरिस (एपी)। माली में इस्लामी चरमपंथियों के खिलाफ अभियान चलाने के क्रम में दो हेलीकॉप्टरों के बीच हुई टक्कर में 13 फ्रांसीसी सैनिकों की मौत हो गई। फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। मैक्रों ने सोमवार को हुई इस दुर्घटना पर गहरा शोक प्रकट किया जो संघर्ष अभियान के दौरान हुई थी। एक लिखित बयान में, उन्होंने फ्रांस की सेना के लिए अपना समर्थन जाहिर किया और साहेल क्षेत्र में लगातार बने हुए इस्लामी भय का मुकाबला कर रहे फ्रांस के सैनिकों के साहस पर जोर दिया। बयान में दुर्घटना के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी गई। फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली ने कहा कि दुर्घटना किन परिस्थितियों में हुई, यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की गई है। पश्चिम और मध्य एशिया में चलाए जा रहे अभियान में 4,500 कर्मी शामिल हैं और यह विदेश में चलाया जा रहा फ्रांस का सबसे बड़ा सैन्य मिशन है। माली में चरमपंथी हमलों में अचानक हुई वृद्धि ने पिछले दो माह में 100 से अधिक स्थानीय सैनिकों की जान ले ली। इस्लामिक स्टेट समूह अक्सर इन हमलों की जिम्मेदारी लेता रहा है। अमेरिका ने कहा था कि पश्चिम अफ्रीका का साहेल क्षेत्र आईएस और अन्य चरमपंथी समूहों के खिलाफ जंग में एक उभरता हुआ मोर्चा है।आईएस सरगना अबु बकर अल बगदादी ने इस साल अपनी मौत से पहले माली और पड़ोसी बुर्किना फासो में वफादारी निभाने के लिए इन चरमपंथियों को बधाई दी थी।

चीन की सरकारी मीडिया ने हांगकांग चुनाव को विकृत बताया

एएफपी। बीजिंग

चीन की सरकारी मीडिया ने हांगकांग में चुनाव परिणामों को कमतर बताने और उस पर अविश्वास प्रकट करने के संबंध में मंगलवार को कई खबरें दीं। इन चुनावों में लोकतंत्र समर्थक प्रत्याशियों को जबर्दस्त जीत हासिल हुई और ए नतीजे बीजिंग समर्थक शासन के लिए काफी चुभने वाले साबित हुए हैं।

अर्ध स्वायत्त शहर में हुए निकाय चुनावों में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनकारियों को लोगों का जबर्दस्त समर्थन मिलता दिखाई दिया जहां चीन के नियंत्रण को कम करने की मांग वाले प्रत्याशियों को 452 सीटों का शानदार बहुमत मिला। ए विरोध प्रदर्शन कई माह तक चले और इनमें हिंसा हुई। चीनी भाषा की सरकारी मीडिया ने मंगलवार को दी खबरों में चुनाव में जीतने वालों का कोई जिक्र नहीं किया। इनमें सरकारी प्रसारणकर्ता सीसीटीवी और कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र पीपल्स डेली भी शामिल था। पीपल्स डेली ने कहा, सामाजिक अशांति ने चुनावी प्रक्रिया को गंभीर रूप से बाधित किया।

चाइना डेली के अंग्रेजी भाषा के संस्करण में छपे एक संपादकीय में कहा गया कि चुनाव को खराब चालों और डराने-धमकाने के जरिए बिगाड़ा गया। संपादकीय में कहा गया, हिंसक धमकियों वाली युक्तियों की मंशा शासन समर्थित प्रत्याशियों के प्रदर्शन एवं दृश्यता को घटाना था। इसमें कहा गया, बाहरी ताकतों का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र में महीनों से चल रहे सरकार विरोधी अभियान को और भड़काना भी शासन समर्थक प्रत्याशियों की चुनावी संभावनाओं को काफी हद तक नुकसान पहुंचा गया। आधिकारिक संवाद समिति शिन्हुआ पर अंग्रेजी भाषा की एक टिप्पणी में कहा गया कि चुनाव दंगाईयों की भेंट चढ़ गया। समिति ने मंगलवार को कहा, कुछ देशभक्त प्रत्याशियों के अभियान को गंभीर रूप से बाधित किया गया और उनके कार्यालयों में तोड़-फोड़ एवं आगजनी की गई। एक प्रत्याशी हमले में घायल हुआ।

चीन ने हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिकी राजदूत को तलब किया

एपी। हांगकांग

चीन ने अमेरिकी राजदूत टेरी ब्रेनस्टेड को एक बार फिर तलब किया है ताकि वह ट्रंप प्रशासन से हांगकांग में लोकतंत्र पक्षधरों का समर्थन करने संबंधी कांग्रेस के दोनों चैंबरों द्वारा पारित विधेयक को निरस्त करने की मांग कर सके।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि उपमंत्री झेंग जेगुआंग ने हांगकांग मानवाधिकार एवं लोकतंत्र विधेयक के प्रति चीन की कड़ी आपत्ति को सोमवार को जताई और चेताया कि अमेरिका को सभी तरह के परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। चीन ने इस विधेयक पर विरोध जाहिर करने के लिए हाल के कुछ हफ्तों में दूसरी बार ब्रेनस्टेड को तलब किया है। यह विधेयक लभगभ सर्वसम्मति से पारित हुआ और अब इस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर होना बाकी है। ट्रंप शुक्रवार को इस विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे क्योंकि वह चीन के साथ व्यापार सौदे पर काम करने के प्रयास में हैं। पिछले हफ्ते पारित होने के बाद से इस विधेयक पर वीटो करने के लिए उनके पास 10 दिन का समय है। अगर वह ऐसा नहीं करते तो यह अपने आप कानून बन जाएगा, जबकि कांग्रेस दोनों सदन में दो-तिहाई बहुमत के साथ इस वीटो को रद्द कर सकती है। यह विधेयक मानवाधिकार उल्लंघन में संलिप्त चीन एवं हांगकांग के अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करता है।

मौलिक दस्तावेज है भारत का संविधान: यूएनजीए अध्यक्ष

संयुक्त राष्ट्र (भाषा)। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने मंगलवार को भारत को 70वें संविधान दिवस की बधाई देते हुए कहा कि भारतीय संविधान एक मौलिक दस्तावेज है जो इसके, उपनिवेशवाद के अंधेरे से स्वतंत्रता के उजाले में उदय का प्रतीक है। महासभा के अध्यक्ष तिजानी मुहम्मद-बंदे ने कहा, हम इस साल महात्मा गांधी की 150 जंयती मना रहे हैं। गांधी को मनुष्यों के लिए सम्मान एवं अहिंसा के विचार में अतुलनीय योगदान देने के लिए जाना जाता है। बंदे ने भारत के संविधान दिवस के अवसर पर भारतीयों को एक वीडियो संदेश के जरिए बधाई देते हुए कहा, हम भारत का 70वां संविधान दिवस भी मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष ने कई अन्य को प्रेरित किया।

कोहली और अग्रवाल पहली बार शीर्ष दस में

● आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग

भाषा। दुबई

भारतीय कप्तान विराट कोहली बांग्लादेश के खिलाफ दिन रात के टेस्ट में शतक जमाकर आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में स्टीव स्मिथ के करीब पहुंच गए जबकि सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल पहली बार शीर्ष दस में आ गए।

कोहली के 928 रेटिंग अंक हैं जिन्होंने कोलकाता में बांग्लादेश के खिलाफ 136 रन बनाए। उनके और स्टीव स्मिथ के बीच अब तीन अंक का ही अंतर रह गया है। इंदौर में बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट में दोहरा शतक जमाने वाले अग्रवाल एक पायदान चढकर दसवें स्थान पर पहुंच गए। शीर्ष दस में वह चौथे भारतीय हैं। चेतेश्वर पुजारा (791) चौथे और अजिंक्य रहाणे (759) पांचवें स्थान पर हैं। इंग्लैंड के हरफनमौला बेन स्टोक्स भी तीन पायदान चढकर शीर्ष दस में पहुंच गए। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम चार पायदान चढकर 26वें स्थान पर हैं जिन्होंने कोलकाता टेस्ट में 74 रन बनाए। भारतीय तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और उमेश यादव ने कैरियर के सर्वोच्च अंक हासिल किए। ईशांत 716 अंक लेकर 17वें स्थान पर हैं जबकि उमेश 672 अंक के साथ 21वें स्थान पर हैं। स्पिनर आर अश्विन 772 अंक लेकर नौवें स्थान पर हैं। वहीं फिटनेस समस्याओं से जूझ रहे जसप्रीत बुमराह एक पायदान खिसककर पांचवें स्थान पर हैं। रविंद्र जडेजा हरफनमौलाओं की सूची में दूसरे स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज के जैसन होल्डर शीर्ष पर हैं।

न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट की सुरक्षा बढ़ाई

● आर्चर पर नस्लवादी टिप्पणी के बाद लिया फैसला

भाषा। वेलिंगटन

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर पर माउंट मोउनगानुइ में दर्शकों द्वारा नस्लीय टिप्पणी किए जाने के बाद न्यूजीलैंड क्रिकेट ने दूसरे टेस्ट की सुरक्षा बढ़ा दी है। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने आर्चर को इंगित ताने को भयावह बताया। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा कि दोषियों को पुलिस के हवाले किया जाएगा और सीसीटीवी फुटेज में पकड़े जाने पर भविष्य में किसी भी मैदान पर उसके प्रवेश पर रोक लगा दी जाएगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी डेविड व्हाइट ने कहा , हम बहुत निराश हैं।यह अस्वीकार्य है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बारबाडोस में जन्मे आर्चर ने सोमवार को मैच खत्म होन के बाद ट्वीट किया , अपनी टीम को बचाने के लिए संघर्ष करते समय नस्लीय टिप्पणी सुनकर काफी परेशान हुआ। न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट एक पारी और 65 रन से जीता लेकिन जीत से ज्यादा चर्चा इस टिप्पणी की हो रही है। हम नस्लवाद के बिल्कुल खिलाफ है। इस तरह की घटना फिर नहीं होनी चाहिए। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने एक बयान में कहा कि वह मंगलवार को आर्चर से माफी मांगेगा। वहीं कीवी कोच गैरी स्टीड ने कहा कि उनके कुछ गेंदबाज भी आर्चर से बात करेंगे। भीड़ में से किसी एक मूर्ख ने टिप्पणी की है। उम्मीद है कि उसे सजा मिलेगी। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि मामले की मांच में वे न्यूजीलैंड क्रिकेट की मदद कर रहे हैं।

दलीप ट्राफी में टीम भावना का अभाव : सचिन

● उम्मीद है कि गांगुली इसमें सुधार करेंगे

भाषा। कोलकाता

चैम्पियन क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का मानना है कि दलीप ट्राफी में खिलाड़ियों का ध्यान टीम से अधिक व्यक्तिगत प्रदर्शन पर रहता है और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली को इसमें बदलाव करना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि गांगुली दलीप ट्राफी को देखें। यह ऐसा टूर्नामेंट है कि खिलाड़ी अपने प्रदर्शन और अगले टूर्नामेंट पर ज्यादा फोकस करते हैं और उसी के अनुसार खेलते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आईपीएल की नीलामी है या टी20 टूर्नामेंट या वनडे है तो खिलाड़ी उसी तरह से खेलते हैं। वे टीम के लिए नहीं खेलते। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। दलीप ट्राफी पांच टीमों का क्षेत्रीय टूर्नामेंट था लेकिन अब इसमें इंडिया ब्लू, इंडिया ग्रीन और इंडिया रेड टीमें राउंड राबिन प्रारूप में खेलती हैं। तेंदुलकर ने कहा , मैं इसमें बदलाव देखना चाहता हूं क्योंकि क्रिकेट हमेशा से टीम का खेल रहा है। यह टीम भावना और एक टीम के रूप में साथ खेलने को लेकर है। इसमें व्यक्तिगत प्रदर्शन पर फोकस नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसे रणजी ट्राफी फाइनल के तुरंत बाद खेला जाना चाहिए और उन चार टीमों के बीच होना चाहिए जो सेमीफाइनल तक पहुंची हैं और पूरा सत्र साथ में खेलती हैं। शीर्ष चार रणजी टीमों के साथ दो और टीमें इसमें हों क्योंकि ऐसी कई टीमें होंगी जिनमें प्रतिभाशाली खिलाड़ी होंगे लेकिन क्वालीफाई नहीं कर पाती। अंडर 19, अंडर 23 अलग अलग टीमों से इन खिलाड़ियों को लिया जा सकता है।

क्रिकेटर फिलीप ह्यूज को पांचवीं बरसी पर श्रद्धांजलि

मेलबर्न। क्रिकेट आस्ट्रेलिया ने फिलीप ह्यूज की पांचवी बरसी पर उन्हे श्रृद्धांजलि दी। ह्यूज का एक घरेलू मैच में शार्ट पिच गेद लगने के कारण निधन हो गया था। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर 25 नवंबर 2014 को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान ह्यूज को सीन एबोट का बाउंसर लगा था। उन्होने हेलमेट पहना था लेकिन गेद उनके बाएं कान के ठीक नीचे वाले हिस्से पर लगी जो ढका हुआ नही था। क्रिकेट आस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी केविन राबर्टस ने कहा , पिछले पांच साल में ऐसा कोई दिन नही गुजरा जब आस्ट्रेलियाई क्रिकेट जगत को फिल की कमी नही खली हो। ह्यूज ने आस्ट्रेलिया के लिए 25 टेस्ट और 24 वनडे मैच खेले थे। उन्होने इंग्लैंड मे काफी समय काउंटी क्रिकेट भी खेला।

हेजलवुड अपने 50वें टेस्ट मैच में गुलाबी गेंद से गेंदबाजी को लेकर उत्सुक

ब्रिस्बेन। आस्ट्रेलिया के तेज गेदबाज जोश हेजलवुड अपने करियर के 50वे टेस्ट मैच मे गुलाबी गेद से गेदबाजी करने को लेकर काफी उत्सुक है। पाकिस्तान के खिलाफ शुक्रवार से शुरु हो रहे श्रृंखला का दूसरा मैच एडीलेड मे दिन-रात्रि मे गुलाबी गेद से खेला जाएग। एडीलेड ओवल मैदान मे 28 साल के इस तेज गेदबाज का रिकार्ड शानदार है जहां उन्होने चार मैचो मे 20.22 की औसत से 22 विकेट लिए है। गुलाबी गेद से उनकी गेदबाजी और भी मारक हो जाती है जहां दिन रात्रि प्रारूप मे खेले गए तीन मैचो मे उन्होने 19.44 की औसत से 18 विकेट लिए है। हेजलवुड ने क्रिकेट डाट काम डाट एयू से कहा, मुझे लगता है कि एडीलेड से मुझे सबसे ज्यादा लगाव है। मुझे वहां अच्छी सफलता मिली है। मुझे लगता है एडीलेड मे गुलाबी गेद का बर्ताव वैसा ही होता है जैसा यहां (ब्रिस्बेन का गाबा मैदान) लाल गेद का होता है। आईसीसी गेदबाजो की रैंकिंग मे 13वे स्थान पर काबिज इस खिलाड़ी ने कहा, गुलाबी गेद शायद ज्यादा देर तक स्विंग करती है और अगर आपको रात मे नई गेद मिल जाए तो आप काफी कुछ कर सकते है मिला है। मै इसके लिए मैदान मे उतरने को उत्सुक हूं। मै श्रीलंका के खिलाफ पिछले साल यहां खेलने से चूक गया था, इसलिए मैं गुलाबी गेद से गेदबाजी करने का इंतजार कर रहा हूं।

बीबीएल में मेलबर्न रेनेगेड्स के कोच बने क्लिंगर

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया के पूर्व टी20 बल्लेबाज माइकल क्लिंगर को बिग बैश लीग टी20 टूर्नामेंट के आगामी सत्र के लिए मेलबर्न रेनेगेड्स का कोच बनाया गया है। क्लिंगर ने पिछले सत्र मे बीबीएल से संन्यास ले लिया था। वह बीबीएल के इतिहास के सबसे सफल बल्लेबाज है। इस टी20 टूर्नामेंट मे उनके नाम पर आठ सत्र मे एक शतक और 12 अर्धशतक की मदद से 1947 रन दर्ज है। ईएसपीएनक्रिकइंफो की खबर के अनुसार एडिलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ स्कोरचर्स का भी हिस्सा रह चुके 39 बरस के क्लिंगर एंड्रयू मैकडोनाल्ड की जगह लेगे जिन्हे आस्ट्रेलिया का सहायक कोच नियुक्त किया गया है। मैकडोनाल्ड के मार्गदर्शन मे रेनेगेड्स ने बीबीएल खिताब जीता था। क्लिंगर भी जस्टिन लैगर के मार्गदर्शन मे स्कोरचर्स के साथ दो खिताब जीत चुके है। एक दशक से अधिक समय तक घरेलू क्रिकेट मे सभी प्रारूपो मे दबदबा बनाने वाले क्लिंगर 2017 मे आस्ट्रेलिया के लिए तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले। क्लिंगर को मुख्य कोच के पद पर इससे पहले कोई अनुभव नही है। उन्होंने हालांकि कप्तानी का काफी अनुभव है और वह इंग्लैंड मे टी20 ब्लास्ट मे पिछले चार सत्र ग्लास्टरशर के कप्तान रहे। उन्होने इस टीम के बल्लेबाजी सलाहकार के रूप मे भी काम किया। क्लिंगर ने कहा, मौजूदा बीबीएल चैंपियन टीम को कोचिंग देने का मौका मिलना बड़े सम्मान की बात है।

अगले साल भविष्य पर फैसला करेंगे धोनी

● आईपीएल के बाद लेंगे फैसला

भाषा। नई दिल्ली

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अगले साल इंडियन प्रीमयर लीग (आईपीएल) के बाद अपने भविष्य को लेकर फैसला करेंगे। इस स्टार क्रिकेटर के करीबी सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी जिससे उनके करियर को लेकर लंबे समय से चल रहा अटकलबाजियों का दौर थम सकता है।

भारत के जुलाई में इंग्लैंड में खेले गए वनडे विश्व कप से सेमीफाइनल में बाहर होने के बाद से ही धोनी किसी मैच में नहीं खेले हैं। वह वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं गए और इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू श्रृंखलाओं में भी नहीं खेले। सूत्रों ने कहा, धोनी अगर अपने भविष्य को लेकर कोई फैसला करेंगे तो ऐसा आईपीएल के बाद ही होगा। आप अटकलों पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि वह बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वह फिटनेस के लिहाज से बेहतरीन स्थिति में हैं और पिछले एक महीने से कड़ा अभ्यास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, लेकिन वह आईपीएल से पहले कितने प्रतिस्पर्धी मैच खेलेंगे इसका फैसला उचित समय पर किया जाएगा। आईपीएल में चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान 38 वर्षीय धोनी वेस्टइंडीज के खिलाफ छह दिसंबर से शुरू होने वाली सीमित ओवरों की श्रृंखला में भी नहीं खेलेंगे। इस श्रृंखला में तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय और इतने ही वनडे खेले जाएंगे। राष्ट्रीय चयनसमिति के अध्यक्ष एमएसके प्रसाद पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि पैनल अब भविष्य के बारे में सोच रहा है और धोनी आस्ट्रेलिया में अगले साल होने वाले टी20 विश्व कप को ध्यान में रखते हुए ऋषभ पंत जैसे युवा खिलाड़ियों को अधिक मौके देने के उनके इरादों से वाकिफ हैं। पंत हालांकि अब तक मौकों का फायदा नहीं उठा पाए हैं और विकेटकीपर के रूप में लचर प्रदर्शन के लिए उनकी लगातार आलोचना होती रही है। हाल में डीआरएस में गलत फैसलों के लिए भी पंत की आलोचना हुई थी जबकि इस मामले में धोनी लाजवाब हैं। धोनी ने अपनी तरफ से हालांकि अपने भविष्य को लेकर कोई बात नहीं की है। उन्हें हालांकि कुछ दिन पहले झारखंड अंडर-23 टीम के साथ अभ्यास करते हुए देखा गया था जिसके बाद उनकी संभावित वापसी की अटकल लगाई जाने लगी थी।

बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने भी कहा है कि धोनी को वही सम्मान दिया जाएगा जिसका उन जैसा दिग्गज खिलाड़ी हकदार है। उन्होंने इस स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज के तुरंत ही संन्यास लेने से भी इन्कार किया। पिछले महीने बोर्ड अध्यक्ष का पद संभालने के बाद गांगुली ने कहा, आप जानते हैं कि चैंपियन्स जल्द खत्म नहीं होते। धोनी की अगुवाई में भारत ने टी20 विश्व कप 2007 और वनडे विश्व कप 2011 में खिताब जीते थे। उन्होंने 90 टेस्ट, 350 वनडे और 98 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं जिनमें 17 हजार से अधिक रन बनाए हैं।

रूस पर प्रतिबंध की सिफारिश स्वीकार होगी

भाषा। मास्को

● रूस के डोपिंग रोधी प्रमुख को आशंका

रूस के डोपिंग रोधी प्रमुख यूरी गानुस ने मंगलवार को कहा कि उन्हें लगता है कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (वाडा) रूस को चार साल के लिए सभी खेलों से प्रतिबंधित करने की सिफारिश स्वीकार कर लेगी। रूसी डोपिंग रोधी एजेंसी (आरयूएसएडीए) के प्रमुख यूरी ने सोमवार को वाडा के महत्वपूर्ण पैनल की सिफारिश के बाद कहा, यह सच्चाई है। पैनल ने मास्को पर जांचकर्ताओं को सौंपे गए प्रयोगशाला के आंकड़ों में हेरफेर का आरोप लगाया है। यूरी ने कहा, हम बाहर होने वाले हैं, अगले चार साल के लिए, रूस के डोपिंग संकट का नया चरण। चार साल लंबा समय है, यह दो ओलंपिक हैं। यूरी ने कहा कि रूस को तुरंत नए खेल प्रबंधन की जरूरत है और उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्तक्षेप की मांग की। ईमानदारी से कहूं तो मैं इंतजार कर रहा हूं कि राष्ट्रपति इसमें सक्रिय भूमिका निभाएं। यूरी ने कहा, यहां खेलों में काफी समस्याएं हैं लेकिन सबसे मुश्किल और त्रासदीपूर्ण चीज यह है कि हमारे खिलाड़ियों को हमारे खेल अधिकारियों की करनी का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वाडा की अनुपालन समीक्षा समिति (सीआरसी) ने बयान जारी करके प्रतिबंध की मांग की थी जिससे रूस अगले साल होने वाले तोक्यो ओलंपिक से बाहर हो जाएगा। इसे नौ दिसंबर को पेरिस में होने वाली बैठक में स्वीकृति मिल सकती है।

सिंधू, ताइ जू के लिए सर्वाधिक 77 लाख की बोली

● पीबीएल नीलामी

भाषा। नई दिल्ली

विश्व चैंपियन पीवी सिंधू को यहां प्रीमियर बैडमिंटन लीग के पांचवें सत्र की नीलामी में मंगलवार को हैदराबाद हंटर्स ने 77 लाख रुपए की बोली लगाकर अपने साथ बरकरार रखा। दुनिया की नंबर एक महिला खिलाड़ी चीनी ताइपे की ताइ जू यिंग के लिए गत चैंपियन बेंगलुरू रैपटर्स ने 77 लाख रुपए की संयुक्त रूप से सर्वोच्च बोली लगाई। रैपटर्स ने बोली में पुणे 7 एसेस को पछाड़कर ताइ जू को अपने साथ जोड़ा।भारत के शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल बी साई प्रणीत को रैपटर्स की टीम ने 32 लाख रुपए खर्च करके अपने साथ बरकरार रखा। चेन्नई सुपरस्टार्ज ने पुरुष युगल खिलाड़ी बी सुमित रेड्डी को 11 लाख रुपए जबकि पुणे 7 एसेस ने चिराग शेट्टी को 15 लाख 50 हजार रुपए खर्च करके अपने साथ जोड़े रखा। दुनिया की नौवें नंबर की अमेरिकी महिला एकल खिलाड़ी बेइवान झेंग भी अवध वारियर्स के साथ बकरार रहेंगी जिनके लिए टीम ने 39 लाख रुपए खर्च किए। राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद की बेटी गायत्री गोपीचंद को चेन्नई की टीम ने चुना जबकि असम की युवा खिलाड़ी अश्मिता चालिहा को उनकी घरेलू टीम नार्थ ईस्टर्न वारियर्स ने तीन लाख रुपए में खरीदा। पीबीएल के पांचवें सत्र की चमक हालांकि उस समय कुछ फीकी हो गई जब लंदन ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल और किदांबी श्रीकांत ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर पर ध्यान देने के लिए इस टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया। साई प्रणीत, लक्ष्य सेन और पुरुष युगल खिलाड़ी सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी सहित 154 खिलाड़ी नीलामी का हिस्सा थे। पीबीएल का अगला सत्र 20 जनवरी से नौ फरवरी तक खेला जाएगा जिसमें 74 भारतीय खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बेंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद और लखनऊ में होने वाली इस 21 दिवसीय प्रतियोगिता में सात टीमें अवध वारियर्स (लखनऊ), बेंगलुरु रेपटर्स (बेंगलुरु), मुंबई राकेट्स (मुंबई), हैदराबाद हंटर्स (हैदराबाद), चेन्नई सुपरस्टार्ज (चेन्नई), नार्थ ईस्टर्न वारियर्स (पूर्वोत्तर) और पुणे 7 एसेस (पुणे) की टीमें हिस्सा लेंगी। प्रत्एक फ्रेंचाइजी के पास खर्च करने के लिए दो करोड़ रुपए थे लेकिन वे एक खिलाड़ी पर 77 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकती थी। टीम में अधिकतम 11 खिलाड़ी हो सकते हैं जिसमें अधिकतम छह विदेशी खिलाड़ी और कम से कम तीन महिला खिलाड़ी होनी चाहिए। पीबीएल के आगामी सत्र में पिछली बार वाला प्रारूप बरकरार रहेगा जिसमें प्रत्एक मुकाबले में पांच मैच (दो पुरुष एकल, एक महिला एकल, एक पुरुष युगल और एक मिश्रित युगल) होंगे।

विश्व स्तरीय अंपायर तैयार करने में एक दशक लग जाता है : टोफेल

भाषा। नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एलीट पैनल में अभी कोई भारतीय अंपायर शामिल नहीं है और प्रतिष्ठित अंपायर साइमन टोफेल को निकट भविष्य में भी किसी भारतीय के इसमें जगह बनाने की उम्मीद नहीं है क्योंकि उनका मानना है कि एक विश्व स्तरीय अधिकारी को तैयार करने में एक दशक का समय लगता है। पैनल में 2015 से भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे एस रवि को इस साल की शुरुआत में हटा दिया गया। उन्होंने एशेज सहित 33 टेस्ट, 48 एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय और 18 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में अंपायरिंग की। अब संन्यास ले चुके और 2004 से 2008 के बीच दुनिया के नंबर एक अंपायर रहे टोफेल ने पीटीआई से कहा, विश्व स्तरीय अंपायर तैयार करने में 10 साल का समय लगता है। मुझे याद है कि 2006 में जब हमने भारत में हमारा कार्यक्रम शुरू किया था, इसके बाद एस रवि को एलीट पैनल में शामिल होने में 10 साल लगे। उन्होंने कहा, इसलिए मुझे लगता है कि पुनर्विचार की जरूरत है (बीसीसीआई की ओर से)। मैं सुनिश्चित नहीं हूं कि कुछ गलत है। उन्हें अंपायरों की जरूरत है और सौरव गांगुली (बीसीसीआई के नए प्रमुख) जब घरेलू क्रिकेट को मजबूत करने की बात करते हैं तो संभवत: वह सही राह पर हैं और उम्मीद करता हूं कि अंपायरिंग भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होगा। टोफेल ने कहा कि जल्द ही एलीट पैनल में किसी भारतीय के शामिल होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि इस प्रक्रिया में समय लगता है। एस वेंकेटराघवन के बाद 53 साल के रवि 12 सदस्ईय आईसीस एलीट पैनल में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय थे। इस आस्ट्रेलियाई कोच ने कहा, यह सिर्फ अंपायरों की बात नहीं है, यह ढांचे और व्यवस्था की बात है। यह उस माहौल को तैयार करने की बात है जहां अंपायर प्रगति कर सकें। इसका मतलब है कि आपके पास समर्पित संसाधन होने चाहिए। आपको पास अंपायर मैनेजर, अंपायर कोच, अंपायर ट्रेनर होना चाहिए। टोफेल 2012 में संन्यास के बाद अक्टूबर 2015 तक आईसीसी के अंपायर परफोर्मेंस एवं ट्रेनिंग मैनेजर रहे।

तीन भारतीय तीरंदाजों ने कांसे पर साधा तीर

● एशियाई तीरदांजी चैंपियनशिप

भाषा। बैंकाक

अतनु दास की अगुवाई में भारतीय तीरंदाजों ने मंगलवार को एशियाई चैंपियनशिप में तीन कांस्य पदक जीते जबकि कम से कम तीन रजत पदक पक्के किए। भारतीय तीरंदाजी महासंघ के निलंबन के कारण भारत के खिलाड़ी विश्व तीरंदाजी संघ के ध्वज तले खेल रहे हैं। दास ने सबसे पहले पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने कोरिया के जिन हाएक ओह को कांस्य पदक के शूटआफ मुकाबले में 6-5 से हराया। सोमवार को मिश्रित रिकर्व वर्ग में दीपिका कुमारी के साथ कांसा जीतने वाले दास ने बाद में पुरुष रिकर्व टीम के साथ भी पदक हासिल करके कांस्य पदक की हैट्रिक पूरी की। दास ने सीनियर खिलाड़ी तरुणदीप राय और जयंत तालुकदार के साथ मिलकर कांस्य पदक मुकाबले में चीन को 6-2 से हराया। दीपिका कुमारी, लेशराम बोम्बायला देवी और अंकिता भक्त की रिकर्व महिला टीम ने जापान को 5-। से हराकर कांस्य पदक जीता। भारत की यह टीम इससे पहले सेमीफाइनल में कोरिया से 2-6 से हार गई थी। भारत के तीन तीरंदाज कंपाउंड वर्ग के फाइनल में पहुंचने में सफल रहे। फाइनल बुधवार को खेले जाएंगे। अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और मोहन भारद्वाज की भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में ईरान को 229-221 से हराकर फाइनल में जगह बनाई जहां उनका मुकाबला कोरिया से होगा। ज्योति सुरेखा वेनाम, मुस्कान किरार और प्रिया गुर्जर ने भी ईरान को 227-221 से पराजित करके फाइनल में प्रवेश किया। खिताबी मुकाबले में उनका सामना भी कोरिया से होगा। वर्मा और ज्योति की कंपाउंड मिश्रित जोड़ी पहले ही फाइनल में पहुंच चुकी है जहां उनका मुकाबला चीनी ताइपै से होगा।

शीर्ष 20 में जगह बनाना मेरे लिए डकार रैली जीतने जैसा : सीएस संतोष

नई दिल्ली। अपनी सीमाओं से अच्छी तरह से वाकिफ भारत के चोटी के राइडर सीएस संतोष का मानना है कि अगले साल होने वाली डकार रैली में शीर्ष 20 में जगह बनाना उनके लिए विश्व की सबसे मुश्किल रैली को जीतने जैसा होगा जो पहली बार सऊदी अरब में आयोजित की जाएगी। हीरो मोटोस्पोर्ट्स ने 2020 डकार रैली के लिए मंगलवार को अपनी चार सदस्ईय टीम घोषित की जिसमें संतोष के अलावा जोकिम रोड्रिग्स, ओरियल मेना और पाउलो गोंजालेज शामिल हैं। भारत के 35 वर्षीय राइडर संतोष तीसरी बार इस रैली में भाग लेंगे। वह 2018 में 34वें स्थान पर रहे थे जबकि 2019 में उनका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। संतोष ने कहा, मुझ जैसा खिलाड़ी कभी डकार जीतने का लक्ष्य नहीं रखता लेकिन मैं सर्वश्रेष्ठ राइडर में एक हो सकता हूं। मैं जब से विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा हूं तब से मैंने कई बार अच्छे परिणाम हासिल किए। मैं शीर्ष 20 में भी शामिल रहा जो कि बहुत अच्छा है। अगर मैं शीर्ष 20 में जगह बनाता हूं तो यह डकार जीतने जैसा होगा। मेरा यह पहला लक्ष्य है जिसे मैं हासिल करना चाहता हूं। इसके बाद हम देखेंगे कि मैं कहां तक जा सकता हूं। अगली डकार रैली सऊदी अरब में होगी जिसमें चालकों को कुल 7500 मीटर का दुर्गम रास्ता तय करना होगा। यह रैली 12 चरणों में होगी।

सैग में भारतीय ताइक्वांडो टीम को मौका मिलने की उम्मीद

● आईओसी के दखल के बाद हो सकता है फैसला

भाषा। नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) के दखल के बाद भारतीय ताइक्वांडो टीम की अगले महीने नेपाल में होने वाले दक्षिण एशियाई खेलों (सैग) में मौका मिलने की संभावना बढ़ गई है। आईओसी ने इन खेलों के आयोजकों से भारत को भाग लेने की अनुमति देने को कहा है। नेपाल ओलंपिक समिति ने 23 नवंबर को इन खेलों के लिए भारत की तीरंदाजी, ताइक्वांडो और कराटे की टीमों के भाग लेने पर रोक लगा दी थी। नेपाल का कहना है कि इन खेलों के राष्ट्रीय महासंघ को विश्व निकाय द्वारा निलंबित किया गया है और उन्हें राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता भी नहीं मिली है। ताइक्वांडो की वैश्विक इकाई विश्व ताइक्वांडो (डब्ल्यूटी) ने आयोजकों से एक विशेष विचार के तहत भारतीय टीम को इन खेलों में भाग लेने की अनुमति देने को कहा है।

डब्ल्यूटी के सदस्य संबंध और विकास वरिष्ठ निदेशक जोंगकांग सेओ ने आयोजकों को लिखे पत्र में कहा, यह सच है कि भारतीय ताइक्वांडो महासंघ (टीएफआई) को संचालन के मुद्दे पर डब्ल्यूटी ने निलंबित किया है। भारतीय ओलंपिक समिति और डब्ल्यूटी द्वारा गठित अंतरिम इकाई हालांकि मान्यता प्राप्त प्रतियोगिताओं में के लिए खिलाड़ियों के चयन का ध्यान रखती है। डब्ल्यूटी का समर्थन करते हुए आईओसी के एनओसी संबंध विभाग के प्रमुख जेरोम पाइवे ने मंगलवार को नेपाल ओलंपिक समिति के अध्यक्ष जीवन श्रेष्ठा से एक से नौ दिसंबर तक होने वाले खेलों में भारतीय टीम की भागिदारी सुनिश्चित करने को कहा। पोइवे ने अपने पत्र में लिखा,, हम डब्ल्यूटी के विचारों का पूरा समर्थन करते हैं। आपके एनओसी और आयोजन समिति से गुजारिश है कि डब्ल्यूटी के निर्देशों के मुताबिक भारत को भाग लेने का मौका दें।

स्मिथ ने दिया यासिर के इशारे का जवाब

भाषा। एडीलेड

लेग स्पिनर यासिर शाह के सात उंगली वाले इशारे ने आस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ को इस पाकिस्तानी गेंदबाज के खिलाफ बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। यासिर ने ब्रिस्बेन में श्रृंखला के पहले टेस्ट में स्मिथ का विकेट लेने के बाद जश्न मनाते हुए अपनी सात उंगलियां दिखाई थी जिसका मतलब यह था कि खेल के सबसे लंबे प्रारूप में उन्होंने इस बल्लेबाज को सातवीं बार पवेलियन भेजा। स्मिथ से मंगलवार को यहां संवादाता सम्मेलन में जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अब इस गेंदबाज के खिलाफ सतर्क रहेंगे। उन्होंने कहा, यह (यासिर के सात उंगली दिखाने) मुझे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अधिक प्रेरित करेगा कि मैं इस गेंदबाज के खिलाफ आउट नहीं होऊं। मैं उसके खिलाफ ज्यादा अनुशासन से खेलूंगा। उन्होंने हालांकि यासिर की उपलब्धि को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हुए कहा, यह दिलचस्प है। उसने मुझे ऐसे समय आउट किया है जब मैं क्रीज पर नया था और तेजी से रन बनाने की जरूरत थी। दो बार शायद मैं दूसरी पारी में आउट हुआ हूं जहां मैं थोड़ बेपरवाह हो कर खेल रहा था। मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूं।

वेस्टइंडीज पर विश्व रिकार्ड बनाने उतरेगा अफगानिस्तान

● एकमात्र टेस्ट मैच आज से

पायनियर समाचार सेवा। .लखनऊ

टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के बाद भारत को छोड़कर अन्य टीमों के खिलाफ दमदार प्रदर्शन करने वाली अफगानिस्तान की टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ बुधवार से यहां शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट मैच में जीत दर्ज करके विश्व रिकार्ड बनाने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगी। अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमें लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेई इकाना स्टेडियम में यह मैच खेलेंगी। अफगानिस्तान इसे घरेलू मैदान के तौर पर उपयोग कर रहा है। वनडे सीरीज में हार के बाद टी20 श्रंखला में वेस्टइंडीज को पटखनी देने वाली अफगानिस्तान की टीम इस टेस्ट को जीतकर अपने शुरुआती चार टेस्ट मुकाबलों में से तीन को जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बनना चाहेगी। अफगानिस्तान ने पिछले साल भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट गंवाने के बाद आयरलैंड और बांग्लादेश को हराया था। अगर वह इस टेस्ट में वेस्टइंडीज को हरा देती है तो नया कीर्तिमान रच देगा। स्पिनरों के लिए की मददगार पिच पर बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा होने के आसार हैं। पिछले दिनों ड्रॉ छूटे अभ्यास मैच में पिच का ऐसा ही व्यवहार देखा गया था और पहली पारी में कोई भी टीम घूमती गेंदों के आगे 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई थी। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी में धाकड़ मानी जाने वाली वेस्टइंडीज और अफगानिस्तान दोनों की टीमों के सामने टी20 के खुमार से बाहर आने की चुनौती होगी। स्पिनरों के माफिक पिच पर बल्लेबाजों को टिककर खेलने का माद्दा दिखाना होगा। जो टीम इसमें ज्यादा सफल होगी, बाजी उसी के हाथ लगने की सम्भावना है। अफगानिस्तान पर नजर डालें तो वनडे और टी20 सीरीज में रहमत शाह को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज टिककर खेलने की क्षमता नहीं दिखा सका। दूसरी ओर, आलराउंडर जैसन होल्डर की अगुवाई वाली वेस्टइंडीज के पास शाई होप, क्रेग ब्रेथवेट और रोस्टन चेज जैसे मंझे हुए बल्लेबाज हैं। यह पहलू कैरेबियाई टीम के पक्ष में है। वहीं, सबकी निगाहें अफगान कप्तान राशिद खान पर भी होंगी, जो पिछली चार टेस्ट पारियों में तीन बार पांच या उससे ज्यादा विकेट ले चुके हैं। स्पिनरों के लिए अनुकूल परिस्थितियों में अफगानिस्तान तीन फिरकी गेंदबाजों राशिद, कैस अहमद और जहीर खान के साथ उतरेगी। वहीं, वेस्टइंडीज में स्पिन का दारोमदार चेज और भारीभरकम क्रिकेटर रहकीम कॉर्नवाल पर रहेगा। टी20 में जोरदार प्रदर्शन करने वाले करीम जनत को टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके अफगान आलराउंडर मोहम्मद नबी के स्थान पर टीम में शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 25 साल के बाद कोई अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला जाएगा। इससे पहले वर्ष 1994 में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें भारत ने पारी और 119 रन से जीत दर्ज की थी।

टीमें :अफगानिस्तान राशिद खान (कप्तान), इब्राहीम जादरान, इहसानउल्ला, रहमत शाह, जावेद अहमदी, असगर अफगान, करीम जनत, अफसर जजई (विकेटकीपर), कैस अहमद, यामीन अहमदजई और जहीर खान में से।
वेस्टइंडीज जेसन होल्डर (कप्तान), क्रेग ब्रेथवेट, शाई होप, शामराह ब्रुक्स, सुनील एम्ब्रिस, रोस्टन चेज, शिमरॉन हेटमेयर, शेन डॉरिच, रहकीम कॉर्नवाल, केमार रोच, जोमेल वारिकन में से।

भारत अंडर-19 टीम को मिली हार

● अफगानिस्तान ने तीन विकेट से हराया

लखनऊ

बल्लेबाजों के गैरजिम्मेदराना प्रदर्शन के कारण भारतीय अंडर19 टीम को कम स्कोर वाले तीसरे युवा एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच में मंगलवार को यहां अफगानिस्तान से तीन विकेट से पराजय का सामना करना पड़ा जो पांच मैचों की श्रृंखला में उसकी पहली हार है।
भारतीय टीम 49 ओवर में 152 रन आउट हो गई। अफगानिस्तान अंडर19 ने 46.2 ओवर में 155 रन बनाकर तीन विकेट से मैच अपने नाम किया। भारतीय टीम हालांकि पहले दोनों मैच जीतने के कारण श्रृंखला में 2-। से आगे है। पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिलने पर भारतीय टीम लगातार अंतराल पर विकेट गंवाती रही। पारी के 22वें ओवर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद पदार्पण कर रहे विक्रांत भदौरिया (39) और कप्तान शुभांग हेगड़े (46) ने छठे विकेट के लिए 73 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 120 के पार पहुंचाया। इस जोड़ी के टूटने के बाद हालांकि एक बार फिर पारी लड़खड़ा गई और पूरी टीम 152 रन पर आउट हो गई। अफगानिस्तान के लिए आबिद मोहम्मदी ने चार जबकि अब्दुल रहमान ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए इमरान (34) और विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद इशाक (32) ने दूसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी कर जीत की नींव रखी। इस साझेदारी को हेगड़े (10 ओवर में 20 रन पर दो विकेट) ने इशाक को आउट कर तोड़ा। जिसके बाद भारतीय गेदबाजों ने कसी हुई गेंदबाजी की लेकिन रहमानुल्लाह (21) और रहमान (नाबाद 26) के उपयोगी योगदान से अफगानिस्तान अंडर19 ने मैच अपने नाम कर लिया। भारत के लिए कार्तिक त्यागी सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने 10 ओवर में 24 रन देकर तीन विकेट लिए। श्रृंखला का चौथा मुकाबला 28 नवंबर को खेला जाएगा।

सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेंगी विनेश और साक्षी

जालंधर। विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता विनेश फोगाट और ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक जालंधर में 29 नवंबर से एक दिसंबर के बीच होने वाली सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आकर्षण का केंद्र होंगी। इस चैंपियनशिप में 500 से अधिक पहलवान पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको रोमन और महिला स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। महिला वर्ग में भाग लेने वाली खिलाड़ियों में तोक्यो ओलंपिक में पदक की दावेदार विनेश (55 किग्रा), ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक (62 किग्रा), उदीयमान दिव्या काकरान (68 किग्रा), सीमा बिस्ला (50 किग्रा), सरिता मोर (57 किग्रा) और नवजोत कौर (65 किग्रा) प्रमुख है। इस टूर्नामेंट में कुछ रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते है। दिव्या काकरान को 68 किग्रा में पिंकी से कड़ी चुनौती मिल सकती है। नवजोत कौर को अपने भार वर्ग में गार्गी यादव की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। पुरुष वर्ग में ग्रीको रोमन के स्टार सजन (77 किग्रा) के अलावा चोटी के फ्रीस्टाइल पहलवान गौरव बालियान (74 किग्रा), सुमित मलिक (125 किग्रा), सत्यव्रत कादियान (97 किग्रा) और राहुल मान (70 किग्रा) पर निगाहे टिकी रहेगी।

फीफा ने कोलकाता में अंडर-17 महिला विश्व कप की तैयारी का निरीक्षण शुरू किया

कोलकाता। फीफा का आठ सदस्ईय प्रतिनिधिमंडल 2020 में होने वाले अंडर-17 महिला फुटबाल विश्व कप के आयोजन स्थलों की प्रगति और तैयारी का जायजा लेने के लिए मंगलवार को आधिकारिक निरीक्षण के लिए यहां पहुंचा। निरीक्षण से पूर्व अंडर-17 महिला विश्व कप के परियोजना प्रमुख ओलिवर वोगट ने कहा, हम यह देखने के लिए उत्सुक है कि चीजे कैसी रहती है। हमने 2017 में पुरुष टूर्नामेंट के आयोजन के साथ भारत में फुटबाल की क्षमता देखी और समझा कि यहां कोलकाता में यह कितना अधिक सफल था। फीफा और स्थानीय आयोजन समिति (एलओसी) का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को कोलकाता में स्टेडियम और ट्रेनिंग स्थल का निरीक्षण करेगा जबकि गुरुवार को गुवाहाटी में निरीक्षण होगा। वोगट ने कहा, हमे भरोसा है कि प्रत्एक हितधारक यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करेगा कि 2020 में होने वाले फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप सफल रहे और यह टूर्नामेंट महिला फुटबाल के इतिहास में छाप छोड़े। इस दौरे पर स्टेडियम और ट्रेनिंग स्थलों का बुनियादी ढांचा देखने के अलावा हमारी यह देखने में भी रुचि होगी कि भविष्य में देश में महिला फुटबाल के विकास के लिए विभिन्न आयोजन स्थलों ने क्या योजना बनाई है। टूर्नामेंट का आयोजन अगले साल दो से 21 नवंबर तक किया जाएगा।

यूरोपीय चैम्पियन लोनाह होंगी कोलकाता 25के की मुख्य आकर्षण

कोलकाता। मौजूदा यूरोपीय चैम्पियन (10 हजार मीटर) इसाइल की लोनाह सालपेटर 25 दिसंबर को यहां आयोजित होने वाली टाटा स्टील कोलकाता 25के दौड़ के एलीट महिला वर्ग में मुख्य आकर्षण होंगी। खिताब की दावेदार लोनाह को यहां तंजानिया की फैलूना मतंगा से कड़ी चुनौती मिलेगी जो इस दौड़ के पिछले दो सत्र में तीसरे स्थान पर रही थी। इस बार उनकी कोशिश प्रदर्शन में सुधार करके खिताब जीतने की होगी। इस साल रिगा मैराथन और सेविला मैराथन में जीत दर्ज करने वाली इथोपिया की धावक क्रमशः बिर्के देबेले और गुटेनी शोन यहां अपनी सफलता को दोहराना चाहेगी। पुरुषो के वर्ग में कीनिया के लियोनार्ड बारसोटन और इथोपिया के तारिकु बेकेले शीर्ष खिलाड़ी होंगे। तारिकु 2017 के विजेता केन्ड़ेइसा बेकेले के भाई है। बेकेले लंदन ओलंपिक में 10,000 मीटर स्पर्धा में कांस्य जीत चुके है जबकि बारसोटोन विश्व क्रास कंट्री में दो बार के रजत पदक विजेता है। ए पदक उन्होंने 2013 में अंडर 20 और फिर 2017 में सीनियर स्तर पर जीता।

भारतीय तेज गेंदबाजों ने विश्व क्रिकेट को रोमांचक बना दिया है : सिमन्स

लखनऊ। वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर फिल सिमन्स ने कहा कि वर्तमान भारतीय तेज गेंदबाजी आक्रमण ने विश्व क्रिकेट को रोमांचक बना दिया है। भारतीय तेज गेंदबाजों ने जसप्रीत बुमराह की अनुपस्थिति के बावजूद बांग्लादेश के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन जिससे टीम ने यह श्रृंखला आसानी से 2-0 से जीती। बुमराह की वापसी के बाद आक्रमण अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। इन दो मैचों में बांग्लादेश के बल्लेबाज इशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और उमेश यादव का सामना नही कर पाए।
सिमन्स वेस्टइंडीज की उस टीम का हिस्सा थे जिसकी एक समय तूती बोलती थी। ईएसपीएनक्रिकइन्फो के अनुसार उन्होंने कहा, मै यह नही कह सकता कि यह कितने समय पहले की बात है लेकिन जब मै पहली बार यहां आया था तो तब मदनलाल गेंदबाजी का आगाज करते थे। अब आपके पास ऐसे गेंदबाज है जो 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते है और आपका मुख्य तेज गेंदबाज (बुमराह) चोटिल है। उसे अभी वापसी करनी है। यह विश्व क्रिकेट के लिए रोमांचक है।

आनंद ग्रैंड शतरंज टूर से बाहर

● कार्लसन को मिले रिकार्ड अंक

भाषा। कोलकाता

विश्वनाथन आनंद मंगलवार को यहां समाप्त हुए टाटा स्टील रैपिड एवं ब्लिट्ज टूर्नामेंट की आखिरी पांच बाजियों में केवल एक अंक हासिल कर पाए और इस तरह से ग्रैंड शतरंज टूर से बाहर हो गए। मैगनस कार्लसन ने टूर्नामेंट में 27 अंक हासिल किए और इस तरह से उन्होंने ग्रैंड शतरंज टूर में अपना ही पिछला रिकार्ड तोड़ा। उन्होंने इस साल के शुरू में आइवरी कोस्ट के अबिदजान में 26.5 अंक बनाए थे। नार्वे का यह खिलाड़ी अंतिम दिन अपनी सर्वश्रेष्ठ फार्म में नहीं दिखा लेकिन तब भी उन्होंने कुछ शानदार जीत दर्ज की और अमेरिका के हिकारू नकामुरा पर चार अंक की बढ़त के साथ इस चरण में शीर्ष पर रहे। नकामुरा 23 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। कार्लसन के दबदबे का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि संयुक्त तीसरे स्थान पर रहे नीदरलैंड के अनीस गिरी और अमेरिका के वेस्ली सो के 18.5 अंक रहे जो कि चैंपियन से 8.5 अंक कम हैं। चीन के डिंग लीरेन 18 अंक लेकर पांचवें जबकि रूस के इयान नेपोमिनियाची ने 17 अंक के साथ छठा स्थान हासिल किया। आनंद उनसे एक अंक पीछे रहे और उन्हें 16 अंकों के साथ सातवें स्थान से संतोष करना पड़ा। भारत के विदित गुजराती और हरिकृष्णा 14.5 अंक लेकर संयुक्त आठवें स्थान पर रहे। आर्मेनिया के लेवोन आरोनियन को अंतिम स्थान मिला। अगले महीने 50 साल के होने वाले आनंद मामूली अंतर से ग्रैंड शतरंज टूर फिनाले से चूक गए। जब पांच दौर की बाजी बची थी तो लग रहा था कि वह कम से कम अकेले छठे स्थान पर रहकर फिनाले में जगह बना लेंगे। लेकिन हमवतन गुजराती के खिलाफ हार के बाद वह संभल नहीं पाए। गिरी के खिलाफ वह जीत की स्थिति में थे लेकिन उनके पास समय नहीं बचा था। नकामुरा से उन्होंने ड्रा खेला लेकिन कार्लसन के सामने उनकी एक नहीं चली। इस तरह से आनंद 1.5 अंकों से क्वालीफाई करने से चूक गए।

तन्वी, ऋतुपर्णा सैयद मोदी बैडमिंटन के मुख्य ड्रा में

लखनऊ। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी तन्वी लाड और ऋतुपर्णा दास ने मंगलवार को यहां सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल के मुख्य ड्रा में जगह पक्की की। तन्वी ने प्राशी जोशी को 19-21 21-18 21-8 जबकि ऋतुपर्णा ने शिखा गौतम को एकतरफा मुकाबले में 21-10 21-12 से हराया। मुख्य ड्रा के शुरुआती दौर में तन्वी का सामना रूस की नतालिया पेर्मिनोवा से होगा तो वही ऋतुपर्णा को हांगकांग की यिप पुई यिन की चुनौती का सामना करना होगा। मुख्य ड्रा में जगह बनाने वाले भारतीय खिलाड़ियों में में असम की युवा अश्मिता चालिहा और श्रुति मुंदादा भी शामिल हैं। अश्मिता ने आकर्षि कश्यप को 21-13 21-18 जबकि श्रुति ने ऋतिका ठाकेर को 21-19 21-13 से शिकस्त दी। पुरुष एकल में भारत के राहुल यादव चित्ताबोइन, अलाप मिश्रा, और अंसल यादव के साथ चीनी ताइपे के हुआंग पिंग-हिसयन मुख्य ड्रा में पहुंचने में सफल रहे।

आईओए को 2023 आईओसी सत्र के लिए नहीं मिला प्रायोजक

● दिल्ली में हो सकता है आयोजन

भाषा। नई दिल्ली

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने प्रायोजक नही मिलने के कारण 2023 में होने वाले अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) सत्र के लिए नई दिल्ली को वैकल्पिक स्थल में रूप में रखा है। आईओए इस सत्र के आयोजन के लिए पहले ही दावा पेश कर चुका है। आईओए ने पहले 2023 आईओसी सत्र का आयोजन मुंबई में करने का प्रस्ताव रखा था। इस सत्र में 2030 शीतकालीन ओलंपिक खेलो के मेजबान का चयन किया जा सकता है। आईओए ने इस साल जून में आईओसी के 134वे सत्र से इतर आईओसी प्रमुख थामस बाक के पास औपचारिक दावा भी पेश कर दिया था। इस आयोजन के लिए 80 से 90 लाख डालर धनराशि की जरूरत पड़ेगी और प्रायोजको से पुष्टि नही मिलने के कारण आईओए ने अब आईओसी से पूछा है कि क्या मेजबान शहर मुंबई के बजाय नई दिल्ली बदलने का कोई प्रावधान है। बत्रा ने आईओसी के प्रतियोगिता प्रबंधन विभाग को लिखे पत्र में कहा है, औद्योगिक घरानो से 19 नवंबर या 20 या 21 या 22 और यहां तक कि 23 नवंबर तक पेशकश नही मिली जिसे आईओए कार्यकारी बोर्ड के पास चर्चा और फैसले के लिए रखा जा सके। उन्होने कहा, औद्योगिक घरानो को अपना प्रस्ताव आईओए के पास 19 नवंबर से पहले भेजना था ताकि उसे आईओए कार्यकारी बोर्ड के पास रखा जा सके। बत्रा ने पत्र में लिखा है, (आईओए) कार्यकारी बोर्ड जानना चाहता है कि अगर मुंबई में इसके आयोजन में देरी या परेशानी हो तो क्या आईओसी सत्र 2023 का आयोजन दिल्ली में किया जा सकता है। बत्रा ने इसके साथ ही आईओसी को सूचित किया कि आईओए ने आईओसी सत्र 2023 के आयोजन के लिए औद्योगिक घराने के साथ प्रायोजन करार को अंतिम रूप देने और उस पर हस्ताक्षर करने के लिए पांच सदस्ईय समिति गठित की है जिसमे अनिल खन्ना, सुधांशु मित्तल, आदिल सुमरिवाला, आनंदेश्वर पांडे और आर के सचेती शामिल है।

कपास के खेतों में काम करने वाली लड़की ने क्रास कंट्री के लिए किया क्वालीफाई

भाषा। औरंगाबाद (महाराष्ट्र)। कपास के खेतो में काम करने वाली 15 साल की लड़की ने राष्ट्रीय क्रास कंट्री चैम्पियनशिप के लिए क्वालीफाई किया है जिसका आयोजन स्कूल खेल महासंघ अगले महीने पंजाब में करेगा। औरंगाबाद जिले की बाबुलगांव बुदरुक गांव की गायत्री सुखदेव गायकवाड़ के लिए स्कूल जाने के अलावा खेतो से कपास चुनना दिनचर्या में शामिल है। उन्होने हाल ही में पश्चिमी महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित राज्यस्तर की क्रास कंट्री में जीत दर्ज कर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया। उनके कोच और शिक्षक सतीश पाटिल ने कहा, गायत्री का घुटना चोटिल था जिसके बावजूद उसने हाल में सतारा में आयोजित दौड़ को जीतकर पंजाब में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया।
उन्होने बताया, गायत्री इसके लिए बालेवाड़ी खेल परिसर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर में भी भाग लेगी।

PUBLIC NOTICE
To be known to all that my client Birju Natraj S/o Shri H.K. Gaur, R/o SFS Flat No. 319, IInd floor Mukherjee Nagar, Delhi, vide File No. F131(13)95/SFS/MN. The original Possession Letter, Site Possession Letter, JE Letter and others has been lost/misplaced. An F.I.R. to this effect has been lodged in the Police Station, Crime Branch, Delhi vide LR No.1925876/2019 dated 25.11.2019. Any person(s) claiming any right, documents, may writer contact with above address/ Phone No. 9868232211 within 15 days from the date of publication of this notice. The person(s) claiming any right, interest, objection within respect of this property, can personally inform or write to Deputy Director (SFS)(H) Vikas Sadan, INA Colony, Delhi-110023
S.P. Singh, Advocate
Ch. Central Circular Wing, Tis Hazari, Delhi

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड की निगाहें अजेय क्रम बरकरार रखने पर

भाषा। गुवाहाटी

नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी बुधवार को यहां इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में मुंबई सिटी एफसी के खिलाफ होने वाले हीरो इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) के छठे सत्र के मैच जीत दर्ज करके अंकतालिका में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहेगी। नॉर्थईस्ट यूनाइटेड उन तीन टीमों में शामिल है, जिसे इस सत्र में अब तक एक भी हार का सामना नहीं करना पड़ा है। कोच रोबर्ट जार्नी की टीम चार मैचों में दो जीत और दो ड्रॉ के साथ आठ अंक लेकर अंकतालिका में चौथे पयदान पर है। जार्नी अपने स्टार खिलाड़ी रेडीम लांग के फॉर्म से काफी खुश होंगे, जो इस सत्र में अब तक दो गोल दाग चुके हैं। डिफेंडर काई हीरिंग्स का लीग से सस्पेंड होना हालांकि कोच के लिए जरूर चिंता की बात है। टीम के सहायक कोच खालीद जमील का कहना है कि नॉर्थईस्ट की टीम मुंबई सिटी के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ खेलेगी। जमील ने कहा, मुंबई के खिलाफ तीन अंक काफी महत्वपूर्ण है। हमारी टीम में कोई चोटिल नहीं है, लेकिन टीम को हीरिंग्स की कमी खलेगी। हम उसी तरह से खेलेंगे, जैसा कि आमतौर पर खेलते हैं। हमें एक अच्छी टीम के खिलाफ खेलना है, इसलिए उन्हें हल्के में नहीं ले सकते हैं। दूसरी तरफ मुंबई सिटी की टीम अपने अधिकतर चोटिल खिलाड़ियों के वापस टीम में लौटने से काफी खुश होगी। इनमें रॉवलिन बोर्जेस, मोदौ सौगु और माटो जर्जिक ऐसे खिलाड़ी हैं, जो टीम में वापस आ चुके हैं। इन खिलाड़ियों की वापसी से कोच जॉर्ज कोस्टा को काफी राहत मिलेगी। लगातार दो जीत के साथ सत्र को शानदार तरीके से शुरू करने वाली मुंबई सिटी को अगले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा। टीम चार मैचों के बाद इस समय अंकतालिका में आठवें नंबर पर है। मुंबई सिटी के पिछले सत्र में भी चार मैचों में इतने ही अंक थे, लेकिन इसके बाद टीम नौ मैचों में अपराजित रही थी और कोस्टा चाहेंगे कि टीम इस बार भी वैसा ही करे। हमने ठीक पिछले सत्र जैसी शुरूआत की। पिछले सत्र में भी चार मैचों के बाद हमारे चार अंक थे। हमने अच्छी शुरूआत की थी और फिर कुछ समस्याएं थी। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा विश्वास है। उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मैच और हमें तीन अंक हासिल करना है।

आडवाणी, सेठी अखिल भारतीय ओपन बिलियर्ड्स के सेमीफाइनल में

लखनऊ । दिग्गज क्यू खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने मंगलवार को यहां अखिल भारतीय ओपन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। तेइस बार के विश्व बिलियर्ड्स और स्नूकर चैंपियन आडवाणी ने दो घंटे चले नाकआउट मुकाबले में उत्तर प्रदेश के अक्षय कुमार को आसानी से 1351-210 से हराया। बेंगलुरु के क्यू खिलाड़ी आडवाणी ने 296, 199, 177 और 109 के ब्रेक के साथ आसानी से अंक जुटाए। ड्रा के दूसरे हाफ में आठ बार के विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन गुजरात के गीत सेठी ने नलिन पटेल के खिलाफ आसान जीत दर्ज की। यह ओपन बिलियर्ड्स टूर्नामेंट है जिसका आयोजन अगले साल होने वाली राष्ट्रीय चैंपियनशिप से पहले किया गया है लेकिन ए दोनो दिग्गज खिलाड़ी आमंत्रण पर यहां खेल रहे है।

स्पोर्ट्स कालेज ने सब जूनियर हाकी जीती

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

जैद खान के तीन गोलों की मदद से स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ ने स्पोर्ट्स हास्टल सैफई को 7-3 गोलों से हराकर राज्य स्तरीय सबजूनियर बालक हाकी प्रतियोगिता जीत ली है। मो. शाहिद हाकी स्टेडियम में खेले गए खिताबी मुकाबले में स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ ने स्पोर्ट्स हास्टल सैफई खेल के हर क्षेत्र में पछाड़ा। जैद खान ने खेल के 19वें मिनट में पहला गोल किया। इसके बाद उसने 47वें और 60वें मिनट में दो और गोल किए। इसके अलावा राहुल राजभर ने खेल के 57वें और 60वें मिनट में दो गोल किए। वहीं सूरजपाल ने 28वें और राजन गुप्ता ने 59वें मिनट में एक-एक गोल किए। दूसरी तरफ से कप्तान सुजीत कुमार ने खेल के 26वें मिनट में एक गोल करके स्पोर्ट्स हास्टल सैफई को 1-1 से बराबरी पर ला दिया, लेकिन उनका यह प्रयास नाकाफी साबित हुआ। स्पोर्ट्स हास्टल सैफई के नागेन्द्र कुमार ने 32वें और सिद्धांत सिंह ने 55वें मिनट में एक-एक गोल किए। मुख्य अतिथि राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती ने पुरस्कार बांटे। इस अवसर पर सैयद अली, सुजीत कुमार, देवेन्द्र ध्यानचन्द्र, मुकुल शाह, निशा मिश्रा, अविनाश श्रीवास्तव, बीके वाजपेयी, आदि मौजूद रहे।

सेंट जोसेफ फाइनल में

लखनऊ। सेंट जोसेफ स्कूल ने कर्नल एसएन मिश्रा इलेवन को नौ विकेट से हराकर कर्नल एसएन मिश्रा स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। एनआर स्टेडियम में खेले गए सेमीफाइनल में कर्नल एसएन मिश्रा इलेवन ने पहले बैटिंग करके 17.2 ओवर में 70 रन बनाए। रीशू ने 24 और रीतेश ने 16 रन का योगदान दिया। यश गोस्वामी ने तीन, अंकित सिंह और आकाश यादव ने दो-दो विकेट लिए। जवाब में सेंट जोसेफ स्कूल ने 10.2 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 73 रन बनाकर नौ विकेट से मैच जीत लिया। रितिक ने नाबाद 32 और अखिलेश दास ने 18 रन बनाए। लवकेश को एक विकेट मिला।

संदीप की उम्दा गेंदबाजी, अखिल इंफ्रा जीता

लखनऊ। संदीप यादव की उम्दा गेंदबाजी के सहारे अखिल इंफ्रा ने अखिलेश दास टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट (ए डिवीजन)में यूपी टिम्बर को पांच रन से हराया। अखिलेश दास स्टेडियम में अखिल इंफ्रा ने पहले बैटिंग करके 20 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 135 रन बनाए। अमित चोपड़ा ने 53 गेंदों में छह चौके और पांच चौके की सहायता से नाबाद 78 रन बनाए। इसके अलावा सूफियान खान ने नाबाद 22 रन का योगदान दिया। प्रिंस मौर्या ने तीन और हसन अख्तर ने दो विकेट लिए। जवाब में यूपी टिम्बर की टीम 19.2 ओवर में 130 रन बनाकर आल आउट हो गयी। विश्वजीत मिश्रा ने 25, शुभंग राज ने 21, विपराज निगम ने 17 और करन सिंह ने 17 रन का योगदान दिया। संदीप यादव ने 16 रन देकर चार और नवनीत यादव ने तीन विकेट चटकाए।

आईजीएसएस क्रिकेट: सेंट फेडलिस व एसआर ग्लोबल विजयी

लखनऊ। मैन आफ द मैच अथर्व के अर्धशतक की मदद के सहारे सेंट फेडलिस स्कूल ने आईजीएसएस क्रि केट ट्राफी में एलपीएस को 15 रन से मात दी। आईआईएसई कैम्पस कल्याणपुर में खेले गए मैच में सेंट फेडलिस ने पहले बल्लेबाजी करके अथर्व के 60 व साद 27 रनों की सहायता से 20 ओवर में तीन विकेट पर 136 रन बनाए। एलपीएस के वैभव ने तीन विकेट चटकाए। जवाब में एलपीएस निर्धारित ओवर में नौ विकेट गंवाकर 121 रन ही बना सकी। शुभम ने 27 व वैभव ने 17 रन का योगदान दिया। सेंट फेडलिस के प्रियांशु ने तीन जबकि सार्थक व अक्षत ने दो-दो विकेट चटकाए। दूसरे मैच में एसआर ग्लोबल ने अवध अकादमी को 108 रनों से हराया।

अंकित व मंजू रानी जीते

लखनऊ। अटल बिहारी स्टेडियम में आयोजित द रन मैराथन में पुरुष वर्ग में अंकित कुमार और महिलाओं में मंजू रानी ने पहला स्थान हासिल किया। अंकित कुमार ने 42.195 किमी. की दूसरी दो घंटा 12.13 मिनट में पूरी की। वहीं मंजू रानी ने यह दौड़ तीन घंटा 37.32 मिनट में पूरी की। वहीं 21.97 किमी. की हाफ मैराथन में दीप नारायण ने एक घंटा 12 मिनट का समय निकाला। महिला वर्ग में खुशबू गुप्ता ने एक घंटा 28.43 मिनट का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया। इसके अलावा 10 किमी. रेस में श्रवण कुमार, डिम्पल सिंह, पांच किमी. रेस में नरेश और शिखा गुप्ता विजयी रहे। इससे पूर्व द रन का शुभारम्भ पांच बार आयरन मैन रहे ब्रांड अम्बेसडर सत्यम सहाय ने किया। इस मौके पर राजेन्द्र सिंह, एडिशनल डायरेक्टर जनरल (विजीलेंस) कस्टम इनडाइरेक्ट टैक्सेज, ललिता पांडेय डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन, सुरभि सहाय एमडी क्लेट पॉसिबल आदि मौजूद थे।

मेरा Raipur SMART CITY
OFFICE OF THE RAIPUR SMART CITY LIMITED
e-Procurement Tender Notice, Main Portal: http://eproc.cgstate.gov.in
Online bids are invited for the following of works up to16/12/2019 at 17:30 hours

Sytem Tender No	NIT NO.	Name of work/Description of Work	Tender amount	EMD Amount	Time period
58986	209/RSCL/2019 RAIPUR DATED 25/11/2019	Purification & Restroration of Amlidih Apna Talab in Raipur(C.G.) including Operation & Maintenance of 3years	₹ 54.40 Lakhs	₹ 54,400	36 months O&M period including 36 months DLP
58987	210/RSCL/2019 RAIPUR DATED 25/11/2019	Purification & Restroration of Bada Khamardih Talab in Raipur (C.G.) including Operation & Maintenance of 3 Years	₹ 55.00 Lakhs	₹ 55,000	36 months O&M period including 36 months DLP
58988	211/RSCL/2019 RAIPUR DATED 25/11/2019	Purification & Restroration of Karbala Talab in Raipur (C.G.) including Operation & Maintenance of 3 Years	₹ 70.00 Lakhs	₹ 70,000	36 months O&M period including 36 months DLP

NOTE :- 1. All the detailed information related to above bids can be viewed on https://eproc.cgstate.gov.in
MANAGING DIRECTOR
RAIPUR SMART CITY LIMITED RAIPUR, (C.G.)

सांकेतिक कब्जे की सूचना
ICICI Bank
शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक द्वितीय तल, वीडियोकॉन टॉवर, झंडेवालान एक्स., नई दिल्ली- 110055
जबकि
अधोहस्ताक्षरी ने वित्तिय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतरर्गत आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रुप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं निर्गमित की थी जिसमें उक्त सूचना के प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर सूचना में वर्णित राशि को प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
कर्जदार/सह-कर्जदार/जमानतदार राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे है अतएव एतद् द्वारा कर्जदार तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षर दाता द्वारा सांकेतिक अधिग्रहण किया गया है जो कि उक्त अधिनियम धारा 13(4) के तहत नियम 8 में दर्शाया गया है। संपत्ति तथा अधिग्रहण की तिथि नीचे दर्शाई गई है एतद् द्वारा विशेष रुप से कर्जदार एवं जनसाधारण को सम्पत्ति के संव्यवहार नहीं करने के लिए सचेत किया जाता है तथा सम्पत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार इसमें वर्णित राशि तथा उस पर आगे ब्याज हेतु आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

| क्र. | कर्जदार/ सह-कर्जदार का नाम/ खाता क्र. | सम्पति का विवरण/ सांकेतिक कब्जे की तिथि | डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.) | श

प्रख्यात कार्टूनिस्ट सुधीर धर का निधन

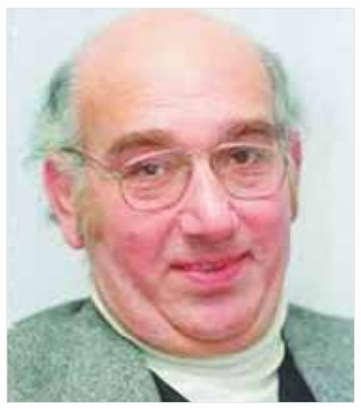

नई दिल्ली। प्रख्यात कार्टूनिस्ट सुधीर धर का मंगलवार की सुबह दिल का दौरा पड़ने के बाद निधन हो गया। धर 87 साल के थे। उनके परिवार के सदस्यों ने उनके निधन की जानकारी दी। अपने 58 साल के करियर में कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में कार्टून के जरिए समसामयिक मुद्दों पर व्यंग्य करने वाले धर ने 1961 में द स्टेट्समैन से शुरूआत की और बाद में वह हिंदुस्तान टाइम्स से जुड़ गए। उनके बनाए कार्टून द इंडिपेन्डेन्ट , द पायनियर , डेह्ली टाइम्स , न्यूयार्क टाइम्स , वाशिंगटन पोस्ट और सैटरडे रिव्यू सहित कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए तथा लोगों ने उन्हें बेहद पसंद किया।

इशिता गांगुली को मिली पहली हॉरर फिल्म

मुंबई। अभिनेत्री इशिता गांगुली हॉरर फिल्म 'कर्मा' से ओटीटी की दुनिया में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। इशिता ने कहा,'कर्मा' मेरी पहली हॉरर और थ्रिलर फिल्म है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगी। मेरे किरदार का नाम शिवा है, जो एक हाउसवाइफ है। अतीत की कुछ घटनाओं के कारण उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। यह आम भूत प्रेत वाली फिल्म नहीं है, जिसमें आपको भूत प्रेत दिखाई देंगे। इशिता ने 'शास्त्री सिस्टर्स', 'लाल इश्क' और 'जग जननी मां वैष्णो देवी' जैसे टीवी शो में काम किया है।

भारत में कहीं भी न हो बाल विवाहः ताहिरा

नई दिल्ली। लेखिका-फिल्मकार ताहिरा कश्यप खुराना का कहना है कि वह भारत को बाल-विवाह के अभिशाप से मुक्त करना चाहती हैं। यह दुर्भाग्य है कि भारत में कम उम्र की दुल्हनों की संख्या सबसे अधिक है। टाइम्स स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन लिमिटेड और वर्ल्ड वी वांट द्वारा नई दिल्ली में इस महीने की शुरुआत में आयोजित एसडीजी सम्मेलन में आने के दौरान ताहिरा ने अपने मन की बात कही। इस दौरान ताहिरा ने अपने बचपन की एक घटना का जिक्र किया, तब वह जालंधर (पंजाब) में रहती थीं। उनकी दोस्त की शादी 14 वर्ष की उम्र में हो गई थी और उसने 15 साल की उम्र में पहले बच्चे को जन्म दिया था। ताहिरा ने कहा, इस बात ने मेरे जीवन को झकझोर कर रख दिया था। मैं तब छठी की छात्रा थी और हर दिन अपना पेशा बदलते रहती थी कि मुझे भविष्य में क्या बनना है, और तब मेरी दोस्त को ऐसा कुछ करने का मौका तक नहीं मिला। यहां तक कि उससे न सिर्फ उसका बचपन छीन लिया गया, बल्कि उसके सपने भी तोड़ दिए गए।

'अब कोई अभिनेता चुनौतीपूर्ण रोल करने से पीछे नहीं हटता'

बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम कर चुके अभिनेता **गजराज राव** ने 90 के दशक में फिल्मी दुनिया में पदार्पण किया था। लेकिन हाल ही में आई फिल्म 'बधाई हो' के माध्यम से वो चर्चा में आए और अब 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' के माध्यम से वो लोगों के सामने आने की प्रतीक्षा में हैं। अपने कॅरियर और उसमें मिलने वाले अवसरों को लेकर उनसे विस्तार में बात की पायनियर संवाददाता **शालिनी सक्सेना** ने। प्रस्तुत हैं प्रमुख अंश-

■ फिल्म 'मेड इन चाइना' में काम करने का आपका अनुभव कैसा रहा?

- जिन लोगों ने फिल्म देखी है कहते हैं कि मेरा उसमें कोई महत्वपूर्ण रोल नहीं है। लेकिन मैं फिल्म के लेखक और निर्देशक मिखिल मुसाले द्वारा सुनाई गई फिल्म की कहानी और उसमें अपने रोल को सुनकर ही उसमें शामिल होने पर सहमत हुआ था। फिल्म को लेकर जिस प्रकार की धुन उनके भीतर देखी थी वो देखकर मुझे फिल्म की सफलता पर पूरा विश्वास हो गया था। राजकुमार राव और सुमीत व्यास के साथ काम करके मुझे अद्भुत अनुभव हुआ।

■ किन अन्य कारणों से आप फिल्म की टीम का हिस्सा बनने पर सहमत हुए?

- इसके कई कारण थे। एक तो जिस तरह से मिखिल ने फिल्म की संकल्पना तथा कहानी सुनाई उससे मैं अत्यधिक उत्साहित हो गया। इसके अलावा मैं फिल्म के निर्माता दिनेष विजन और पूजा बिज़न का भी बहुत सम्मान करता हूं और वे भी मेरे फिल्म की टीम ज्वाइन करने का एक कारण रहे। मैं काफी समय से उनके साथ काम करने के अवसर तलाश रहा था और जब ये मिला तो मैंने तुरंत इसे लपक लिया।

■ क्या इसमें 'बधाई हो' से पूर्व या पश्चात जैसे किसी तत्व की भी उपस्थिति है?

मैं कई एडफिल्म तथा अभिनय जैसे काम मुंबई में रहते हुए पिछले 20-25 सालों से करता चला आ रहा हूं। लेकिन फिल्म की रिलीज़ के बाद जिस तरह से मेरे काम की सराहना हुई वो मेरे लिए आश्चर्य से कम नहीं था। दर्शकों तथा फिल्म बिरादरी से भी मुझे अपने काम के लिए काफी सराहना मिली थी। ऐसा अवसर हर अभिनेता को अपने जीवनकाल में एक बार अवश्य मिलना चाहिये।

■ आपके अनुसार फिल्म इतनी हिट किस कारण से साबित हुई?

- हर कलाकारर के साथ दस साल की अवधि में एक चरण आता है। एक समय था जब देवानंद या राजकपूर टाइप फिल्में ही सफल हुआ करती थीं। इसके बाद राजेन्द्र कुमार, मनोज कुमार की फिल्में आईं। उसके बाद धर्मेन्द्र, अमिताभ बच्चन, मिथुन तथा गोविंदा जैसे अभिनेताओं का दौर आया। फिर यष चोपड़ा ने मैदान संभाल लिया। लेकिन वर्तमान दौर नया और कई अर्थों में अलग है। आज लोग एक ही पृष्ठभूमि तथा एक ही तरह की कहानी वाली फिल्मों से ऊबने लगे हैं। यही कारण है कि करण जौहर ने खुद को नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। अब वो कभी खुशी कभी गम जैसी फिल्में न बनाकर स्टूडेंट ऑफद ईयर, कलंक और कपूर एंड सन्स जैसी फिल्में बना रहे हैं। लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म के आगमन के बाद अब दर्षक घर में बैठकर दुनिया भर की कंटेंट का अवलोकन कर सकते हैं। आजकल निर्माताओं के समक्ष चुनौतियों में वृद्धि हुई है। अब निर्माता लोग भी नई कंटेंट की तलाष कर रहे हैं। बधाई हो के साथ अच्छी बता ये रही कि ये सेट पैटर्न की कामर्शियल फॉर्मूला फिल्म नहीं थी। इसकी सेटिंग पूरी तरह से अलग थी। इसमें आयुष्मान खुराना और सान्या की कहानी के समानांतर नीनाजी और मेरी कहानी भी चल रही थी।

■ क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से अभिनेताओं को अपने भीतर परिवर्तन करना पड़ रहा है?

- जी हां, सभी तरह के सिनेमा के अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों के लिए ये स्वर्णिम युग कहा जा सकता है। आज तापसी पन्नू तथा नीना जी जैसी अभिनेत्रियों के लिए भी उचित स्थान है। अभिनेताओं के अलावा तकनीशियनों, सिनेमॉटोग्राफर तथा पटकथा लेखकों के लिए भी आज काम की कमी नहीं है। प्रत्येक के पास चुनने के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं। अब केवल आपके पास चलकर आने वाले काम के अलावा भी बहुत कुछ है। विकल्पों की आज कोई कमी नहीं है।

■ क्या आप भी मानते हैं कि आजकल फिल्मी उद्योग में सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं?

- जी हां, फिल्म निर्माण के संदर्भ में आज एक सकारात्मक युग चल रहा है। आज हिंदी के अतिरिक्त बंगाली, मराठी और मल्यालम सहित असमी भाषा का सिनेमा भी आगे बढ़ रहा है। सभी को कुंबलांगी नाइट्स जैसी श्रेष्ठ फिल्म देखनी चाहिये। आज हर क्षेत्रीय उद्योग फलफूल रहा है। हर प्रकार के सिनेमा का अच्छा समय चल रहा है।

■ क्या आप स्वयं को बड़े परदे का बड़ा स्टार मानते हैं?

- नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये भी सच है कि मुझे आजकल कई स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं, लेकिन मैं सावधानीपूर्वक उनका चयन करता हूं। मैं मुझे मिलने वाल सभी परियोजनाओं को हरी झंडी नहीं दिखाता। अभी तो मैं केवल 'शुभ मंगल ज्यादा सावधान' और 'मैदान' में ही काम कर रहा हूं।

■ तो क्या आप भी चेकलिस्ट के आधार पर परख कर ही रोल के लिए सहमत होते हैं?

- मेरे लिए केवल वेतन ही सबकुछ नहीं है। मैं देखता हूं कि मैं कैसे लोगों के साथ काम कर रहा हूं, कि कौन इसका निर्माण कर रहा है, सहकलाकार कौन कौन हैं, निर्देशक और लेखक कौन हैं? मैं देखता हूं कि इसकी स्क्रिप्ट कैसी है। ये भी देखना पड़ता है कि निर्माता अपनी टीम की कितनी देखभाल करते हैं। फिल्म रिलीज़ हो पाएगी या नहीं। किसी भी फिल्म के हिट होने का कोई फार्मूला नहीं होता। मेरे लिए तो मेरी यात्रा ही महत्वपूर्ण है।

■ क्या बॉलिवुड में आज भी अभिनेता की एक निष्चित छवि बन जाती है?

- नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल स्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया है। आप देखिये कि राजकुमार राव कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं आप आयुष्मान खुराना को ही देखिये, उनका प्रदर्षन उच्चकोटि का है आप विकी कौशल, दीपिका को ही देखिये कितना अच्छा कर रहे हैं। आप रणवीर सिंह को ही लीजिये। पद्मावत में उन्होंने कितना अच्छा अलग चरित्र निभाया था। आज से 20 साल पहले कोई अभिनेता ऐसा दुस्साहसपूर्ण चरित्र निभाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था, करने की तो बात जाने ही दीजिये। अब कोई भी अभिनेता चुनौतीपूर्ण रोल करने से पीछे नहीं हटता।

■ आपका एक एड प्रोडक्शन हाउस है। तो ऐसे में आपको कैमरे के सामने आने पर कैसा अनुभव होता है?

- वास्तव में देखा जाए तो मैं दोनों प्रकार के दायित्वों के निर्वाह का आनंद लेता हूं। जब मैं निर्देशन का काम करता हूं तो कई लोगों के सहयोग से काम करता हूं और कहानियों को दूसरों के सामने रखता हूं लेकिन जब मैं अभिनय कर रहा होता हूं तो मैं स्वयं ही किसी दूसरे के निर्देषन में कहानी को साकार कर रहा होता हूं।

■ थियेटर से लेकर फिल्मों तक की आपकी यात्रा कैसी रही है?

- मुझे किसी भी प्रकार का पछतावा नहीं है। मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 20-25 साल से काम कर रहा हूं। मैं बैंडिट क्वीन, ब्लैक फ्राइडे से लेकर तलवार और अब बधाई हो जैसी विविधतापूर्ण कहानियों वाली फिल्मों का हिस्सा रहा हूं। लेकिन फिल्म 'बधाई हो' के बाद से मेरे कॅरियर ग्राफ में अचानक से परिवर्तन आ गया है। अब मुझे जैसे एक नई पहचान मिल गई है। मैं अपने जीवन में अद्भुत व्यक्तित्व के धनी लोगों से मिला हूं और मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं कि ये अवसर मुझे मिले।

नवाजुद्दीन की 'मैक माफिया' को एमी 2019 में मिला सर्वश्रेष्ठ ड्रामा पुरस्कार

भाषा। न्यूयार्क

नवाजुद्दीन सिद्दीकी अभिनीत मैक माफिया को 47वें अंतरराष्ट्रीय एमी समारोह में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार दिया गया है।

पुरस्कार मिलने के तुरंत बाद अभिनेता ने सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया। नवाज ने मैक माफिया की टीम के साथ अपना चित्र ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, न्यूयार्क में अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार समारोह में मेरे पसंदीदा निर्देशक जेम्स वाटकिंस के साथ मैक माफिया में हमारे काम के लिए विजेता की ट्रॉफी मिलना अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है। मैं मैक माफिया की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। पैंतालीस वर्षीय अभिनेता ने मैक माफिया श्रृंखला में भारतीय व्यवसाई दिली महमूद का रोल अदा किया है।

'मैक माफिया' को बीबीसी ने बनाया था। यह एक नॉन फिक्शन बुक 'मैकमाफिया- अ जर्नी थ्रू द ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड' पर बनी है।

47वें इंटरनेशल अवॉर्ड्स में भारत में बनी वेब सीरीज और एक्टर्स को नॉमिनेशन मिला था। बावजूद इसके एक भी अवॉर्ड भारत के खाते में नहीं आया। हालांकि नवाजुद्दीन स्टारर मैक माफिया को बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया है, जिसका मुकाबला अनुराग कश्यप की वेबसीरीज सेक्रेड गेम्स से था। एमी अवॉर्ड्स में अनुराग कश्यप की वेबसीरीज सेक्रेड गेम्स बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में नॉमिनेटेड थी, लेकिन अवॉर्ड मैक माफिया ने जीता है। लस्ट स्टोरीज को बेस्ट टीवी मूवी/मिनी सीरीज कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अवॉर्ड सेफ हार्बर ने जीता है। राधिका आप्टे को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन अवॉर्ड ईटरनल विंटर की एक्ट्रेस मरीना गेरा ने जीता। इनके अलावा साधना सुब्रह्मणयम की विटनेस- इंडियाज फॉरबिडन लव भी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की कैटेगरी में नॉमिनेट की गई थी, लेकिन अवॉर्ड बेलिंगकैट- ट्रुथ इन ए पोस्ट ट्रुथ वर्ल्ड को मिला है।

'मैक माफिया' को बीबीसी ने बनाया था। यह एक नॉन फिक्शन बुक 'मैकमाफिया- अ जर्नी थ्रू द ग्लोबल क्रिमिनल अंडरवर्ल्ड' पर बनी है। इस किताब के राइटर मिशा ग्लेनी हैं। इस सेरेमनी के लिए नॉमिनेशन सितंबर 2019 में घोषित किए गए थे। जिनमें 11 कैटेगरीज में 21 देशों की एंट्रीज शामिल की गई थीं। इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स का आयोजन मैनहट्टन के द न्यूयॉर्क हिल्टन होटल में किया गया। भारत की ओर से करन जौहर, अनुराग कश्यप, कुब्रा सैत, साधना सुब्रह्मण्यम, राधिका आप्टे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अवॉर्ड नाइट में रेड कार्पेट पर पहुंचे थे।

सोमवार को हिल्टन होटल में 47वें अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स पर पहुंची राधिका आप्टे

स्टार, सुपरस्टार, मेगास्टार जैसे तमगों में यकीन नहीं

नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने 'सरफरोश', 'शूल' और 'मुन्नाभाई एमबीबीएस' जैसी फिल्मों में छोटे-मोटे किरदारों से अपने करियर की शुरुआत की थी. खुद को साबित करने और अपने मन-मुताबिक किरदार पाने के लिए उन्हें 12 साल संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा. यह अनुराग कश्यप की फिल्म 'गैंग्स ऑफ वासेपुर' थी, जिसने उनकी तकदीर बदलकर रख दी और तब से अब तक 'बदलापुर', 'रईस', 'रमन राघव 2.0', 'ठाकरे', 'मंटो' और 'सेक्रेड' जैसी कई परियोजनाओं में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया. आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कई प्रशंसक हैं, लेकिन इसके बावजूद वह खुद को 'स्टार' की श्रेणी में रखना नहीं पसंद करते हैं। उन्होंने बताया, मुझे खुद को स्टार कहना नापसंद है। मैं ऐसे तमगों में यकीन नहीं रखता हूं. स्टार, सुपरस्टार या मेगास्टार के रूप में पहचाने जाने के बाद इंडस्ट्री में कलाकारों को रूढ़बिद्ध किया जाता है और उन्हें एक ही जैसा काम करने को दिया जाता है। नवाजुद्दीन ने आगे कहा, 'सच्चा कलाकार वही होता है जो भिन्न किरदारों को निभाता है, लेकिन अगर आप स्टार श्रेणी में फंस जाते हैं, तो आप सीमाबद्ध होकर रह जाते हैं। 'स्टार' और 'सुपरस्टार' जैसी चीजें महज विपणन रणनीतियां हैं, इसलिए मुझे खुद को स्टार कहलवाना पसंद नहीं। नवाजुद्दीन का यह भी मानना है कि 'स्टार' का यह तमगा एक कलाकार के विकास को रोक देता है. उन्होंने इस बारे में कहा, 'मैं कम्फर्ट जोन में फंसकर नहीं रखना चाहता। एक कलाकार के लिए यह बेहद जरूरी है कि वह अपने कम्फर्ट जोन से परे जाकर कुछ करे।

इलियाना को थी अपनी बॉडी से प्रॉब्लम

मुंबई। अपने अंदाज से हमेशा दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री इलियाना डीक्रूज ने इस बात का खुलासा किया है कि उन्हें हमेशा से अपने शरीर को उसके वास्तविक रूप में स्वीकारने में परेशानी रही है। इसी के साथ 33 वर्षीय इस अभिनेत्री का कहना है कि फिलहाल वह खुश हैं और पहले से अब कहीं ज्यादा वह अपनी बॉडी को इज्जत करती हैं। एक साक्षात्कार में इलियाना ने बताया, मुझे अपनी बॉडी को उसके वास्तविक रूप में स्वीकारने में हमेशा से परेशानी रही है। अन्ततः मैं एक ऐसी स्थिति पर आ चुकी हूं, जहां मैं यह जैसा है इसे उसी रूप में पसंद करना सीख रही हूं। अब मैं अपने शरीर को पहले से कहीं ज्यादा इज्जत देने और इसका पर्याप्त देखभाल करने लगी हूं और मुझे लगता है कि यह दिख रहा है, तो मैं अभी खुश हूं।

> अब मैं अपने शरीर को पहले से कहीं ज्यादा इज्जत देने और इसका पर्याप्त देखभाल करने लगी हूं और मुझे लगता है कि यह दिख रहा है

लंबे समय बाद इलियाना फिर से मल्टीस्टारर फिल्म 'पागलपंती' के साथ बॉलीवुड में अपनी वापसी कर रही हैं, उन्होंने अपने प्रशंसकों संग डायट और फिटनेस से जुड़े कुछ टिप्स साझा किए हैं: 'एक वक्त ऐसा था जब मैं महीनों तक पागलों की तरह वर्कआउट किया करती थी। मेरा वजन कम हो जाता और मैं अच्छी दिखने लगती थी। इसके बाद मैंने इसे कुछ वक्त के लिए छोड़ दिया, तब मुझे एहसास हुआ कि अगर आप अपनी जीवनशैली को पूरी तरह से बदल देते हैं, तो इससे बदलाव आने लगते हैं।' उन्होंने आगे कहा, 'पहले मैं जिम में काफी ज्यादा वक्त गुजारा करती थी और खाने पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती थी फिर मुझे एहसास हुआ कि आप जैसा दिखते हैं उसका नब्बे प्रतिशत आप क्या खाते हैं उस पर निर्भर करता है, तो आपको अच्छा खाना खाने की जरूरत है। अगर संभव हो तो एक अच्छे न्यूट्रीशनिस्ट या पोषण विशेषज्ञ पर निवेश करें। अच्छा खाए, साफ खाए। मैं अब ज्यादा से ज्यादा ऐसा ही करने की कोशिश करती हूं। मैं अपने खाने को लेकर बेहद चौकस हूं और हर दिन मैं कितना मीठा ले रही हूं उस पर नजर रखती हूं। आने वाले समय में इलियाना 'द बिग बुल' में अभिषेक बच्चन के साथ नजर आने वाली हैं।

मैं लोगों के मजाक का आदी बन चुका हूं : अर्जुन कपूर

मुंबई। फिल्मकार आशुतोष गोवारीकर की महत्वाकांक्षी फिल्म 'पानीपत' का पोस्टर रिलीज होते ही इंटरनेट पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। जहां कुछ लोगों ने फिल्म के शानदार लुक की तारीफ की, वहीं इसे लेकर कई तरह के मीम्स भी बने, ट्रोलिंग भी की गई और खासतौर पर इसमें फिल्म के मुख्य कलाकार अर्जुन कपूर पर निशाना साधा गया। हालांकि अर्जुन का मानना है कि जिन ऐतिहासिक किरदारों और वीर योद्धाओं ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उन्हें लेकर मजाक बनाया जाना उचित नहीं है। यह फिल्म पानीपत की तीसरी लड़ाई पर आधारित है, जिसमें अर्जुन महान मराठा योद्धा सदाशिव राव भाऊ का किरदार निभा रहे हैं, जिन्होंने अफगानी शासक व हमलावर अहमद शाह अब्दाली संग लड़ाई की। फिल्म की रिलीज से पहले एक प्रोमोशनल इवेंट में जब उनसे इन मीम्स व ट्रोलिंग को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा, 'हर कोई ट्रोल हो जाता है। मुझे लगता है कि अब लोगों को नकारात्मक रहने और कड़वेपन की आदत हो गई है, शायद इसलिए क्योंकि वे अपनी निजी जिंदगी में इन्हीं चीजों का सामना कर रहे होते हैं। इससे उनकी परवरिश और वे जैसे हैं, वह साफ तौर पर झलकती है।